



लखनऊ, नई दिल्ली और रायपुर से प्रकाशित

प्रायोजक



वायनाड की त्रासदी
से अलग तरीके से
निपटना होगा
राष्ट्रीय-10

www.dailypioneer.com

कोचिंग सेंटर मौत मामले की सीबीआई करेगी जांच

दिल्ली हाईकोर्ट ने सौंपी, कहा-यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनता को इस पर संदेह न हो

पीटीआई। नई दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां राजेंद्र नगर में स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन विद्यार्थियों की डूबने से हुई मौत के मामले की जांच शुरू करने के लिए दिल्ली पुलिस से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी। उच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच को सीबीआई को यह सुनिश्चित करने के लिए सौंपी कि जनता को जांच पर कोई संदेह न हो।



कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडला की पीठ ने आपराधिक मामले में सीबीआई द्वारा की जाने वाली जांच की निगरानी के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीबीसी) को एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने को कहा। अदालत ने कहा, घटना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनता को जांच के संबंध में कोई संदेह न हो, यह अदालत मामले की जांच सीबीआई को सौंपती है। पीठ ने बेसमेंट में पानी भरने से तीन विद्यार्थियों की मौत के

मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा एक वाहन चालक को गिरफ्तार किए जाने पर कटाक्ष करते हुए कहा, गनीमत है कि आपने बेसमेंट में घुसने वाले बारिश के पानी का चालान नहीं काटा। वाहन (शेष पेज 9)

नीट-यूजी में शुचिता का उल्लंघन नहीं शीर्ष अदालत ने कहा, इसलिए परीक्षा रद्द नहीं की गई

राजेश कुमार। नई दिल्ली

पेपर के आरोपों और परीक्षा में अन्य अनियमितताओं पर बढ़ते विवाद के बावजूद वर्ष 2024 (नीट यूजी 2024) के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा स्नातक परीक्षा को रद्द नहीं करने का विस्तृत कारण बताते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कोई प्रणालीगत कमी नहीं थी। पेपर लीक केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था। शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया, इसलिए इस वर्ष की परीक्षा के संबंध में दोबारा परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। अपने 63 पन्नों के फैसले में, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि एनटीए को 'फिलप फ्लॉप' से बचना चाहिए, जो इस साल देखा गया क्योंकि यह छात्रों के हित में काम नहीं करता है। इसने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (स्नातक) आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में केंद्र द्वारा नियुक्त पैनल के दायरे का भी विस्तार किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि पैनल का दायरा बढ़ा



नीट से पहले चिकित्सा शिक्षा खुला व्यवसाय थी: नड्डा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

हाल ही में हुए नीट पेपर लीक विवाद के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने परीक्षा प्रणाली का बचाव करते हुए कहा कि नीट शुरू होने से पहले चिकित्सा शिक्षा एक खुला व्यवसाय बन गई थी और प्रत्येक पीजी सीटें 8 करोड़ रुपये से 13 करोड़ रुपये में बेची गईं। डीएमके के राज्यसभा सदस्य एम. मोहम्मद अब्दुल्ला के एक निजी सदस्य के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान चिंताओं



को संबोधित करते हुए, नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि चिकित्सा शिक्षा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से निपटने के (शेष पेज 9)

एयर इंडिया ने इजराइल की उड़ानें आठ तक स्थगित की पीटीआई। नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच एयर इंडिया ने शुक्रवार को तेल अवीव के लिए उड़ानें आठ अगस्त तक स्थगित करने की घोषणा की। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन राष्ट्रीय राजधानी से इजराइली शहर के लिए सप्ताह में पांच उड़ानें संचालित करती है।

एयरलाइन ने एक बयान में कहा, पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में मौजूदा स्थिति को देखते हुए, हमने तेल अवीव से आने-जाने वाली अपनी उड़ानों के निर्धारित संचालन को तत्काल प्रभाव से आठ अगस्त 2024 तक स्थगित कर दिया है। एयरलाइन ने यह भी कहा कि वह इस अवधि के दौरान तेल अवीव से आने-जाने के लिए टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को सहायता प्रदान कर रही है तथा यात्रा पुनर्निर्धारण और रद्दीकरण शुल्क पर एक बार की छूट दे रही है। एयर इंडिया ने वृहस्पतिवार को अपनी तेल अवीव की उड़ान रद्द कर दी थी। इजराइल और हमस सहित विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष के कारण पश्चिम एशिया में तनाव के हालात हैं। इस वर्ष की शुरूआत में भी, पश्चिम एशिया में तनाव के कारण एयर इंडिया ने अलग-अलग समय पर तेल अवीव के लिए उड़ानें कुछ समय के लिए स्थगित कर दी थीं।



आशा किरण में हुई मौतों की जांच के आदेश

एलजी ने मुख्य सचिव को सभी आश्रयगृहों पर श्वेत पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया

सौम्या शुक्ला। नई दिल्ली

राजस्व विभाग को मजिस्ट्रेट जांच शुरू करने और 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। आशा किरण 'मानसिक रूप से दिव्यांगों' के लिए दिल्ली सरकार द्वारा संचालित सुविधा है और इसके समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आती है। राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद विभाग फिलहाल बिना मुखिया के है। फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसी भी मंत्री को विभाग का प्रभार (शेष पेज 9)

केंद्र सरकार ने केरल के भूखलन प्रभावित वायनाड के 13 गांवों समेत छह रायों में फैले पश्चिमी घाट के 56,800 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) घोषित करने के लिए पांचवां मसौदा अधिसूचना जारी की है तथा 60 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। यह अधिसूचना 31 जुलाई को जारी की गई थी।

वायनाड के 13 गांवों समेत पश्चिम घाट के 56 हजार किमी के लिए मसौदा अधिसूचना जारी पीटीआई। नई दिल्ली

मसौदा अधिसूचना में केरल के 9,993.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील घोषित करने का प्रस्ताव है, जिसमें भूखलन प्रभावित जिले के दो तालुका के 13 गांव शामिल हैं। अधिसूचना में प्रस्तावित ईएसए में गुजरारत में 449 वर्ग किमी, महाराष्ट्र में 17,340 वर्ग किमी, गोवा में 1,461 वर्ग किमी, कर्नाटक में 20,668 वर्ग किमी, तमिलनाडु में 6,914 वर्ग किमी और केरल में 9,993.7 वर्ग किमी क्षेत्र शामिल हैं। मसौदा अधिसूचना में रेत खनन समेत सभी तरह की खनन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया गया है। इसमें कहा गया है कि मौजूदा खदानों को अंतिम अधिसूचना जारी होने की तारीख से पांच वर्षों के भीतर या मौजूदा खनन पट्टे को समाप्त कर, जो भी पहले हो चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया जाएगा।

दुश्मनों ने गला दबाकर जिंदा गाड़ा, कुत्तों ने बचाई जान



पायनियर समाचार सेवा। आगरा/नई दिल्ली

आगरा में तीस के आसपास की उम्र के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि भूमि विवाद के सिलसिले में चार लोगों ने उसे पीटा, गला घोंटा और जिंदा दफना दिया, लेकिन बाद में आगरा कुत्तों द्वारा जमीन खोदने के बाद चमत्कारिक रूप से वह बच गया। आगरा पुलिस ने कहा कि एक शिकायत के आधार पर चार लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 (हत्या का प्रयास), 115 (स्वेच्छ से चोट पहुंचाना) और 351 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पीड़ित रूप किशोर ने दावा किया कि 18 जुलाई को आगरा के अरटोनी इलाके में अंकित, गौरव, करण और आकाश नाम के चार लोगों ने उन पर हमला किया था। आरोपियों ने उसका भी गला घोंटा दिया और फिर उसे मरा समझकर अपने खेत में दफना दिया। किशोर ने

मुख्यमंत्री ने दुष्कर्म पीड़िता की मां को दिया भरोसा, बख्शे नहीं जाएंगे दरिंदे सीएम ने अयोध्या की बच्ची की मां से की मुलाकात

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/अयोध्या

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की दुष्कर्म पीड़िता बच्ची की मां को आश्वासन दिया है कि उन्हें न्याय दिलाए के लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। बच्ची के साथ दरिंदगी करने वालों को किसी भी सूत में बख्शा नहीं जाएगा उनपर कठोरतम कार्रवाई होगी। शुक्रवार को दुष्कर्म पीड़ित बच्ची की मां ने मुख्यमंत्री से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। सीएम से मिलने के बाद पीड़िता की मां ने मीडिया को बताया कि उनकी बच्ची के साथ दरिंदगी करने वालों के लिए उन्होंने सरकार से फांसी की सजा की मांग की है, इसपर मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि बच्ची को हर कीमत पर न्याय दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बच्ची की मां ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर भी आश्वासन दिया है कि आरोपित सपा नेता मोहन खान की संपत्तियों की जांच कराई जाएगी और अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा। मुख्यमंत्री आवास पर शुक्रवार को पीड़िता की मां से सीएम योगी की मुलाकात के दौरान बौकापुर के विधायक अमित सिंह चौहान भी मौजूद रहे। बता दें कि अयोध्या के पूरा कलंदर थानाक्षेत्र में घटी शर्मनाक



घटना में पिछड़ा वर्ग की 12 वर्षीय बच्ची के साथ सपा नेता मोहन खान और उसके नौकर पर दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप है। आरोपित मोहन खान फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी बताया जाता है। एक दिन पहले ही सीएम योगी ने विधानसभा में इस मामले पर बोलते हुए गहरी नाराजगी व्यक्त की थी। उन्होंने इस मामले में समाजवादी पार्टी की ओर से आरोपितों को लेकर सांप्टे कॉर्नर रखने के लिए सपा नेताओं की कड़े शब्दों में भर्त्सना की थी। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री को पीड़ित बच्ची की मां से मिलने के बाद अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बच्ची के स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंधन किये जाएं। सीएम योगी ने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य अनीता अग्रवाल (शेष पेज 9)

थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज सरपंच, आरोपी सपा नेता के जमीन-जायदाद को पैमाइश शुरू

लखनऊ/अयोध्या। गटरसा में हुए विनोद कोड के बाद लखनऊ में दुष्कर्म पीड़ित बच्ची की मां से मुलाकात करते के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कुछ ही घंटों के अंदर कार्रवाई शुरू हो गई है। सबसे पहले इस मामले में थानाध्यक्ष पुराकलंदर रतन शर्मा व गटरसा चौकी इंचार्ज अखिलेश गुप्ता को सरपंच कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जल्द ही और बड़े स्तर पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। नाबालिक बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पीड़िता की मां को सीएम योगी की ओर से मिले गयेसे के बाद शुक्रवार थाना एलडीएम सोहाबल आनंद कर्मियों के साथ आरोपी सपा नेता मोहन खान के घर पहुंचे। आरोपी सपा नेता की जमीनों की पैमाइश शुरू हो गई है।

52 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में दी आस्ट्रेलिया को मात

पीटीआई। पेरिस

कप्तान हरमनप्रीत सिंह के दो गोल और पी आर श्रीजेश की अद्भुत गोलकीपिंग के दम पर भारत ने 52 साल बाद ओलंपिक में आस्ट्रेलिया को हराते हुए आखिरी ग्रुप मैच में इस दिग्गज प्रतिद्वंद्वी पर 3-2 से जीत दर्ज की। भारत ने आखिरी बार पुरुष हॉकी में ओलंपिक में आस्ट्रेलिया को 1972 म्युनिख खेलों में हराया था। वहीं सिडनी ओलंपिक 2000 में आस्ट्रेलिया से 2-2 से ग्रुप मैच ड्रा रहा था। आस्ट्रेलिया ने तोक्वो ओलंपिक 2021 में ग्रुप मैच में भारत पर 7-1 से जीत दर्ज की थी।

तोक्वो ओलंपिक के आखिरी पदक विजेता भारत के लिए जहां श्रीजेश ने सही मायने में दीवार की तरह काम करते हुए असंख्य गोल बचाए तो हर मैच में गोल करते आए हरमनप्रीत ने उस सिलसिले को बरकरार रखा। वहीं पहली बार ओलंपिक खेल रहे डिफेंडर जर्मनप्रीत सिंह और फॉरवर्ड मुखिया के हैं। फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसी भी मंत्री को विभाग का प्रभार (शेष पेज 9)



पेरिस में ओलंपिक मैच के दौरान जीत दर्ज करने के बाद खुश दिख रहे भारतीय खिलाड़ी, दूसरी तरफ आस्ट्रेलिया के यानस केन बाएं से तीसरे तथा साथी खिलाड़ी जेक हार्वी के चेहरे साफ झलकी जा रही हैं।



के उन जख्मों पर महम जरूर लगा होगा जो दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल 2010 के फाइनल में 8-0 और बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल फाइनल में 7-0 से मिली हार के बाद मिले थे। इस मैच से पहले ओलंपिक में भारत ने

फाइनल, 1964 तोक्वो सेमीफाइनल और 1972 म्युनिख ग्रुप मैच) मैच जीते थे जबकि आस्ट्रेलिया ने छह जीते और दो ड्रां खेलें थे। भारतीय टीम पूल चरण में तीन जीत, एक ड्रा और एक हार के साथ बेल्जियम के बाद दूसरे स्थान पर रही और क्वार्टर फाइनल में उसका सामना पूल ए की तीसरे नंबर की टीम से होगा। भारतीय टीम ने पहले क्वार्टर से ही काफी आक्रामक खेल दिखाते हुए शुरूआती 15 मिनट में 2-0 की बढ़त बना ली। भारत को पांचवें मिनट में ही गोल करने का मौका मिला जब जर्मनप्रीत ने बाएं फ्लैंक से सुखजीत को गेंद सौंपी लेकिन वह उसे पकड़

नहीं पाए। आस्ट्रेलिया को 11वें मिनट में पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला जिस पर जेरेमी हेवर्ड का शॉट बाहर से निकल गया। इसके अगले मिनट भारत ने जवाबी हमला बोला और बेल्जियम के खिलाफ पिछले मैच में गोल करने वाले अभिषेक ने तूफानी शॉट पर गेंद सोधे गोल के भीतर डाल दी। आस्ट्रेलिया के गोलकीपर एंड्रयू चार्टर को समझने का समय ही नहीं मिला। भारत ने अगले मिनट पर मिले पेनल्टी कॉर्नर पर हरमनप्रीत के शानदार गोल से बढ़त दुगुनी कर ली। हरमनप्रीत का पेरिस ओलंपिक में यह पांचवां गोल था। पहले क्वार्टर में भारत 2-0 से (शेष पेज 9)

गांवों के ओपन जिम साकार करेंगे 'कैच देम यंग' का सपना

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

खेलों में भी उत्तर प्रदेश सिरमौर बने। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की मंशा है। इसके लिए सबसे प्रभावी फॉर्मूला है, 'कैच देम यंग'। मसलन बचपन से होनहार प्रतिभाओं को पहचानकर उनको उसी तरह की बुनियादी सुविधाएं, प्रशिक्षण और एक्सपोजर दिलाना। इसमें गांव गांव में खुलने वाले ओपन जिम की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसीलिए अनुपूरक बजट में भी सरकार में ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम खोलने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ओपन जिम में ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाएं निखरेगीं वहीं सरकार द्वारा संचालित खेलों इंडिया सेंटर और सभी सुविधाओं से आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज में इंटरनेशनल स्तर के कोच के प्रशिक्षण से इनको और निखारा जाएगा। सरकार एक जिला एक खेल (वन डिस्ट्रिक्ट,वन स्पोर्ट्स) पर भी गंभीरता से काम कर रही है।

अनुपूरक बजट में भी जिम के लिए किया गया 100 करोड़ का प्रावधान



उल्लेखनीय है कि हर जिले में कुछ खास खेल अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित होते हैं। संबंधित जिले में उन खेलों को खास प्रोत्साहन देने और उसी अनुसार बेहतरीन बुनियादी

सुविधाएं और प्रशिक्षण देने की भी योजना है। मेरठ में युद्ध स्तर पर बन रही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी योगी सरकार की खेल प्रतिभाओं को निखारने में मील का पत्थर बनेगी। सच तो यह

है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खेलों के प्रति निजी रुचि के कारण पिछले सात वर्षों में खेल जगत का पूरा परिदृश्य ही बदल गया है। आज प्रदेश में कानपुर, लखनऊ,

वाराणसी, गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम हैं। कानपुर और लखनऊ में तो लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच भी होते हैं। बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड) द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश का एकमात्र स्टेडियम होगा। कुछ दिनों तक गोरखपुर में भी इंटरनेशनल स्तर के क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की घोषणा मुख्यमंत्री कर चुके हैं।

युवा खिलाड़ी नामचीन खिलाड़ियों से प्रेरणा ले सकें इसलिए उनका भी सम्मान किया जा रहा है। हाकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यान चंद के नाम से बन रही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बाद मुख्यमंत्री ने अनुपूरक बजट में बाराबंकी स्थित पद्म श्री बाबू केडी सिंह के बाराबंकी स्थित पैतृक निवास को संग्रहालय घोषित करना भी एक ऐसा ही प्रयास है। इस बाबत सरकार ने अनुपूरक

बजट में 19.34 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। गोरखपुर के रामगढ़ झील में नौकायन प्रतियोगिता के लिए पूरी सुविधा मौजूद है। राष्ट्रीय स्तर की एक सफल प्रतियोगिता वहां हो भी चुकी है। खेला इंडिया के तहत उत्तर प्रदेश इंटर यूनिवर्सिटी गेम, नोएडा में मोटो जीपी के तहत पहली बार इंटरनेशनल बाइक रेस का आयोजन इस बात का सबूत है कि उत्तर प्रदेश में खेल संबंधी सुविधाओं के विस्तार के साथ यहां का पूरा परिदृश्य बदल चुका है। बदलाव की यह प्रक्रिया लगातार जारी है। इसके नतीजे भी दूरगामी और बहुआयामी होंगे।

मसलन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों से हास्पिटलटी और इससे संबंधित सेक्टरों को लाभ होगा। खेल सामग्री की मांग बढ़ने से संबंधित इंडस्ट्री को भी लाभ होगा। स्थानीय स्तर पर रोजी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। युवाओं में जीत का जन्मा और अनुशासन का बढ़ना बोनस होगा।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन



पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पवित्र श्रावण मास की शिवरात्रि के पावन अवसर पर शुक्रवार को काशी स्थित बाबा विश्वनाथ धाम में देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जी के ज्योतिर्लिंग का दर्शन-पूजन व जलाभिषेक किया व बाबा विश्वनाथ से समस्त देश व प्रदेशवासियों के सर्वकल्याण की प्रार्थना की। उन्होंने वाराणसी में काशी के कोजवाल बाबा काल भैरव के दर्शन व पूजन भी किया। उप मुख्यमंत्री मौर्य ने उसके बाद वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा से शिष्टाचार भेंट की और शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

एससी, एसटी व ओबीसी के प्रति कांग्रेस-बीजेपी का रवैया नही रहा सुधारवादी: मायावती

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

आरक्षण पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रतिक्रिया देते हुए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में सब कैटेगरी बनाने के फैसले का विरोध किया है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल पूछा है कि सरकार ने इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण पर गुरुवार को दिए फैसले में कहा था कि एससी-एसटी की सूची में सब कैटेगरी बनाने को लेकर कोई संवैधानिक रोक नहीं है। शुक्रवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि



सामाजिक उर्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उर्पीड़न कुछ भी नहीं। क्या देश के खासकर करोड़ों दिलतों और नुकसान की भरपाई के लिए योगी सरकार ने अब तक 150 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की गई है। यह धनराशि क्षतिग्रस्त फसलों को मुआवजा देने के लिए अंतर्गत की डिमांड पर जारी की गई है। वहीं अब तक सवा लाख से अधिक किसानों को उनकी क्षतिग्रस्त फसलों के लिए 71 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा दिया जा चुका है। इसमें सबसे अधिक लखौंपुर खीरी के 70 हजार से अधिक किसानों को 47 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। राहत आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी

बाढ़ से 1,57, 444 किसानों की फसलें हुई प्रभावित, पोर्टल पर डाटा किया गया फीड

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

अन्नदाता किसानों की आय में वृद्धि के साथ ही किसी आपदा में उन्हे होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी योगी सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश में बाढ़ की वजह से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए योगी सरकार ने अब तक 150 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की गई है। यह धनराशि क्षतिग्रस्त फसलों को मुआवजा देने के लिए अंतर्गत की डिमांड पर जारी की गई है। वहीं अब तक सवा लाख से अधिक किसानों को उनकी क्षतिग्रस्त फसलों के लिए 71 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा दिया जा चुका है। इसमें सबसे अधिक लखौंपुर खीरी के 70 हजार से अधिक किसानों को 47 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। राहत आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी

योगी सरकार बाढ़ प्रभावित इलाकों को जारी कर चुकी है अब तक 150 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि

आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के बाढ़ग्रस्त इलाकों में लगातार क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वे किया जा रहा है, ताकि किसानों को समय से मुआवजा दिया जा सके। उन्होंने बताया कि नेपाल और पहाड़ी क्षेत्रों से छोड़े गये पानी से प्रदेश के 18 जिलों की 82126.50 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई। वहीं सर्वे के दौरान वास्तविक क्षतिग्रस्त फसल 29,243.74 हेक्टेयर पायी गयी। बता दें कि सरकार की ओर से बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और बाढ़ से क्षतिग्रस्त 33 प्रतिशत से अधिक फसल के नुकसान पर ही मुआवजा दिया जाता है। राहत आयुक्त ने बताया कि बाढ़ से

1,57,444 किसानों की फसल प्रभावित हुई जबकि लेखापाल द्वारा अब तक 1,56,952 किसानों को सहायता धनराशि देने के लिए पोर्टल पर फीड किया जा चुका है। इसके सापेक्ष अब तक 1,25,521 किसानों को 71.01 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। वहीं बचे हुए किसानों की फीडिंग का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। सबसे अधिक लखौंपुर के 88546 किसानों की फसल बाढ़ से प्रभावित हुई है। इसके सापेक्ष भुगतान के लिए अब तक 88544 किसानों की फीडिंग पोर्टल पर की जा चुकी है। वहीं 70,691 किसानों को 47 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसी तरह सिद्धार्थनगर 19805 किसानों की फसल बाढ़ से प्रभावित हुई है। सभी किसानों की फीडिंग पोर्टल पर की जा चुकी है जबकि 15478 किसानों को 7.70 करोड़ का भुगतान किया जा चुकी है।

गरीबों की जमीनें छीनकर उन्हें बेघर करने का संयंत्र रच रही सरकार

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार गरीबों की जमीनों को छीनकर उन्हें बेघर करने का षडयंत्र रच रही है। भाजपा सरकार गरीब विरोधी है। समाजवादी पार्टी और समस्त विपक्ष के विरोध के बाद भी सत्ता के अहंकार में चूर भाजपा सरकार नजूल जमीन विधेयक बीजेपी के कुछ लोगों के फायदे के लिए लायी है। ये लोग अपने आसपास की गरीब जनता की जमीनें हड़पना चाहते हैं। सात साल से सरकार में



रहकर बजट की लूट करने के बाद भी सश्रम में बैठे लोगों का पेट नहीं भरा है। अब ये नया कानून बनाकर जमीनें लूटना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि नजूल लैंड का मामला पूरी तरह से 'घर उजाड़ने' का फंसला है क्योंकि बुलडोजर हर घर पर नहीं चल सकती है। भाजपा घर-परिवार वालों के खिलाफ है। जनता को दुख देने में भाजपा अपनी खुशी मानी है। जबसे भाजपा आई है, तब से जनता रोजी-रोटी-रोज़गार के लिए भटक रही है, और अब भाजपाई मकान भी छीनना चाहते हैं। कुछ लोगों के पास दो जगह का विकल्प है, पर हर एक उनके जैसा

नहीं है। बसे बसाये घर उजाड़कर भाजपा वालों को क्या मिलेगा। क्या भू-माफियाओं के लिए भाजपा जनता को बेघर कर देगी? अखिलेश यादव ने कहा कि अगर भाजपा को लगता है कि उनका ये फंसला सही है तो हम डंके की चोट पर कहते हैं, अगर हिम्मत है तो इसे पूरे देश में लागू करके दिखाएं क्योंकि नजूल लैंड केवल मुचों में ही नहीं पूरे देश में है। समाजवादी पार्टी की यही मांग है कि अमानवीय 'नजूल जमीन बिल' हमेशा के लिए वापस हो। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ये बिल अपने निजी फायदे के लिए लाकर गरीबों की जमीनें हड़पना चाहते हैं। इस बिल का जनहित और विकास से कोई वास्ता नहीं है। गोरखपुर में नजूल के अनन्त आने वाली बेशकौमती जमीनों पर सीएम की नज़र है। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी जी ने सोचा कि सत्ता का फायदा उठाकर उन जमीनों पर कब्जाकर लिया जाए। इसलिए ये बिल लाया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा

की पहले गोरखपुर, अयोध्या फिर लखनऊ और धीरे-धीरे पूरे यूपी की बेशकौमती नजूल भूमि पर कुदृष्टि है और गरीब जनता पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। ये जमीनें जनता से छीन कर बिल्डर्स, उद्योगपतियों को देने की साजिश है, चूकि लेकिन तमाम भाजपाई दिग्गजों की कोठियां, मकान, प्रतिष्ठान, बंगले भी नजूल में आ रहे हैं इसीलिए भाजपा के अंदर भी उसका विरोध हो रहा है। भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता के लिए मुसीबत बन गयी है। इसका सत्ता में रहना जनता के लिए हर दिन दुखदायी है। भाजपा सरकार प्रदेश की जनता को सुकून नहीं रहने देना चाहती है। भाजपा की गलत नीतियों से महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त जनता के सामने हर दिन भाजपा सरकार नए-नए संकट पैदा करने परेशानी में डाल रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के सफाये से ही जनता की परेशानियों और संकटों से निजात मिलेगी।

बीआरडी मेडिकल कॉलेज को आज 55 करोड़ रुपए की सौगात देंगे सीएम योगी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/गोरखपुर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज को 55 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों और सुविधाओं की सौगात देंगे। मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में दोपहर बाद 3.30 बजे से प्रस्तावित कार्यक्रम में सीएम योगी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ ही जनहित में विभिन्न नई सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे। लोकार्पण, शिलान्यास और सुविधाओं के शुभारंभ समारोह के मंच से मुख्यमंत्री स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण के तहत एमबीबीएस और पैरामेडिकल छात्रों को 483 टैबलेट-स्मार्टफोन का वितरण भी करेंगे।

बाबा राघव दास (बीआरडी) मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों जिन प्रमुख सुविधाओं का शुभारंभ होगा उनमें 7

करोड़ 17 लाख रुपये की लागत से सीटी स्कैन मशीन और 11.25 लाख रुपये की लागत वाली लिथोट्रिप्सी मशीन का लोकार्पण प्रमुख है। इसके अलावा सीएम जेनेटिक मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स आर्थोपेडिक्स ओपीडी तथा मिलक बैंक का भी शुभारंभ करेंगे। मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री द्वारा माइक्रोबायोलॉजी विभाग में सैमल कलेक्शन सेंटर की स्थापना, पैथालॉजी विभाग में फ्लू आटोमेटिक टिगु प्रोसेसर, फ्लू आटोमेटिक यूरिन एनालाइजर, 5 पॉट सिमेक्स सीबीसी एनालाइजर तथा न्यू एडवॉन्स टेक्नोलॉजी का हारमोनो ट्यूमर मैकर डिडक्शन की एलएनटी मशीन की स्थापना का शुभारंभ और आईएएससी पैपल के रेंज की वृद्धि कार्य का शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही वह फार्मसी कॉलेज के विस्तार निर्माण कार्य का लोकार्पण करेंगे। इस पर 8 करोड़ 5 लाख रुपये की लागत आई है।

यूपी में मनरेगा श्रमिकों के लिए सरकार का खुला खजाना

● केंद्र से 3600 करोड़ से भी ज्यादा धनराशि की गई जारी सामग्री मद मे भी मिले 1,100 करोड़

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि मनरेगा श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान शीघ्र ही किया जायेगा, उनके प्रयासों से भारत सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि उत्तर प्रदेश के लिए जारी की गयी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के मजदूरों और निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता एजेंसियों के लिए एक राहत भरी खबर है। इन लोगों के बकाये का अब बहुत जल्द ही भुगतान होगा। सरकार ने उत्तर प्रदेश मनरेगा के लिए अपना खजाना खोल दिया है। श्रमार्थ, सामग्री और प्रशासनिक मद की बात करें, तो केंद्र सरकार से करीब 3,667 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि जारी कर दी गई है। इसमें श्रमार्थ की बात करें, तो करीब 2,517 करोड़ रुपए जारी किये गये हैं, सामग्री मद में 1,100 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है, इसके अलावा प्रशासनिक मद हेतु भी करीब 50.41 करोड़ की धनराशि केंद्र ने जारी की है। जारी धनराशि से बकायेदारी भी दूर होगी। अब बहुत जल्द ही श्रमिकों और निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता एजेंसियों तक यह धनराशि पहुंचेगी। जारी धनराशि से जहां मजदूरों को उनका श्रमार्थ मिलेगा, वहीं

मनरेगा में निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता एजेंसियों को भी उनका बकाया भुगतान किया जा सकेगा। इस धनराशि के मिलने से मनरेगा कार्यों में भी तेजी आएगी। ऐसे में आपूर्तिकर्ता एजेंसियों के साथ-साथ मजदूर भी पूरी ऊर्जा के साथ मनरेगा कार्यों में अपना योगदान देंगे।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिकों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लगातार काम कर रही है। श्रमिकों की मजदूरी उनके खाते में समय से पहुंचे, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। मनरेगा के लिए जारी धनराशि के लिए केंद्र सरकार का भी श्रमिकों की ओर से आभार भी जताया है। आपको बताते चलें कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 26 करोड़ मानव दिवस सुजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष अब तक प्रदेश द्वारा 13.50 करोड़ से ज्यादा मानव दिवस सृजित कर लिया गये हैं।

ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने बताया कि मनरेगा योजना के लिए मांग के अनुरूप केंद्र द्वारा श्रमार्थ, सामग्री एवं प्रशासनिक मद हेतु करीब 3,667 करोड़, जिसमें श्रमार्थ करीब 2,517 करोड़, सामग्री मद में 1,100 करोड़, और प्रशासनिक मद हेतु भी करीब 50.41 करोड़ की धनराशि केंद्र ने जारी की है। जारी धनराशि से बकायेदारी भी दूर होगी। अब बहुत जल्द ही श्रमिकों और निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता एजेंसियों तक यह धनराशि पहुंचेगी। जारी धनराशि से जहां मजदूरों को उनका श्रमार्थ मिलेगा, वहीं

लगातार तीसरे दिन मेरठ व बागपत में शिवमठों पर हुई पुष्प वर्षा



पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/मेरठ/बागपत

योगी सरकार के निर्देश पर लगातार तीसरे दिन शुक्रवार को मेरठ और बागपत में कार्वाइयों पर पुष्प वर्षा की गई। गुरुवार को मेरठ में जहां डीएम और एसएसपी ने हेलीकॉप्टर से शिव भक्तों पर फूल बरसाए थे तो वहीं शुक्रवार को श्रावण शिवरात्रि के पावन अवसर पर मेरठ मंडल की मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे और आईजी नचिकेता झा ने मेरठ में बाबा औचड़ना मंदिर और बागपत में बाबू महादेव मंदिर में कार्वाइयों पर हेलिकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। दोनों अधिकारियों ने पुष्प वर्षा के साथ ही मंदिर परिसर का सर्वेक्षण भी किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होते देख कार्वाइये खुशी से झूम उठे और

बोल बम बोल बम के नारे लगाने लगे। इससे पूर्व गुरुवार को मेरठ के डीएम दीपक मीणा और एसएसपी विपिन ताड़ा ने भी मेरठ के ऐतिहासिक कैथेड्रल मंदिर, दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग, पल्लवपुरम, सिवाय टोल प्लाजा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की थी।

इंडियन बैंक Indian Bank	
दवावस्त आरित प्रबन्धन शाखा प्रथम तल, मुख्य शाखा भवन, हरवरगंज, लखनऊ-226001 फोन नं. 0522-2288988	
सार्वजनिक सूचना	
वित्तीय अतिरिक्त के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत वित्त प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(1) के अंतर्गत वित्त 10.08.2020, 13.01.2022 तथा 13.02.2024 को जारी विज्ञापन नोटिस एवं पत्र 13(4) के अंतर्गत वित्त 03.06.2023 को जारी कक्षा नोटिस को कुछ तकनीकी कारणों से वापस लिया जाता है। उपरोक्त नोटिस पत्र हटाने का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। वित्त नोटिस में विभिन्न नोटिस एवं कक्षा नोटिस को पुनः जारी करेंगे।	
दिनांक - 01.08.2024 स्थान - लखनऊ	प्राधिकृत अधिकारी इंडियन बैंक

Karnataka Bank Ltd.	
Your Family Bank. Across India.	
आर्य समाज वित्त निगम शाखा प्लॉट नं. 8-बी, प्रथम तल, राजेश पार्क, पुस्तक भवन, नई दिल्ली - 110060	फोन: 011-40591567 (एक्स. 240) ईमेल: delhi@kbnk.com वेबसाइट: www.karnatakabank.com सीआरएल: LBS110KA1924PLC001128

अचल सम्पत्ति की बिक्री सूचना
वित्तीय परिपंक्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-मौलामी बिक्री नोटिस, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटोर(ओं) को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/प्रसारित है, जिसका सांकेतिक कब्जा कर्नाटक बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, सुरक्षित लेनदार द्वारा 14.07.2021 को लिया गया है, उसके उधारकर्ता/गारंटर/सह-ओलिंगमेंट (1) श्रीमती पुष्पा गुप्ता पत्नी श्री मोला गुप्ता (2) मोला गुप्ता पुत्र श्री वेजनाथ गुप्ता (3) श्रीमती सोनम गुप्ता पत्नी श्री लाल गुप्ता (4) श्री गैला लाल गुप्ता पुत्र श्री मोला गुप्ता सभ (1), (2), (3) और (4) विवासी: एचए 2/261 पी, पांडेपुर वाराणसी - 221002 (उत्तर प्रदेश) से सुरक्षित लेनदार कर्नाटक बैंक लिमिटेड, वाराणसी-221001, उत्तर प्रदेश, की बकाया राशि रु. 19,32,381.16 (रु. उन्नीस लाख बत्तीस हजार तीन सौ इय्यासी और पैसे सोलह सारू) अर्थात पीएस 202 लोन खाता नं. 7997001800006061 के तहत दिनांक 02.08.2021 से मलिया के ब्याज के साथ, पत्तस तालत इत्यादि सहित की वस्तु है हेतु "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक 22.08.2024 को बेचा जाएगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण
रिहायशी सम्पत्ति का यह समस्त भाग एवं अंश जिसका क्षेत्रफल 63.25 वर्ग मी. एसएम प्लॉट नं. 103 में से, उस पर निर्माणित भवन, मौजूदा कोदोपूर, परगना, रामनगर, तहसील और जिला वाराणसी में स्थित, श्रीमती पुष्पा गुप्ता से संबंधित, घोड़ी: पूर्व में - ठाकुर प्रसाद का बगीचा परिचय नं - 610/ बीडा कच्चा रास्ता टी/ए जखर खान का मकान, उत्तर में - मुना और अन्य का मकान, दक्षिण में - शाहनवाबी और अन्य का मकान आरक्षित मूल्य/अंशक मूल्य जिसके नीचे संपत्ति नहीं बेची जा सकती: रु. 27,00,00,000/- (रु. सात्ताईस लाख मात्र)
जमा /निविदा की जाने वाली बतयाना राशि: रु. 7,20,000/- (रु. दो लाख सत्तर हजार मात्र)
(उधारकर्ता/बंधककर्ता का ब्याज अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के अंतर्गत और आनुकूल वित्त प्राप्त है, जो सुरक्षित परिपंक्तियों को सुदृढ़ करने के लिए उधारकर्ता के संबंध में है।)
(1) के तहत नोटिस के रूप में भी कार्य करेंगे।
12 की विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया कर्नाटक बैंक की वेबसाइट अर्थात www.karnatakabank.com में दिए गए लिंक पढ़ें। दिनांक 22.08.2024 को मेना ई-मौलामी के अंतर्गत ई-मौलामी 22.08.2024 को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक 05 मिनट के अंतर्गत विस्तार के साथ पोर्टल <https://bankauctons.in/> के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता को <https://bankauctons.in/> पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा और उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड निशुल्क प्राप्त करना होगा और ई-मौलामी (संभवतः 21.08.2024 को) नर्सरॉ 4 बजे तक, प्लॉट नं.102, प्लॉट नं. 20, अमृत अपार्टमेंट, मोतीनगर, हैदराबाद-500018 सर्वकर्म नं. 040-23836405, फोन. 08142000692 ई-मेल: info@bankauctons.in से ऑनलाइन पंजीकरण प्राप्त करना होगा।
दिनांक: 02.08.2024
स्थान: वाराणसी

कुचे कर्नाटक बैंक लि. मुख्य प्रबंधक और प्राधिकृत अधिकारी

सूचना

मै सैय्य चं -22050437L रैंक सिपाही नाम विद्युत विकास मोहन, मेरी माता का नाम गलती से मैरे सॉर्सि दस्तावेज में गलती से मामोनी मोहन है जबकि ठीक नाम मामी मोहन है।

सूचना

सूचना
मेरे मवन संख्या 443 E.W.S (D/S) भूतल योजना-नौबस्ता, कानपुर नगर का मूल आवंटन पत्र दिनांक 29/12/1988 व कब्जा प्रमाण पत्र एवं मवन संख्या 444 E.W.S ब्लॉक (D/S) प्रथम तल, योजना-नौबस्ता, कानपुर नगर मूल आवंटन पत्र खो गया है, जिसका किसी प्रकार से प्रयोग अथवा एवं शूच्य होगा। वर्तमान में उक्त दोनों मवन मेरे द्वारा श्री सुधीर कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद को विक्रय किये जा चुके हैं। पूर्व मकान मालिक -सुरेश चन्द्र गुप्ता पुत्र स्व. छोट लाल।

वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मास्टर प्लान तैयार

सरकार 10 सेक्टरों के जरिए साधेगी देश की सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले राज्य का लक्ष्य

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

अनुपूरक बजट के बाद प्रदेश को इस साल ऐतिहासिक साढ़े सात लाख करोड़ के बजट की सौगात देने के बाद अब योगी सरकार का लक्ष्य अगले चार कुछ साल में सूबे को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य के रूप में स्थापित करने का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए 'दस का दम' लगाने पर जोर देते हुए विस्तार से कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये हैं। एक दिन पहले ही सदन में प्रदेश के अनुपूरक बजट पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी के लिए 10 सेक्टर में कार्य किये जाने की चर्चा की थी। प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के बड़े लक्ष्य को साधने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन 10 सेक्टरों पर

विशेष जोर देने के निर्देश सभी अधिकारियों को पहले ही दे दिये हैं। बीते फरवरी माह में आयोजित हुए ग्रांडड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) के जरिए प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश धरातल पर उतरने से योगी का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है। प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए योगी सरकार ने पूरी ताकत झोंकते हुए 10 सेक्टरों को चिह्नित किया है। इसमें प्रदेश के आर्थिक विकास से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विभागों के बीच समन्वय कायम करते हुए कार्य करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं। जिन 10 सेक्टर पर मुख्यमंत्री ने सबसे अधिक फोकस करने के निर्देश दिये हैं उनमें कानून व्यवस्था, कृषि उत्पादन, सामाजिक सुरक्षा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास,

नगरीय विकास, ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन एवं संस्कृति और राजस्व संग्रह को लेकर अगले तीन साल तक मिशन मोड में कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। इन प्रत्येक सेक्टर की जिम्मेदारी एक-एक कैबिनेट मंत्री को दी गई है, जिन्हें अपर मुख्य सचिव स्तर के अनुभवी अधिकारी संभालेंगे। मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक सेक्टर के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार की जाए। साथ ही कार्ययोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं मॉनीटरिंग होगा। योगी सरकार अपना 7 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। बीते 7 वर्षों में प्रदेश के इन्फ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था, यातायात कनेक्टिविटी और रोजगार के मोर्चे पर उल्लेखनीय सफलता

हासिल करने वाली योगी सरकार ने अब आगामी तीन साल के लिए बड़े लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के विशाल लक्ष्य के लिए योगी सरकार के पास बड़ा आधार भी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उल्लेखनीय बढ़ोतरी के रूप में देखा जा सकता है, जो कि बीते वित्तीय वर्ष 2023-24 में 25.48 लाख करोड़ रुपए रहा है। जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह 22.58 लाख करोड़ रुपए था। वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 8 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। राज्य सरकार के विगत सात वर्षों के नियोजित प्रयासों के परिणामस्वरूप इसमें और वृद्धि की संभावना है। इसके अलावा देश में सबसे ऊर्वर भूमि, प्रचुर जल संसाधन, युवा आबादी, देश का

इन 10 सेक्टर पर है फोकस

कानून व्यवस्था, कृषि उत्पादन, सामाजिक सुरक्षा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, नगरीय विकास, ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन एवं संस्कृति, राजस्व संग्रह

सबसे बड़ा उपाधोदा और श्रम बाजार होने के साथ ही उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8 प्रतिशत का योगदान देता है। यही नहीं देश की कुल 12 प्रतिशत कृषि भूमि और खाद्यान्न उत्पादन में यूपी करीब 20 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने में एक अहम रोल निभाने जा रहा है।

गोमती नगर में अवैध रो-हाउस व आशियाना में निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स सील

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

एलडीए द्वारा गोमती नगर विस्तार व आशियाना क्षेत्र में कार्यवाही की गयी। काम्प्लेक्स पर विहित प्राधिकारी द्वारा नोटिस भेजकर सीलिंग की नोटिस दी गयी थी, लेकिन उदासनीता बरतने पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। आदेश पर एलडीए प्रवर्तन टीम द्वारा रो.हाउस भवनों व एक निर्माणाधीन व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को सील किया गया।

शुक्रवार को एलडीए ने गोमती नगर विस्तार में अवैध रो.हाउस व आशियाना में निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स सील किया। प्रवर्तन जोन.1 की जोनल अधिकारी वन्दना पाण्डेय ने बताया कि विपिन गर्ग व अन्य द्वारा गोमती नगर विस्तार के छोटा भरवारा में लगभग 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर अवैध रूप से रो.हाउस भवनों का निर्माण कराया जा रहा था। जिसके विरुद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के



आदेश पारित किये गये थे। इसके अनुपालन में सहायक अभियंता उदयवीर सिंह, अवर अभियंता आशीष श्रीवास्तव व उसके दीक्षित द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय

थाने के पुलिस बल के सहयोग से उक्त भवनों को सील कर दिया गया। प्रवर्तन जोन.2 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि अजय अहूजा गौतम अहूजा व अन्य द्वारा

बसंतकुंज में पीएम योजना के तहत बने आवासों की होगी जांच

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

एलडीए की ओर से बसंतकुंज में बनाए गए पीएम आवास की जांच होगी। इसके लिए एलडीए सचिव द्वारा पांच-पांच इंजीनियरों की दो टीमों बना दी गयी हैं। इनको मकानों की गुणवत्ताएँ अथुरे और मानक के विपरीत हुए कार्यों की जांच की जिम्मेदारी दी गई है।

वहीं, समिति को एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। टीमों को अथुरे कार्यों को एक सप्ताह में पूरा भी करवाना होगा। हरदोई रोड स्थित बसंतकुंज में पीएम आवास योजना के भवनों की जांच

पांच-पांच इंजीनियरों की दो टीमों गठित

के लिए एलडीए प्रशासन ने टीमों बनाने का निर्णय लिया है। एलडीए सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने हाल ही में पीएम आवास योजना के बसंतकुंज योजना का निरीक्षण किया था। उन्हें मकानों में तमाम खामियाँ मिली थीं। मानक के विपरीत और कुछ काम अधूरा भी मिला था। उन्होंने इसकी रिपोर्ट वीसी व सचिव को भी भेजी थी। वीसी के निर्देश पर अब सचिव विवेक कुमार श्रीवास्तव ने मकानों की जांच के लिए विशेषज्ञ इंजीनियरों की दो टीमों

कराये बिना किये जा रहे इस निर्माण कार्य के विरुद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश दिये गये थे। जिसके अनुपालन में शुक्रवार को सहायक अभियंता

अनिल कुमार, अवर अभियंता विपिन बिहारी राय व एसके सिंह द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से निर्माणाधीन बिल्डिंग को सील कर दिया गया।

विकास में तेजी के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों निवेश हों

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में केन्द्रीय बजट 2024-25 पर हुआ पैनल चर्चा का आयोजन

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

बासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में शुक्रवार को अर्थशास्त्र विभाग की ओर से केन्द्रीय बजट 2024-25 पर पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एन.एम.पी. वर्मा ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जोआईडीएस लखनऊ के पूर्व निदेशक प्रो. ए. के. सिंह उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त मंच पर आईसीसीएसआरटी, लखनऊ के पूर्व निदेशक प्रो. अजय प्रकाश, लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रो. मनोज अग्रवाल, अर्थशास्त्र विभाग, बीबीओएफ के विभागाध्यक्ष एवं आयोजक प्रो. सनातन नायक, प्रो. डी. के. यादव एवं डॉ. सुरेंद्र मेहर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत



दीप प्रज्वलन एवं बाबासाहेब के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। सर्वप्रथम प्रो. सनातन नायक ने सभी को अतिथियों के परिचय से अवगत कराया एवं पैनल चर्चा का विषय प्रस्तुत किया। कुलपति प्रो. एन.एम.पी. वर्मा ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि विकास में तेजी लाने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों निवेश किए जाने चाहिए। हालाँकि, सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश कम हो गया है, जो चिंता का एक बड़ा कारण है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च वर्तमान बजट में आवंटित राशि से अधिक होना चाहिए था। प्रो. ए. के. सिंह ने बजट को राजनीतिक व आर्थिक नजरिये से समझने की

जरूरत पर बल दिया। उनका कहना था कि जीडीपी में वृद्धि को गति देने के लिए निजी उपभोग मांग को बढ़ाना होगा। साथ ही अर्थव्यवस्था में आयुर्विध विवरण, स्वास्थ्य सुविधाएँ देने के साथ साथ उनकी काउंसिलिंग भी करते हैं। एकेडमिक फार्मिसिट, वैज्ञानिक फार्मिसिट की भूमिका बौद्धिक होने के कारण और भी बढ़ जाती है। यादव ने कहा कि इस संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ लगातार कार्य कर रहा है। इसी क्रम में प्रत्येक वर्ष अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें स्तनपान के बारे में जागरूकता, प्रचार प्रसार किया जाता है। यादव ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एस आई एच एक डब्लू के यूट्यूब चैनल पर शुक्रवार की शाम डॉक्टर के नाम शीर्षक से प्रत्येक शुक्रवार प्रसारित होने वाले लाइव वार्ताओं में एप्रील 15 में एक वार्ता नवजात शिशु को देखभाल, स्तनपान शीर्षक से सुलभ है।

स्तनपान के लिए जागरूक करें फार्मिसिट: सुनील यादव

लखनऊ। विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर फार्मिसिट फेडरेशन ने एक लिखित अपील और वीडियो ट्यूटोरियल जारी करते हुए सभी फार्मिसिटो से अपील की है कि स्तनपान से होने वाले लाभ के बारे में जनता में जन जागरूकता फैलाने के लिए आगे आए। अपील के माध्यम से फार्मिसिट फेडरेशन के अध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि फार्मिसिट जनता के अत्यंत करीब होता है। चाहे वह कम्यूनिटी फार्मिसिट हो जो मेडिकल स्टोर पर जनता के सीधे संपर्क में होता है, वही हॉस्पिटल या क्लिनिकल फार्मिसिट भी मरीज के सीधे संपर्क में आकर औषधि वितरण, स्वास्थ्य सुविधाएँ देने के साथ साथ उनकी काउंसिलिंग भी करते हैं। एकेडमिक फार्मिसिट, वैज्ञानिक फार्मिसिट की भूमिका बौद्धिक होने के कारण और भी बढ़ जाती है। यादव ने कहा कि इस संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ लगातार कार्य कर रहा है। इसी क्रम में प्रत्येक वर्ष अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें स्तनपान के बारे में जागरूकता, प्रचार प्रसार किया जाता है। यादव ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एस आई एच एक डब्लू के यूट्यूब चैनल पर शुक्रवार की शाम डॉक्टर के नाम शीर्षक से प्रत्येक शुक्रवार प्रसारित होने वाले लाइव वार्ताओं में एप्रील 15 में एक वार्ता नवजात शिशु को देखभाल, स्तनपान शीर्षक से सुलभ है।

सामान्य कार्यदिवसों की तरह कल खुले रहेंगे सभी आरटीओ कार्यालय: परिवहन आयुक्त

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश के समस्त आरटीओ कार्यालय 4 अगस्त, 2024 दिन रविवार को सामान्य कार्य दिवस की भांति प्रवर्तन टीम द्वारा पूरे प्रदेश में स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच हेतु शिविर कैम्प आयोजित किए जायेंगे। उल्लेखनीय है कि विगत माह से स्कूली एवं यात्री वाहनों की फिटनेस जांच हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। परिवहन आयुक्त चन्द्रभूषण सिंह ने शुक्रवार को समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों (प्रशासन/प्रवर्तन) एवं निरीक्षकों को आगामी रविवार को कार्यालय खोलने के संबंध में निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच हेतु शिविर कैम्प लगाने के निर्देश दिये। स्कूली वाहनों के फिटनेस जांच हेतु वाहन स्वामियों को जागरूक करने को कहा है। परिवहन आयुक्त ने कहा कि शिविर कैम्प के अंतर्गत स्कूली वाहनों के फिटनेस जांच हेतु आवश्यक स्टाल की व्यवस्था की जाए। जिससे फिटनेस जांच करने आने वाले वाहन स्वामियों को असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने वाहन स्वामियों से आग्रह किया है कि वे स्वयं भी आरटीओ कार्यालय आकर अपनी-अपनी वाहनों का फिटनेस जांच करायें। सरकार की मंशा है कि किसी भी परिस्थित में अनफिट वाहनों से बच्चों को स्कूल न आना जाना पड़े। अनफिट वाहनों की वजह से बच्चों की जान का खतरा बना रहता है। सुरक्षित यातायात मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है।

फिल्म प्रमोशन को लेकर राजधानी पहुँचे सितारे, एल्यू में लगाये दुमके

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

फिल्म स्त्री की सफलता के बाद मैडॉक फिल्मस और जियो स्टूडियोज के बैनर तले बनी हॉरर-कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 के आगामी 15 अगस्त को बड़े पड़े पर रिलीज होने को लेकर शुक्रवार को प्रमोशन के लिए अभिनेता राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पवन सिंह लखनऊ पहुँचे। दिन में लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच पहुँचे सितारों ने दुमके भी लगाये। इस दौरान पाँच स्टार के नाम से मशहूर भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह ने छात्रों से भोजपुरी में बात करते हुए फिल्म देखने की अपील की। प्रमोशन के बाद एक निजी होटल में मीडिया से मुखातिब हुए। फिल्म में विक्की का किर्दार निभा रहे राजकुमार राव कहते हैं, स्त्री के पहले पार्ट में दीवारों पर ओ स्त्री



कल आना लिखा जाता था, सिर्फ इसलिए ताकि स्त्री उस पढ़कर फिलहाल चली जाए। लेकिन, नए पार्ट में इन दीवारों पर लिखा मिलेगा ओ स्त्री रक्षा करना। यह देखा वाकई मजेदार होगा कि आखिर क्यों नए पार्ट में लोग चाहते हैं कि स्त्री है दिन उनके शहर चंदेरी में आए। विक्की की चोटी वाली गलफ्रेड का

किर्दार निभा रहें श्रद्धा कपूर कहती हैं कि इस बार फिल्म में फैंस और दर्शकों को सरकटे का दमदार आतंक देखने को मिलेगा। सरकटे का आतंक कहानी में नया आकर्षण जोड़ने का काम करेगा। फिल्म स्त्री 2 का निर्देशन अमर कौशिक ने किया है। वहीं दिनेश विजान की मैडॉक फिल्मस ने इसे निर्मित किया है।

अम्बेडकर चौराहे से होटल ताज तक जलभराव की समस्या होगी दूर

लखनऊ। गोमतीनगर के अम्बेडकर चौराहे से होटल ताज तक जलभराव की समस्या दूर करने की कवायद शुरू हो गई है। पीडब्ल्यूडी पूरे क्षेत्र का सर्वे कराकर प्रस्ताव तैयार करेगी, जिससे बाँरिश में जलनिकासी की उचित व्यवस्था की जा सके। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने वर्ष 2021 में अम्बेडकर चौराहे से ताज होटल तक सड़क पीडब्ल्यूडी को हँडओवर किया था, जिसके बाद सड़क की मरम्मत और रखरखाव की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी की है। यहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग

परिवार और दोस्तों संग घूमने और मस्ती करने पहुँचते हैं, लेकिन जलनिकासी की कवायद व्यवस्था न होने से बाँरिश के दौरान यहां घुटनों तक पानी भर जाता है। इससे वाहन चालकों को काफी दिक्कत होती है। जलभराव के कारण सड़क भी खराब हो जाती है। बुधवार को बाँरिश के दौरान भी यहां जलभराव के कारण काफी लोग फंस गए। इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने पूरे एरिया का सर्वे कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत ड्रेनेज सिस्टम, नाला निर्माण समेत अन्य पल्लुओं को देखा जाएगा।

हॉस्टल में मूलभूत सुविधाओं को लेकर नर्सिंग छात्रों ने दिया धरना

लखनऊ। हॉस्टल में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर शुक्रवार को किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के नर्सिंग संवर्ग की छात्र-छात्राओं ने शुक्रवार को धरना दिया। धरने के दौरान छात्राएँ हॉस्टल में सुविधा बढ़ाने की मांग कर रही थी। धरने पर बैठी छात्राओं ने बताया कि बाँरिश के दौरान हॉस्टल में पानी भर जाता है। एक-एक छात्राओं को रखा गया है। छात्राओं ने बताया कि कोई रेगुलर साफ-सफाई नहीं होती है। टायलेट का सीवर चोक हो जाता है। परिसर में दिन भर चले प्रदर्शन के दौरान विवि के अधिकारियों ने छात्रों को मनाने का प्रयास किया लेकिन नर्सिंग छात्र अपनी मांग पर अड़े रहे।

मेडिकल कालेजों की मदद को लेकर डिजिटल स्लाइड स्कैनर पर फोकस करें

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

एसजीपीजीआई के पैथोलॉजी पर विभाग द्वारा पल्मोनरी पैथोलॉजी पर सतत चिकित्सा शिक्षा के साथ अपना दूसरा स्थाना दिवस मनाया गया। इस मौके पर निदेशक प्रोफेसर राधा कृष्ण धीमन ने विभाग की नई नैदानिक तकनीकों की सराहना की। उन्होंने सभी संकाय सदस्यों और कर्मचारियों को पूर्ण समर्पण से काम करने और अन्य मेडिकल कालेजों की मदद के लिए डिजिटल स्लाइड स्कैनर और डिजिटल पैथोलॉजी को शामिल करके विभाग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रेरित किया।

विभाग के प्रमुख, प्रोफेसर मनोज जैन ने विभागीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। साथ ही उन्होंने सर्वाङ्कल कैंसर की जांच के लिए तरल आधारित साइटोलॉजी, रोगों के



सटीक निदान और पूर्वानुमान के लिए आणविक परीक्षण, शीघ्र व अधिक परिष्कृत के लिये पूरी तरह से स्वचालित क्लिनिकल रसायन विज्ञान प्रयोगशाला के माध्यम से नई नैदानिक तकनीक प्रदान करने में विभाग की उपलब्धियों को प्रस्तुत किया। इस मौके पर विभाग द्वारा हाल ही में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। फेफड़े के कैंसर के प्रचलित होने और 1 अप्रस्त को विश्व फेफड़े के कैंसर दिवस के रूप में पहचाने जाने के अवसर पर पल्मोनरी पैथोलॉजी पर आधे दिन की

सीएमई का आयोजन किया गया। पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध पल्मोनरी पैथोलॉजिस्ट प्रोफेसर अमनजोत बाल ने इस बात पर जोर दिया कि उन्नत नैदानिक परीक्षण के साथ फेफड़ों के कैंसर के इलाज में लिए कई चिकित्सीय विकल्प सामने आ रहे हैं। पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के प्रमुख प्रोफेसर आलोक नाथ ने छोटे और सटीक फेफड़ों के नमूने प्राप्त करने की नई तकनीकों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का समापन डॉ. राम नवल राव के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

इंटरनशिप अब सीपीसी बोर्ड की पहल का हिस्सा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

लखनऊ विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग के राधाकमल सभागार में शुक्रवार को केन्द्रीय प्लेसमेंट सेल (सीपीसी) बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में, प्रो. वाइस चांसलर प्रो. मनुका खन्ना, विश्वविद्यालय के डीन और विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। सत्र को प्रो. वाइस चांसलर मनुका खन्ना ने संबोधित किया और सीपीसी बोर्ड के निदेशक प्रोफेसर अनूप के. भारतीय ने नेतृत्व किया।

प्रो. मनुका खन्ना ने प्रमाणन के साथ लघु अवधि के पाठ्यक्रमों को शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो विश्वविद्यालय के छात्रों को प्लेसमेंट इंटरव्यू में प्रतिस्पर्धात्मक बहुर प्रदान करेंगे। प्रोफेसर अनूप भारतीय ने बताया कि इस बैठक का उद्देश्य सीपीसी बोर्ड की प्रभावशीलता को बढ़ाना था। उन्होंने घोषणा की कि इंटरनशिप अब सीपीसी बोर्ड की पहलों का हिस्सा होंगी। हालाँकि, उन्होंने विभागीय स्तर पर प्रशिक्षण और प्लेसमेंट सेल में सुधार की



आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रोफेसर भारतीय ने पारंपरिक पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए अवसरों को आमंत्रित करने के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए पहले से ही कई नियोजता हैं। विभागाध्यक्षों से पूर्व छात्रों, प्लेसमेंट डेटा और उपलब्धियों की सूचियाँ प्रदान करने का अनुरोध किया गया। उन्होंने नए छात्रों के लिए सीपीसी के साथ ओरिएंटेशन प्रोग्राम की आवश्यकता पर भी जोर दिया, ताकि उन्हें भविष्य के करियर संभावनाओं

को समझने में मदद मिल सके। जिला रोजगार ब्यूरो के प्रशिक्षण और प्लेसमेंट विभाग से एक सरकारी अधिकारी ने बैठक में भाग लिया और प्लेसमेंट पर व्यावहारिक जानकारी प्रदान की। यह बताया गया कि आज के नौकरी बाजार में डिग्री से अधिक कौशल को महत्व दिया जाता है। विभागाध्यक्षों ने वर्तमान प्लेसमेंट अनुपात द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ।

फर्जी टाउनशिप को चिन्हित कर करें कार्रवाई: डॉ रोशन जैकब

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब की अध्यक्षता में सरोजिनी नगर तहसील में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के विरुद्ध चल रही कार्यवाही के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक की गयी। मंडलायुक्त द्वारा सरकारी भूमि की पैमाइश नगर निगम व राजस्व की संयुक्त टीम मौके पर उपस्थित रहते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया। वहीं, मंडलायुक्त द्वारा शहर के अवैध प्लॉटिंग एवं फर्जी टाउनशिप को चिन्हित करते हुए ध्वस्तिकरण की कार्यवाही में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। शुक्रवार को मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब की अध्यक्षता में सरोजिनी नगर तहसील में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के विरुद्ध चल रही कार्यवाही के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन स्मार्ट सिटी ऑफिस के सभागार में की गई। बैठक के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मंडलायुक्त को अवगत कराया गया कि सात गाँवों को पहले चरण में 70



गाटो का सर्वे करा लिया गया है। जिस पर उन्होंने संबंधित को निर्देशित करते हुए कहा कि सरकारी भूमि की पैमाइश के लिये बनाई गई स्पेशल टीम के द्वारा सरकारी भूमि के सर्वे में तेजी लाये। सर्वे किये गये भूमि का चिन्हाकन एवं सीमांकन कराते हुए संबंधित भूमि को अपने स्वामित्व में लेते हुए एक भूमि पर बोर्ड व पत्थर गाड़ते हुए सरकारी भूमि को सुरक्षित किया जाये। इसके मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शहर के अवैध प्लॉटिंग

व फर्जी टाउनशिप को चिन्हित करते हुए ध्वस्तिकरण को कार्यवाही की जाये। उन्होंने मागों एवं चकमागों पर जनवरो को न बाधने को लेकर प्रतिबंधित किया जाने के निर्देश दिये। सर्वे के लिए बनाई गई स्पेशल टीम के प्रभारी द्वारा नियमित रूप से की जारी कार्यवाही की मॉनिटरिंग करते रहें। नगर निगम व राजस्व की टीम संयुक्त रूप से मौके पर रहते हुए कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे। पैमाइश के दौरान अवैध अतिक्रमण मिलने पर तत्काल ध्वस्तिकरण कराते रहे।

सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे में अधिकारियों की संलिप्तता पर मंडलायुक्त की कड़ी चेतावनी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

बीकेटी में अवैध कब्जे की शिकायत पर मंडलायुक्त द्वारा दौराकर क्षेत्र का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान मंडलायुक्त द्वारा रामपुर, देवरई, हाजीपुर सहित अन्य क्षेत्र में अधिकारियों के साथ पहुंची। अधिकारियों को पैमाइश कर जमीन को अपने कब्जे में लेने का निर्देश दिया गया। शुक्रवार को सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा की शिकायत मिलने पर मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब तहसील बीकेटी के ग्राम रामपुर देवरई, हाजीपुर, उनई पहुंचकर, संबंधित सरकारी भूमि का जायजा लिया। साथ ही सरकारी भूमि के संबंधित गाटों की गहनता पूर्वक पड़ताल करने के निर्देश संबंधित को दिए। रामपुर देवरई में

गाटा संख्या 316, 317, 652, 653 का जायजा लेते हुए कहा कि उक्त भूमि की पैमाइश कराते हुए अपने स्वामित्व में लिया जाये। उन्होंने कहा कि तहशील के संबंधित अधिकारियों द्वारा सरकारी भूमि के अवैध कब्जों में संलिप्तता व भू माफियों को संरक्षण देने की जानकारी मिलने पर संबंधित की खिलाफत मंडलायुक्त कार्यवाही की जाएगी। मंडलायुक्त ने बताया कि लखनऊ जनपद के समस्त सरकारी भूमि को अवैधकब्जा से अतिक्रमण मुक्त करने के लिये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जो कि जनपद के समस्त क्षेत्र के सरकारी भूमियों की पैमाइश, जीएस मैपिंग व जीरो टैगिंग कराया जाना सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीनों का चिन्हाकन सीमांकन करके अपने स्वामित्व में लिया जाएगा।

कावड़ यात्रा मार्गों, प्रमुख धार्मिक स्थलों व मंदिरों में हो 24 घंटे विद्युत आपूर्ति: ऊर्जा मंत्री

● बार-बार ट्रांसफार्मर जलने और ओवरलोड फीडर की लगातार निगरानी किए जाने के लिए निर्देश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ



मिले, इसके लिए सभी क्षेत्रों को निर्धारित शेड्यूल के अनुरूप बिजली आपूर्ति की जाए, वहीं पर भी अनावश्यक कटौती न हो। ट्रांसफार्मर के जलने पर निर्धारित समय पर बदलने का प्रयास किया जाए। सभी विद्युत कार्मिक पूरी इमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करें, अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से संवाद बनाए रखें, सभी के फोन उठाए, उपभोक्ताओं की समस्याओं का

तत्काल समाधान करें। ऊर्जा मंत्री शुक्रवार को शक्ति भवन में विद्युत व्यवस्था और कार्यों की वर्युअल समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिए कि बार-बार ट्रांसफार्मर के जलने, किसी एक फीडर पर बार-बार विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही, फीडर के ओवर लोड होने और लो वोल्टेज की समस्याओं की लगातार मॉनिटरिंग करें। ऐसी जगहों पर विद्युत चोरी करने, कटिया लगाने की संभावना रहती है, इसकी नियमित जांच की जाए और विद्युत चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी करें। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर जलने पर अगर उस क्षमता का ट्रांसफार्मर उपलब्ध न हो तो उससे ज्यादा क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाए, उन्हीं इसके

लिए एसओपी जारी करने के भी निर्देश दिए। ट्रांसफार्मर के जलने और उसके बदलने की जानकारी को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को उपलब्ध कराए और मुख्यालय को भी इसकी जानकारी दें। किसी फीडर में रिकॉर्ड से ज्यादा लोड होने पर तत्काल इसकी विजिलेंस जांच कराए। सभी डिस्कॉम के एमडी निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए मैनेजमेंट और प्लानिंग पर फोकस करें तथा अपनी टेक्निकल टीम को सतर्क रखें।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बेहतर प्रबंधन और कार्मिकों की मेहनत के कारण ही 30 से 31 हजार से अधिक मेगावाट बिजली देने में हम सक्षम हुए हैं। फिर भी बिजली न आने की शिकायतें आ रही हैं। उन्हीं लोड

मैनेजमेंट पर ध्यान देने तथा माइक्रो मैनेजमेंट के तहत कार्य करने को कहा। विद्युत आपूर्ति को लेकर कई जनप्रतिनिधियों ने शिकायतें की हैं, मऊ से शिकायत है की बिजली न आने से इंसुलिन के इंजेक्शन खराब हो गए। सभी डिस्कॉम अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर कार्य योजना बनाएं और उसी के तहत आरडीएसएस और बिजनेस प्लान के तहत कार्य कराए। ऊर्जा मंत्री ने मऊ जनपद में बुधवार को हुई बारिश से 152 पोल् एलटी लाइन के 11 पोल् एचटी लाइन के तथा एक पोल् 33 केवी लाइन का गिरने की जांच कराकर संबंधित कंपनी पर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्हीं कहा कि सभी विद्युत पोल् को ग्राउंडिंग ठीक से कराई जाए।



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विवेक हिंदू परिषद गोरखा विभाग अवध प्रांत के प्रांत गोरखा प्रमुख राजेश सिंह के की शिष्टाचार भेंट

नवनियुक्त सहायक अनुभाग अधिकारियों को दिया जा रहा है आधारभूत प्रशिक्षण

लखनऊ। केन्द्रीय सचिवालय भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में नवनियुक्त सहायक अनुभाग अधिकारियों को 12 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बखी का तालाब, लखनऊ में दिया जा रहा है। इन्हें ग्रामीण लगाव एवं भारत दर्शन विषय पर व्यवहारिक प्रशिक्षण एवं ग्रामीण अध्ययन भ्रमण भी कराया जा रहा है। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास संस्थान के प्रभारी अक्षय निदेशक बीडी चौधरी ने बताया कि इस आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में

भारत सरकार के संघ लोक सेवा आयोग, जल संसाधन, भूतल परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग, सूचना एवं प्रसारण, संचार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, रक्षा, नीति आयोग, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास, नागरिक उड्डयन, पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, कृषि एवं कृषक कल्याण, विधि मामले, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आवास एवं शहरी कार्य तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इत्यादि मंत्रालयों से सम्बद्ध सहायक अनुभाग अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। प्रशिक्षण

सत्र के दौरान संस्थान के प्र. अक्षय निदेशक बीडी चौधरी द्वारा प्रतिभागी अधिकारियों को सम्बोधित करते हुये संस्थान के संस्थापक डॉ.चा, संकायों से सम्बद्ध कार्यों तथा प्रशासनिक नियंत्रणधीन प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों की कार्यशैली तथा प्रशिक्षण विधा के अन्तर्गत आने वाली समस्त गतिविधियों तथा प्रशिक्षकों की भूमिकाओं से, विधिवत व विस्तृत रूप से परिचित कराया गया और प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण क्यों? प्रशिक्षण कब? इन विषयों पर भी व्याख्यान दिया गया।

रालोद के जिलाध्यक्ष 31 अक्टूबर तक घोषित होंगे

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय की अध्यक्षता में प्रकोष्ठ के अध्यक्षों एवं क्षेत्रीय अध्यक्षों की एक बैठक आयोजित की गयी। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी मौजूद रहे। बैठक में किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलवंत सिंह बिट्टू उपस्थित रहे। बैठक को सम्बोधित करते हुये राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने संगठन विस्तार पर चर्चा करते हुए सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षों व क्षेत्रीय अध्यक्षों को निर्देशित किया कि सभी प्रकोष्ठों की 31 अगस्त तक क्षेत्रीय कमेटी एवं 31 अक्टूबर तक जिलाध्यक्ष घोषित कर दिये जाय, 15 सितंबर से समीक्षा की शुरुआत होगी। प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने कहा कि संगठन किसी भी राजनैतिक दल की रीढ़ होती है एवं संगठन की मजबूती पर ही राजनैतिक दल की सफलता निर्भर करती है।

बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा

विधि संवाददाता। लखनऊ

चार वर्ष की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्त रूपक जैन उर्फ काजू को पाँक्सो की विशेष अदालत ने 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष जज विजेन्द्र त्रिपाठी ने इस पर 30 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। 13 जुलाई 2022 को इस मामले की एचआईआर पीड़िता की मां ने थाना पारा में दर्ज कराई थी। विशेष लोक अभियोजक अभिषेक उपाध्याय व अरुण कुमार के मुताबिक पीड़िता और उसका भाई घर के नीचे खेल रहे थे। पापा ने पीड़िता को मार दिया तो रोते हुए अंदर कमरे में चली गईं। इन्होंने आरोपी गाड़ी की चाबी लेने आया। वो पीड़िता को चुप कराने लगा। इस दौरान वो पीड़िता के साथ गलत हरकत करने लगा। पीड़िता और जोर से रोने लगी और मम्मी मम्मी चिल्लाने लगी। उसकी मम्मी आई तो रोकर बताने लगी कि काजू अंकल उसके साथ गलत काम कर रहे थे।

नाथ नगरी इंटीग्रेटेड टाउनशिप में शापिंग कांप्लेक्स के ऊपर बनाए जाएंगे पलैट

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

बरेली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप बरेली विकास प्राधिकरण बरेली में प्रदेश की पहली अनुठी नाथ नगरी इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित करने जा रहा है। बीडीए ने इसके लिये पांच गांवों की जमीन चिह्नित की है। जमीन खरीदने की तैयारी शुरू हो गई है। इंटीग्रेटेड टाउनशिप में आइटी पार्क, औद्योगिक क्षेत्र, मल्टीस्पेशलिटी हास्पिटल, अपार्टमेंट, शापिंग कांप्लेक्स, आउटलेट, शिक्षण संस्थान विकसित करने के लिये लेआउट और डिजाइन तैयार किया गया है। विश्वस्तरीय सौंदर्यीकरण के साथ टाउनशिप में आने जाने के लिये इलेक्ट्रिक वाहनों की सुविधा मिलेगी। अत्याधुनिक पार्किंग स्थल रहेगा।

इंटीग्रेटेड टीओडी टाउनशिप में शापिंग कांप्लेक्स के ऊपर पलैट बनेंगे। इसमें ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) नीति के प्रविधानों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें तीन चार

● मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप टाउनशिप के साथ विकसित होगा रामगंगा रिवरफ्रंट

मंजिल तक नीचे शापिंग कांप्लेक्स होंगे। उसके ऊपर गगनचुंबी पलैट बनेंगे। बीडीए उपाध्याय ने बताया कि इसके विकास के साथ नाथ नगरी बरेली के विकास को नये आयाम मिलेंगे। नाथ धाम इंटीग्रेटेड टाउनशिप से आवासीय विकास के साथ एमएसएमई एवं बरेली के उत्पादों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जायेगा।

बीडीए सचिव योगेंद्र कुमार ने बताया कि यह प्राधिकरण का महात्वांक्षी प्रोजेक्ट है। टाउनशिप के साथ बीडीए रामगंगा रिवरफ्रंट का डेवलपमेंट भी करवाएगा। इसका विकास जैविक संरक्षण के साथ पर्यावरण के अनुकूल होगा। इसमें बायोडायवर्सिटी पार्क का भी विकास कराया जाएगा। मुख्य आकर्षण-भारत सरकार की टीओडी नीति के तहत विकास, शापिंग कांप्लेक्स एवं ऊपरी

तल पर पलैट, जूरी जूरेटोर्जी सेंटर का विकास, पलैटेड डेवलपमेंट माड्यूल के तहत, विश्व स्तरीय स्टेडियम प्रस्तावित, लघु उद्योग की स्थापना के लिए पर्याप्त अवसर, गंगा एक्सप्रेसवे से 15 मिन्ट की दूरी पर प्रस्तावित है। इससे एमएसएमई एवं जूरी जूरेटोर्जी के निर्यात में सुगमता होगी। बरेली के उत्पाद जूरी जूरेटोर्जी के कामगारों की रिकल को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी लगेगी। इसके साथ उत्पाद इंटीग्रेटेड टाउनशिप से आवासीय विकास लिए के लिए दुकान और काम करने वाले के लिए एमएसएमई सेंटर की व्यवस्था की जायेगी। आर्किटेक्ट सुमित अग्रवाल ने बताया कि टाउनशिप में छोटे कामगारों एवं व्यापारियों के लिए पलैटेड डेवलपमेंट के रूप में छोटी पूंजी में जगह उपलब्ध होगी। जिसके नीचे एक्विजिशन एवं कन्वेंशन सेंटर होंगे। जूरी जूरेटोर्जी के उत्पादों के निर्यात को सुगम बनाने के लिए एक्सपोर्ट हाउस एवं आधुनिक होटल प्रस्तावित किये जा रहे हैं। टाउनशिप को विश्व स्तरीय मानकों पर विकसित किया जा रहा है।

आजमगढ़ से वांछित 25 हजार का इनामी अपराधी आशीष उर्फ हंटर गिरफ्तार

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

आजमगढ़ से वांछित 25 हजार के इनामी अपराधी आशीष यादव उर्फ बिट्टू उर्फ हंटर को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। हंटर के खिलाफ थाना निजामाबाद धारा 109/ 115 (2)/ 352/ 351(1) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज है। एसटीएफ को सूचना मिली कि कुख्यात अपराधी आशीष यादव उर्फ बिट्टू उर्फ हंटर अपने घर आने वाला है। इस सूचना पर एसटीएफ ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर घेराबंदी की और आशीष यादव को असनी पुलिया से गिरफ्तार कर लिया। आशीष यादव ने पूछताछ पर बताया कि उसने 29 जुलाई 2024 को रायि लगभग 10 बजे अपने गांव के बाल्मीकि यादव पुत्र जगधारी यादव निवासी मोहनपुर, थाना निजामाबाद को गोली मारी थी। जिसमें आशीष यादव जो कि उसके गांव के रहने वाले हैं, के साथ बाइक चलाकर बाल्मीकि यादव के घर गया था। उसने बाल्मीकि यादव को गोली मारी और ब्रजेश के साथ बाइक से भाग आया। कड़ाई से पूछताछ पर बताया कि बाल्मीकि यादव के पुत्र नीरज यादव से उसका विवाद चल रहा था और उसने भरे पिता व परिवार वालों को कुछ दिन पहले मार-पीट किया था। जिसमें भरे पिता व भाई को चोट लग गयी थी। जिसका बदला मैंने बाल्मीकि यादव को गोली मार कर लिया था। नीरज यादव के विरुद्ध भी कई मुकदमें दर्ज हैं। अभियुक्त तभी से अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए वह छिपाता फिर रहा था।

ऋषा वितरण व ब्याज उपादान भुगतान की कार्रवाई तेजी से पूरी की जाए

लखनऊ। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के खादी भवन के सभाकक्ष में मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. उज्वल कुमार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यालय के अधिकारियों के साथ-साथ परिक्षेत्रीय/जनपदीय अधिकारियों एवं मंडलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्यों से विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। बैठक में डॉ. कुमार ने निर्देश दिए गए कि जनपद के मुख्य अधिकारी अधिकारी की अध्यक्षता में प्रति सप्ताह होने वाली बैठकों में बैंकों को प्रेषित आवेदन पत्रों का विवरण उपलब्ध कराते हुए ऋषा वितरण एवं स्वीकृति की कार्यवाही कराई जाए, साथ ही ब्याज उपादान के दवाों के भुगतान को इशारा करने पर उस व्यक्त द्वारा खुद को पुलिस से घिर देवा पुलिस के ऊपर जान से मारने की न्ययत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा आन्तरिकार्थ फायरिंग की गई। जिसमें अभियुक्त नीरज पुत्र संतराम निवासी ग्राम झरौड़ीया थाना कोटवाली शहर जनपद हरदोई गोली लगने से घायल हो गया।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यूपी के सभी सेक्टरों में तेजी से हो रहा विकास: मनोज कुमार सिंह



पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से प्रांतीय सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के 31 प्रशिक्षु अधिकारियों ने भेंट की। इस मौके पर मुख्य सचिव ने प्रशिक्षु अधिकारियों का उत्तर प्रदेश शासन परिवार में स्वागत करते हुए कहा कि यूपी कैडर देश के सर्वश्रेष्ठ केंद्र में से एक है। आप सभी भाग्यशाली हैं कि आप लोगों को उत्तर प्रदेश में काम करने का मौका मिला। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सभी सेक्टरों में तेजी से विकास हो रहा है। यह सेवा दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करती है। नए जोश एवं

● मुख्य सचिव से प्रांतीय सिविल सेवा के 31 प्रशिक्षु अफसरों से भेंट की

उत्साह के साथ जनहित में कार्य करें। उन्हीं कहा कि कानून-व्यवस्था और विकास कार्यक्रमों के क्रियाबन्धन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राजस्व संबंधी मामलों को लम्बित न रखें। जनता से संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान करें। विकास कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण कर उसे समयवधि में पूरा करायें। बैठक में अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव परिवहन एल. वैकटेश्वर लू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश के सभी प्रमुख मार्गों के किनारे 1001 ढाबों पर पर्यटकों को मिलेंगी मनपसंद सुविधाएं

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) और राज्य राजमार्ग (एसएच) सहित अन्य प्रमुख मार्गों के किनारे स्थित 1001 ढाबों की सूची बनाई है। यहां विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पर्यटन विभाग की ओर से 25 से 30 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा, ढाबों का बड़ी कंपनियों के साथ कॉलैबोरेशन कराया जाएगा। ताकि, पर्यटकों को इन कंपनियों के प्रोडक्ट भी ढाबों पर आसानी से मिल सकें। ढाबों पर काम करने वाले कर्मचारियों को अच्छे आतिथ्य-सत्कार के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

यह जानकारी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि पर्यटन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तेजी से विकास करने वाला राज्य है। यहां वर्ष 2023 में 48 करोड़

से अधिक पर्यटकों ने भ्रमण किया था। प्रतिदिन देश-दुनिया से लाखों लोग अयोध्या, काशी, मथुरा, बौद्ध स्थल सहित अन्य स्थानों पर पहुंच रहे हैं। राज्य में पर्यटन स्थलों और पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। विभाग का प्रयास है कि पर्यटकों को गंतव्य स्थल तक पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। पर्यटक कहीं धूमने जा रहे हैं तो सफर में ऐसे स्थल का आवश्यकता होगी, जहां आराम करने के साथ-साथ खाने-पीने सहित अन्य सुविधाएं गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध हों। पर्यटन विभाग इसी जरूरत को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में एनएच, एसएच सहित अन्य प्रमुख मार्गों पर स्थित ढाबों को बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित करने की तैयारी है।

प्रदेश भर में 10 अगस्त से 2 सितंबर तक चलेगा सर्वजन दवा सेवन अभियान

● 340 ब्लॉक में 61512 टीमें घर-घर जा कर कराएंगी दवा का सेवन

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश भर में 10 अगस्त से शुरू हो रहे सर्वजन दवा सेवन अभियान में 6 करोड़ 69 लाख लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जाएगी। यह दवा फाइलेरिया से बचाव के साथ-साथ पेट से कीड़े निकालने और शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक साबित होती है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अलावा शिक्षा विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार, पंचायती राज और महिला कल्याण विभाग से भी सहयोग लिया जा रहा है।

फाइलेरिया प्रभावित 27 जिलों में 6.69 करोड़ लोगों को खिलाई जाएगी दवा

संक्रमित मच्छर को दाने से किसी भी आयु वर्ग में होने वाला यह संक्रमण लिम्फैटिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और अगर इससे बचाव न किया जाए तो शारीरिक विकलांगता भी आ सकती है। स्वास्थ्य प्रणाली के पास फाइलेरिया रोग की रोकथाम, प्रबंधन और उन्मूलन के लिए सारे समाधान उपलब्ध हैं। इन समाधानों से न केवल फाइलेरिया रोगी लाभान्वित हो रहे हैं बल्कि ऐसे लोगों को भी फायदा हो रहा है जिनके शरीर में फाइलेरिया परजीवी मौजूद हैं और जिन्हें इसके संक्रमण का जोखिम है। 27 फाइलेरिया प्रभावित जिलों में चलेगा अभियान: यह अभियान प्रदेश के 27 फाइलेरिया प्रभावित जिलों में चलाया जाएगा। ये जिले हैं औरैया, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, चन्दौली, देवरिया, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हरदोई, कन्नौज,

कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मीरजापुर, रायबरेली, महाराजगंज, संतकबीरनगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर एवं सीतापुर। प्रमुख सचिव ने अपील की कि यदि आप इनमें से किसी भी जिले में रह रहे हैं तो अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करें। क्षेत्र की आशा से संपर्क करें या निकटतम बूथ पर जाएं और फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन करें जिससे आप खुद को, परिवार को, आस-पड़ोस, समुदाय, गाँव, कस्बे, शहर और प्रदेश के हर व्यक्ति को सुरक्षित रख सकें। समुदाय को भागेदारी से ही प्रदेश से फाइलेरिया का उन्मूलन संभव है। हाथोपांव, हाइड्रोमील, हाथ-पैर व स्तन में सूजन है तो ये फाइलेरिया के लक्षण हो सकते हैं। इस बार 6.69 करोड़ लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य: संयुक्त

निदेशक वेक्टर बोर्न डीजीए एवं राज्य के नोडल अधिकारी डा. ए.के. चौधरी ने बताया कि यूपी में इस बार 6.69 करोड़ लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य सधने के लिए 1,23, 024 स्वास्थ्यकर्मी और 12,302 पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। इस बार अभियान मे 340 ब्लॉकों मे टीमें घर-घर जाकर दवा सेवन कराएंगीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में दवा का वितरण नहीं किया जाएगा। अभियान के दौरान सभी को फाइलेरिया रोधी दवा की निर्धारित खुराक प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी बूथ व घर-घर जाकर अपने सामने खिलाएंगे। ध्यान रहे कि यह दवा खाली पेट नहीं खानी है। इस दवा का सेवन एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती और गंभीर रूप से बीमार को छोड़कर सभी को करना है। एक वर्ष से दो वर्ष तक के बच्चों को केवल अलंबेडजोल की आधी गोली (200 मिलीग्राम) खिलाई जाएगी।

माध्यमिक शिक्षा विभाग में लागू होगा सिटीजन चार्टर

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

इस बार सरकार शिक्षक दिवस पर माध्यमिक शिक्षकों को तोहफा देने की तैयारी कर रही है। इसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग में सिटीजन चार्टर लागू किया जायेगा। जिससे सभी संगर्गों की दशकों पुरानी लंबित समस्याओं का जल्द निपटारा हो सकेगा। साथ ही विभाग के साथ-साथ सभी माध्यमिक स्कूलों में सभी पक्षों की शिकायतों का भी समयबद्ध निस्तारण हो सकेगा। इतना ही नहीं सिटीजन चार्टर लागू होने से विद्यालय स्तर से लेकर मंडल और निदेशालय स्तर तक के लंबित मामलों के निस्तारण की जबाबदेही तय होगी और समस्याओं का भी समयबद्ध निस्तारण होगा। तय समय के भीतर सिटीजन चार्टर की रूप-रेखा तैयार हो सके, इसके लिए विभाग के सभी संगर्गों के संगठनों से 31 जुलाई तक सुझाव मांगे थे। सुर्गों का कहना है कि अन्तिम तिथि तक अलग-अलग

संगठनों से इस दिशा में दर्जनों उपयोगी सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिसका परीक्षण किया जा रहा है। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के विद्यालय से लेकर निदेशालय स्तर पर लंबित वर्षों से अवशेषों का भुगतान एक बहुत ही बड़ी समस्या है। यह होगा लाभ: जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर की विभिन्न समस्याओं के अलावा शिक्षकों व कर्मचारियों के चयन एवं एसीपी, अस्थायी जीपीएफ, अग्रिम वेतन निर्धारण, प्रमाण एवं प्रबंधक के हस्ताक्षर प्रमाणित किये जाने आदि मामले तय समय सीमा के भीतर निस्तारित हो जाएंगे। इसके अलावा मंडल स्तर की समस्याओं के निस्तारण के साथ-साथ जीपीएफ अग्रिम, आदेश एवं भुगतान, पदोन्नतियाँ, विनियमितकरण, पीपीओ एवं सेवा निवृत्त संबंधी सभी देयकों के भुगतान के मामले भी तय समय के भीतर निस्तारित हो सकेंगे।

विद्या शक्ति केंद्र का सीडीओ ने किया शुभारम्भ

संवाददाता। सोनभद्र

जनपद में नीति आयोग द्वारा अधिगम स्तर सुधार हेतु संचालित पैललेब का द्वितीय सत्र और विद्या शक्ति केंद्र का जनपद में एक साथ सभी विद्यालयों में शुभारम्भ मुख्य विकास अधिकारी सौरभ गंगवार द्वारा कंपोजिट विद्यालय मुसही राबट्सगंज में किया गया। इस अवसर पर, मुख्य विकास अधिकारी ने योजना का लाभ ले रहे कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों से वार्ता कर स्थिति को परखा। उन्होंने इस पहल को सराहना करते हुए कहा कि समय सारणी के साथ शिक्षण और पैललेब में छात्रों को उनकी अधिगम क्षमता के अनुसार पुनरावृत्ति, उपचारात्मक शिक्षण एवम मूल्यांकन अपेक्षित अधिगम स्तर को प्राप्त किया जा सकता है।

मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को भाषा, गणित और विज्ञान को रोचक तरीके से पढ़ाने के लिए



आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी. कामाकोटी द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट विद्या शक्ति को भी सोनभद्र में स्थापित स्मार्ट क्लासों में चलाया जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकुल आनन्द पाण्डेय ने बताया कि कक्षा 1 और 2 के लिए शिवनाड प्रउन्डेशन द्वारा शिक्षा इनेशिएटिव अन्तर्गत भाषा और गणित हेतु डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराया गया है जो छात्रों के बुनियादी भाषा और संख्या को सुदृढ़ करने में मदद कर रहा है।

इस कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी राबट्सगंज धनंजय सिंह,

एआरपी हर्देश सिंह, जिला कार्यक्रम सहयोगी, नीति आयोग परदीन अहमद, जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुधांशु तिवारी और शिक्षक मौजूद रहे और सभी ने मिलकर जनपद को निपुण बनाने की प्रतिज्ञा ली।

मुख्य विकास अधिकारी ने विद्यालयी परिवेश के बाहर सामुदायिक सहभागिता के माध्यम भी निपुण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपस्थित अभिभावकों, विद्यालय प्रबंध समिति और प्रधान का आह्वान किया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने कंपोजिट विद्यालय मुसही के छात्रों से विभिन्न

स्तर के प्रश्न पूछकर उनके अधिगम स्तर को परख रहे थे, उन्होंने कक्षा 5 के छात्रों से सामूहिक रूप से प्रश्न किया कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो सभी ने सही जवाब दिया।

फिर उन्होंने पूछा कि एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं तो एक छात्र ने तपाक से सही उत्तर दिया, तब उन्होंने उसी छात्र से पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, छात्र ने इधर उधर देखा और कक्षा में लगे हुए स्मार्ट बोर्ड की ओर चला गया, लोग भौचक्ये रह गए कि ये क्या कर रहा है। उसने स्मार्ट बोर्ड को बड़े ही आत्मविश्वास से ऑन किया और प्रश्न को हल करते हुए सही उत्तर बता दिया।

उन्होंने कहा कि डिजिटल शिक्षण प्रणाली को उपयोगिता को इस छात्र ने सार्थक किया है, आकांक्षी जनपद सोनभद्र में परिपरीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास को प्रारंभ करने का निर्णय सार्थक साबित हो रहा है।

इफको यूनियन चुनाव की अंतिम सूची प्रकाशित हुई

प्रयागराज। इफको इम्प्लाईज यूनियन के चुनाव छह अगस्त को होना है। जिसमें अंतिम सूची प्रकाशित कर दी गई। कुल 31 उम्मीदवार विभिन्न पदों पर चुनावी मैदान में होंगे। अध्यक्ष पद पर पंकज पाण्डेय मनोज कुमार तिवारी एवं संतोष कुमार उपाध्यक्ष पद पर धर्म सिंह पटेल प्रभात कुमार एवं सुरेश कुमार सिंह यादव महामंत्री पद पर मनोज कुमार श्रीवास्तव विजय कुमार यादव एवं विनय कुमार यादव संयुक्त मंत्री संगठन पद पर विनोद कुमार यादव वीरम यादव संताज अली एवं सालिक राम पटेल संयुक्त मंत्री प्रचार पद पर अभयराज यादव रजनीश राव एवं राहुल कुमार सहायक मंत्री पद पर अभिषेक पटेल एन जी नायर राम चन्द्र गौतम राम बाबू जयसवाल विनीत कुमार राय एवं ज्ञान सिंह पटेल कोषाध्यक्ष पद पर अनुल तिवारी गौरव श्रीवास्तव एवं दिनेश कुमार मौर्य वहीं कार्यकारणी सदस्य पद पर पंकज सिंह मो आरिफ अंसारी मनोज पटेल विनोद कर्नौजिया सुनील वैश्य एवं सुनील कुमार पाल मैदान में होंगे।

कानपुर स्टेशन पर बिना टिकट यात्रियों एवं अनधिकृत वेंडरों के विरुद्ध चला अभियान

संवाददाता। प्रयागराज

मंडल रेल प्रबन्धक प्रयागराज के नेतृत्व में रेल यात्रियों को सुरक्षित सुखद और आरामदायक यात्रा के साथ बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रयागराज मंडल में अवैध वेंडरों गंदगी फैलाने वालों टिकट रहित और अनियमित यात्रा पर अंकुश लगाने के लिए स्टेशनों व गाड़ियों में विशेष टिकट चेकिंग अभियान चला रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को कानपुर वाणिज्य टीम ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर बिना टिकट यात्रा अनियमित यात्रा एवं अनाधिकृत वेंडरों के विरुद्ध सघन अभियान चलाया गया।

कानपुर सेंट्रल पर गाड़ी संख्या 12488 सीमांद विहार टर्मिनल जोगबानी सीमांचल सुपर फास्ट एक्सप्रेस के प्लेटफार्म संख्या छह पर आगमन के समय वाणिज्य टीम ने



चेकिंग के दौरान दो अनाधिकृत वेंडरों को खानपान सामग्री के साथ पकड़कर रेलवे सुरक्षा बल कानपुर को सौंप दिया गया। इन वेंडरों से 08 कार्टून बिसलरी ब्रांड का पानी जब्त कर एलपीओ आफिस में जमा कर दिया गया। इस चेकिंग अभियान में 38 बिना टिकट एवं अनियमित यात्रियों को पकड़ गया और 14850 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। टिकट चेकिंग अभियान के दौरान यात्रियों को उचित टिकट के साथ

यात्रा करने के लिए जागरूक भी किया गया। प्रयागराज मण्डल में इस तरह के अभियान निरंतर चलाए जा रहे हैं। उचित मध्य रेलवे रेल यात्रियों से अपील करता है कि अनुविधा से बचने और सम्मान के साथ यात्रा करने के लिए उचित और वैध रेलवे टिकट के साथ यात्रा करें। यह जानकारी अमित कुमार सिंह जनसंपर्क अधिकारी प्रयागराज मण्डल उतर मध्य रेलवे ने दी।

कृषि विकास योजना के तहत किया जाये लाभार्थियों का चयन: डीएम



सोनभद्र। जिलाधिकारी बीएन सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति/जिला मिशन समिति एवं डेब्ल्यूसीडीसी की बैठक सम्पन्न हुई, परियोजना क्षेत्र के स्वयं सहायता समूहों को उत्पादक स्वतः रोजगार के माध्यम से चयनित कर लाभ पहुंचाया जायेगा व पंचदीनस्थाल उपाध्यय किसान समुद्धि योजना के अन्तर्गत क्षेत्रफल 800.00 हे० तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत कुल 70 लघु तालाब पहले आवक पहल पावक के आधार पर ऑनलाईन पंजीकरण के माध्यम से चयन कर

किया जायेगा। मनरेगा कन्वेंन्स के अन्तर्गत क्षेत्रफल 1497.00 हे० भूमि सुधार का कार्य विकास खण्ड-धोरावल, नगवां एवं चोपन में किया जायेगा, इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उक्त समस्त योजनाओं का पारदर्शिता पूर्वक क्रियाचन्यन करया जाना सुनिश्चित किया जाये, उक्त योजनाओं से सम्बन्धित कार्य में किसी स्तर पर लापरवाही व शिथिलता न बरती जाये और पूरी पारदर्शिता के साथ पात्र लाभार्थियों का कृषि विकास के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन पारदर्शिता के साथ किया जाये।

विकसित भारत की संकल्पना दूरस्थ शिक्षा से होगी पूर्ण: कुलपति

●प्रयागराज क्षेत्रीय केंद्र के समन्वयकों की कार्यशाला का हुआ आयोजन

संवाददाता। प्रयागराज

2047 तक विकसित भारत की संकल्पना दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ही पूर्ण की जा सकती है। इसमें दूरस्थ शिक्षा माध्यम से जुड़े अध्ययन केंद्र समन्वयकों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बातें उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के कुलपति प्रो सत्यकाम ने शुक्रवार को प्रयागराज क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्गत आने वाले अध्ययन केंद्रों के समन्वयकों के लिए आयोजित नामांकन संवाद सम्पर्क एवं सम्मेषण विषय पर आयोजित कार्यशाला में कहीं।

प्रो सत्यकाम ने कहा कि दूरस्थ शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियाचन्यन की दिशा में अपना संपूर्ण योगदान दे रही है। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा की साक्षरता दर



को बढ़ाने में उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रदेश भर में फैले अपने अध्ययन केंद्रों के माध्यम से महती भूमिका निभा रहा है।

प्रो सत्यकाम ने कहा कि पाठ्य सामग्री के बिना दूरस्थ शिक्षा का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता। विश्वविद्यालय के सभी कार्यक्रमों में स्व अध्ययन सामग्री लेखन के कार्य में सभी शिक्षक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कुलपति ने छात्रों की समस्याओं के निदान के लिए ग्रीवांस पोर्टल के गठन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का लक्ष्य है कि प्रत्येक छात्र को प्रयोगशाला के माध्यम से उच्च शिक्षा की साक्षरता दर

विश्वविद्यालय के एक लाख प्रवेश के लक्ष्य को पूरा करने में अपना सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि सौधे संवाद से कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। समन्वयकों के सामने जो भी समस्याएं आएंगी। विश्वविद्यालय के उनका हर तरह से निदान प्रस्तुत करेगा।

इस अवसर पर प्रवेश प्रभारी प्रो जेपी यादव ने बताया कि विश्वविद्यालय ने इस सत्र से योग में डिप्लोमा और प्रमाण पत्र कार्यक्रम फिर से प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का लक्ष्य है कि कार्यक्रम एमए होम साइंस जनवरी 2025 में पुन प्रारंभ किया जाएगा। इस

विवक न्यूज

स्रोतों को जानने समझने और परखने की आवश्यकता: पांडेय

प्रयागराज। मध्यकालीन इतिहास विभाग सीएमपी डीपी कॉलेज के द्वारा शुक्रवार को भारतीय इतिहास लेखन: श्रोत सन्दर्भ और व्याख्या विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान के मुख्य वक्ता डॉ निराला कुमार पांडेय अतिथि के डॉ निराला इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च नई दिल्ली ने इतिहास लेखन इतिहास के स्रोत स्रोत का स्रोत देना काल परिस्थितियों में स्रोतों का प्रयोग तथ्य जो उभरी तक प्रकाश में नहीं आया उस तरह के तथ्यों के प्रयोग से क्या बदल सकता है पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इतिहास लेखन में हो वे होंगे ऑन होंगे ऑफ और सॉट लास्ट पद्धति के प्रयोग से बचना चाहिए। उन्होंने स्रोतों को जानने समझने और परखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया ताकि दूरे हुए इतिहास के उन पहलुओं को भी मुख्यधारा में लाया जा सके। जिन्हें इतिहासकारों ने या तो राष्ट्रीय इतिहास में कम स्थान दिया या फिर बिल्कुल ही गुला दिया। कार्यक्रम का उद्घाटन विभाग के संयोजक डॉ निराला कुमार सिंह ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉ शशिबाला द्वारा दिया गया। व्याख्यान के अवसर पर डॉ मुनींद्र कुमार शुक्ल डॉ अशिलेश कुमार यादव डॉ अरुण वर्मा डॉ रविन्द्र प्रताप सिंह डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव शोध छात्र विनय कुमार हिन्द अर्जुन पांडेय सागर वर्मा नीलाक्षी पांडे अतुल सिंह पटेल सरोत अनेक विद्यार्थी उपस्थित थे।

सांसद संगीता बलवंत ने उतरया अंधुऊ हवाई पट्टी का मुद्दा

गाजीपुर। आग बढत 2024-25 पर चर्चा में आग लोहे हुए कार्यक्रम सांसद डा. संगीता बलवंत ने अपने गृह जन्मपट को तरफ केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि गाजीपुर - थक मार्ग पर आवागमन अंधुऊ में द्वितीय दिव्य चंद्र के दौरान 63 एचड में हवाई पट्टी बनानी वर्य थी जो आज भी सक्रिय है। संगीता बलवंत ने सरकार की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना के तहत विमान सेवा स्थापित कराने की मांग रखी। साथ ही संगीता बलवंत ने कहा कि विमान सेवा शुरू होने से जन्मपट के साथ साथ जन्मपट मऊ, बलिया, आजमगढ़, चंदौली तथा सीमावर्ती बिहार प्रांत के कई जिले के लोगों को आवागमन हेतु सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा की पूर्ववर्ती सरकारों को आर्डन दिखाते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा कि आजादी के 67 साल 2014 से पहले संपूर्ण भारतवर्ष में मात्र 74 एयरपोर्ट थे। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 10 वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या में दोगुनी वृद्धि हुई और एयरपोर्टों की संख्या बढ़कर 148 से गई है।

विभिन्न मांगों को लेकर एनएचएम सविदा कर्मियों ने सीएमओ को सौंपा पत्र

संवाददाता। गाजीपुर

एनएचएम सविदा कर्मचारी जो अपने कई मांगों को लेकर पिछले 26 जुलाई से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ों में सविदा कर्मचारियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपनी मांगों से संबंधित एक पत्र सौंपा। सविदा कर्मचारी संगठन के जिला अध्यक्ष राधेन्द्र शेखर सिंह ने बताया कि उप्रराष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सविदा कर्मचारी संघ (रजि०) के बैनर तले प्रदेश भर के लगभग 1.50 लाख की संख्या में सविदा कर्मचारी संगठित हैं। समस्त सविदा कर्मचारियों द्वारा वैश्विक महामारी में शहर से लेकर गाँव तक समुदाय के अन्तिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा को पहुंचाने में जीवन तक कुर्बान करते हुये अतुलनीय योगदान दिया है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है।



महोदय स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम सविदा कर्मचारियों के भविष्य को सुदृढ़ करने हेतु आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया संगठन की समस्त 15 सूत्रीय प्रमुख जायज मांगों को लेकर पत्र सौंपा गया है। उन्होंने अपने मुख्य मांगों में म्यूचुअल एवं रिक्त पदों पर गैर जनपद स्थानान्तरण का अनुमोदन एवं सविदा कर्मचारियों हेतु भी प्रत्येक वर्ष स्वयं के अनुरोध पर गैर जनपद स्थानान्तरण नीति को लागू किया जाये। केन्द्र सरकार से उतर प्रदेश को आवंटित अतिरिक्त 3: प्राप्त बजट से

वेतन विसंगति का निस्तारण कर वेतन वृद्धि की जाये। बढ़ती हुई महंगाई के दृष्टिगत सविदा कर्मचारियों हेतु म्च, ग्रेड-पे। (महंगाई भत्ता) लागू किया जाये। प्रदेश के शेष 35 जनपदों के डाटा अपरेंटर को जिला स्वास्थ्य समिति में समायोजित किया जाये। पी०बी०आई०0 उनके मानदेय में जोड़ा जाये।(बिहार राज्य के अनुसार) नियमित पदों के सापेक्ष होने वाली भर्ती प्रक्रिया में स्टाॅफ नर्स की भौति अन्य समस्त सविदा कर्मचारियों को भी भारांक/वरीयता दिया जाये।

ट्रक चालकों की सुविधा के लिए बना विश्राम कक्ष

सोनभद्र। रेणुसगर पावर डिवीजन स्थित कोल गेट ट्रक पार्किंग एरिया में ट्रक चालकों की सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए यूनिट हेड आर पी सिंह द्वारा चालकों के उपस्थिति में पीता काट कर आराम कक्ष का उद्घाटन किया गया। यूनिट हेड ने चालकों को समझाते हुए कहा कि रेणुपावर प्रबंधन ने आप सभी के सुरक्षा का संदेव ध्यान रखा है, और यह आराम कक्ष आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसमें बैठने, सोने, स्नान इत्यादि की पूरी व्यवस्था है। आराम कक्ष होने से चालकों में बहुत ही प्रसन्नता है और इसकी भुर्रि भुर्रि प्रशंसा कर रहे हैं। इस अवसर पर एच आर हेड श्री शैलेश सिंह ने चालकों से कहा की जिस प्रकार आप लोग परिश्रम करते हैं, इसके लिए आराम कक्ष बहुत ही अच्छा रहेगा। इस मौके पर आर मृदुल भास्कराज, सिविल से शशिकांत, डी पी सिंह, सतनाम सिंह, कैप्टन रोहित पारसी, दुबे, ए डी पांडेय, सदानंद पांडे,सूरज, जैनुल आदि मौजूद रहे।

बिजली तारों के टकराने से प्रभावित हुए चार बच्चे, डीएम ने ली जानकारी



अम्बेडकर नगर। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने जनपद के तहसील जलालपुर क्षेत्र के थाना मालीपुर अंतर्गत स्थित ग्राम पंचायत टिकरी में 11000 वोल्ट के विद्युत तार व 440 वोल्ट के विद्युत तार के आपस में टकराने के कारण विद्युत स्पर्शाघात से प्रभावित बच्चा सत्यम पुत्र सतगुरु हाथीतोबा फुले संयुक्त जिला चिकित्सालय के बर्न वार्ड पहुंचकर चिकित्सकों से स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि उक्त घटना में कुल चार बच्चे प्रभावित हुए

थे, जिसमें से तीन बच्चों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां चिकित्सकों द्वारा उपचार के उपरांत स्वास्थ्य ठीक होने पर घर भेज दिया गया तथा सत्यम का जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। जिसके संबंध में चिकित्सकों द्वारा अवगत कराया गया है कि बच्चा पूर्ण रूप से ठीक है तथा बच्चे को इंफेक्शन से बचाव व सुरक्षा के दृष्टिगत अभी चिकित्सालय में चिकित्सकों के निगरानी में रखा गया है जिसे चिकित्सकों के अनुरूप सही होने पर घर भेज दिया जाएगा।

परीक्षा नियंत्रक ने किया विवि परीक्षाओं का औचक निरीक्षण

संवाददाता। गाजीपुर

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के नवागत परीक्षा नियंत्रक डॉ विनोद कुमार सिंह गुरुवार को विश्वविद्यालय परीक्षाओं का औचक निरीक्षण के क्रम में अलग-अलग परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इसी क्रम में वह स्नातकोत्तर महाविद्यालय भी पहुंचे। बताया चर्चे कि बी०ए०३ सेकेंड सेमेस्टर एवं अन्य विषयों के सेमेस्टर की परीक्षाएं वर्तमान में चल रही है। सुविधा पूर्ण परीक्षा संपन्न हो, इसके दृष्टिगत डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने संबद्ध कॉलेजों का औचक निरीक्षण किया।



गुरुवार को परीक्षाओं की तैयारियों और अन्य मामलों की जांच के क्रम में डॉक्टर विनोद कुमार सिंह पी० जी० कॉलेज भी पहुंचे। उन्होंने परीक्षा कक्ष का स्वयं निरीक्षण किया। प्रशासन के दौरान महाविद्यालय प्रशासन की ओर से परीक्षाओं के लिए की गई तैयारी की उन्होंने सराहना की। डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने पी० जी० कॉलेज

प्रशासन की ओर से सीसीटीवी कैमरे आदि की व्यवस्था को भी देखकर संतुष्ट दिखे। उन्होंने कहा कि पी जी कॉलेज की तरह ही जनपद के अन्य संबद्ध कॉलेजों को भी पारदर्शी तरीके से परीक्षा संपन्न करनी चाहिए। परीक्षा संबंधित सभी दस्तावेजों को नियमानुसार सुरक्षित रखा जाना चाहिए। जांच के क्रम में उन्होंने प्रश्न पत्र कोठार एवं उतर पुस्तिका कोठार का भी निरीक्षण किया। जांच में विनोद कुमार सिंह को सभी तैयारी मानक के अनुरूप लगी। इसके उपरांत परीक्षा नियंत्रक महाविद्यालय के शोध ग्रंथालय का

कार्यभार ग्रहण करने के बाद कुलपति प्रो. वंदना सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों की शिफ्टकार बैटुक आहुत की थी। परीक्षा नियंत्रक ने केन्द्रीय शोध ग्रंथालय का निरीक्षण किया। उन्होंने केन्द्रीय शोध ग्रंथालय में रखे आर्गंतुक संदेश पुस्तिका में अपना संदेश भी लिखा।

निरीक्षण के अंत में परीक्षा नियंत्रक को स्मृति चिन्ह देखकर प्राचार्य कक्ष में सम्मानित किया गया। पी जी कॉलेज में दूसरी पाली में हो रही परीक्षाओं का परीक्षा नियंत्रक द्वारा निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान प्राचार्य प्रोफेसर (डॉ०) राधेवेन्द्र कुमार पाण्डेय, प्रोफे० (डॉ०) एस० डी० सिंह, प्रोफे० (डॉ०) अवधेश सिंह, प्रोफे० (डॉ०) एस एन सिंह, डॉ० लवजी सिंह, डॉ० रामदुलारे, डॉक्टर योगेश कुमार, डॉक्टर अमरजीत सिंह, डॉक्टर धर्मेन्द्र, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र, अरूण कुमार सिंह के साथ ही परीक्षा विभाग से संबद्ध अन्य प्राध्यापक भी मौजूद रहे।

अधीक्षक की गैर मौजूदगी में चिकित्सकों की मौज ही मौज

मड्डिहान, मिर्जापुर। मड्डिहान कस्बे में स्थिति मड्डिहान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल वीर महावत के हाथी जैसे हो गया है। ज्यादातर स्वास्थ्य कर्मी मन्मानाी ढंग से कार्य करने पर उतारू हैं। पच्ची काटने वाले की जगह पर कूक कां कर रहा है। कूक के जगह पर सफाई कर्मी, मरीजों को अपने पच्ची पर स्त्री लिंग के जगह पुरूष लिंग, पुरूष लिंग के जगह पर स्त्री लिंग नाम प्राप्त हो रहा है। डाक्टरों के परामर्श के समय मरीजों को हलकानी हो रही है। सूत्रों की मांने तो सभी चिकित्सक सीएचसी पर मौजूद नहीं रहते। चिकित्सकों के गैरमौजूदगी के बावजूद भी हाजिर पंजिका उनके नामों से हस्तुत पाई जाती है। डाक्टर पंकज ज्यादातर गैरहाजिर रहते हैं। इनके नाम से हाजरी पंजिका हमेशा मेन्टेन पाया जाता है।मौजूद चिकित्सकों का गैर जिम्मेदाराना रवैया खुलेआम बाहर की दवा व जांच के लिए मरीजों को मजबूर कर दे रहा है। और आत्म यह है कि अस्पताल में जगह-जगह गंदगी देखी जा रही है।

जांच के कर्मरे की तरफ जाते समय मरीजों व तिमारादरों को नाक ढकना पड़ू है। अस्पताल में आसानी से फिन्टायल मुहैया होने के बावजूद भी छिड़काव नहीं कराया जाता । अस्पताल में मरीजों के साथ आये तोमारादरों को बिमारी की आंशका सताने लगती है। सफाई को लेकर एनम की प्रशिक्षण लेने वाली प्रशिक्षु शिकायत कर चुकी है। इन लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश किया गया था। कुछ प्रशिक्षु आधे में प्रशिक्षण छोड़ कर घर जाने के लिए तैयार हो गई थी। किसी तरह इस मामले को शांत कराया गया। बिना मुबिया के अस्पताल के कर्मचारियों में अपने जिम्मेदारियों को लेकर लापरवाही करते देखा जा रहा है। विगत कुछ माहों से सीएचसी के अधिक्षक पद का कार्य भार अपर चिकित्सा अधिकारी डॉ मुकेश यादव सम्भाल रखें है अपर चिकित्सा अधिकारी होने के कारण पूरे जनपद की चिकित्सा प्रबंधन व्यवस्था इनकी देखभाल पड़ती है। सीएचसी पर हमेशा उपलब्ध नहीं हो पाते।

आग लगने से झोपड़ी जलकर हुई राख 3 मैसों व 6 बकरियों की मौत



गाजीपुर। जनपद के नगसर थाना क्षेत्र के अवंती गांव में बीते गुरुवार की देर रात्रि को रीता देवी के एक निजी गोशाला में अज्ञात कारणों से आग लगने से झोपड़ी जलकर राख हो गई,जबकि आग की चपेट में आने से तीन भैंसे एवं छह बकरियां झुलझुल कर गईं। इस भीषण आगलगी में जानवरों का चारा,कपडा, आदि अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया, इस अगालगी में पंडित परिवार को करीब तीन लाख रूपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है,आग लगने को सूचना पर शुक्रवार को लेखपाल आशुतोष कुमार मौके पर पहुंचे नुकसान का सर्वे कर रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दिया। वहीं पंडित व ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे पशु चिकित्सक शशिभूषण कुमार ने मौके पर मृत पशुओं का पोस्टमार्टम किया,इसके बाद मृत जानवरों को सुरक्षित जगहों पर दफन कर दिया गया। अवंती गांव निवासी रीता देवी ने बताया कि वह रोज की तरह शाम को जानवरों को चारा खिलाते एवं दूध दूहने के बाद अपने निजी गोशाला में जानवरों को बांधने के बाद खुद भी भोजन कर सोने चली गईं, उन्होंने बताया कि इसी दौरान देर रात को शोर सुनकर जब वह कमरे से बाहर आई तो देखा की उसके निजी गोशाला की झोपड़ियां धू-धुंकर जल रही है। कई मशकत के करीब घंटे भर बाद आग पर काबू पाया जा नुकसान के सर्वे रिपोर्ट लेखपाल के द्वारा मिलते ही पीडित परिवार को जल्द सरकारी सहायता दी जाएगी।

वायनाड त्रासदी पर्यावरणीय चेतावनी

वायनाड त्रासदी पर्यावरणीय चेतावनी अनदेखा करने के खतरनाक नतीजे प्रदर्शित करती है। लेकिन भारत में दुर्भाग्य से त्योहारों से लेकर त्रासदी तक हर चीज के 'राजनीतिकरण' की बुरी आदत विकसित हुई है और इसका प्रयोग विरोधियों के खिलाफ अवसर के रूप में किया जाता है। केरल के वायनाड में त्रासद भूस्खलन से 170 से अधिक लोगों की जानें गई हैं, लेकिन इसका भी राजनीतिक प्रयोग हो रहा है। इसने राज्य और केन्द्र सरकार के नेताओं के बीच गर्मागर्म बहस को जन्म दिया है। इस त्रासदी में जीवन और संपत्ति का भारी विनाश हुआ है और इसने आपदा के लिए तैयारी तथा पर्यावरणीय अनदेखी जैसे मुद्दों को सामने ला दिया है। भूस्खलन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य सरकार को जल्दी चेतावनी मिल गई थी, पर वह आवश्यक बचाव के उपाय करने में विफल रही। उन्होंने लापरवाही के लिए राज्य सरकार की आलोचना करते हुए संकेत किया कि यदि समय पर कार्रवाई की गई होती तो अनेक लोगों को जीवन बचाया जा सकता था। इस पर केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने फौरन शाह के दावों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने सभी उपलब्ध चेतावनियों पर कार्रवाई की और उसने संभावित प्राकृतिक आपदा का प्रभाव कम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए थे। विजयन ने जोर दिया कि भूस्खलन की अभूतपूर्व विकरालता शीघ्र चेतावनियों के अनुमान से बहुत अधिक थी और राज्य के आपदा प्रबंधन बलों ने अथक रूप से स्थिति से निपटने के प्रयास किए। इस टकराव से कुछ हासिल नहीं हुआ। इससे न घायल लोगों को राहत मिली और न भविष्य में ऐसी घटनाओं को



रोकने के लिए किसी कार्ययोजना पर विचार हुआ। लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी से केन्द्र और राज्य सरकारों ने स्वयं को 'क्लीन चिट' देने का प्रयास जरूर किया।

यह त्रासदी आपदा प्रबंधन की चुनौतियों को उजागर करते हुए राज्य और केन्द्र सरकारों के बीच समन्वित प्रयासों की आवश्यकता रेखांकित करती है। वायनाड त्रासदी ने पर्यावरण संरक्षण तथा प्रकृति की अनदेखी पर व्यापक विमर्श की आवश्यकता भी उजागर की है। केरल सरकार इस बात की दोषी है कि उसने 'पश्चिमी घाटों' पर बेलगाम विकास की अनुमति दी है, जबकि यह देश का एक सर्वाधिक संवेदनशील परिस्थितिकी तंत्र है। बार-बार आने वाली विभीषिकाओं के बावजूद केरल सरकार 'विकास' के नाम पर गैर-टिकाऊ गतिविधियां जारी रखे हैं। इसके कारण भूमि प्रयोग बदलने से घना वृक्षाच्छादन नष्ट हुआ है। इसने सदाबहार जलधाराओं व नदियों को मौसमी बना दिया है तथा मानसून के मौसम में बाढ़ आने का खतरा बढ़ा है। वायनाड भूस्खलन पर्यावरणीय संकेतों की अनदेखी करने के खतरनाक परिणामों की चेतावनी है। निर्वनीकरण व अनियोजित निर्माण ने वायनाड जैसे क्षेत्रों में प्राकृतिक विभीषिकाओं का खतरा पैदा कर दिया है। वायनाड भूस्खलन आपदा प्रबंधन में जवाबदेही तथा सक्रिय कदमों का महत्व भी उजागर करता है। ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से यह हमारे पर्यावरण के सम्मान और देखभाल की आवश्यकता उजागर करता है। जंगल मिट्टी को स्थिर रखने तथा जल-चक्र को नियमित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका आपदा प्रबंधन में। निर्वनीकरण से परिस्थितिकी तंत्र बाधित होते हैं जिनसे भूस्खलन जैसी घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। वायनाड त्रासदी सरकारों, समुदायों और आम जनता का आह्वान करती है कि वे हम सबका अस्तित्व बनाए रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता प्रदान करें।

कौशल व रोजगार को प्राथमिकता

युवा सशक्तीकरण के लिए सरकार ने तीन परिवर्तनकारी योजनाओं की घोषणा की है। इनका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल का विकास करना है।



दिवेश सूद
(लेखक, कौशल संवर्धन क्षेत्र से संबद्ध हैं)



केंद्रीय बजट की नौ सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रोजगार एवं कौशल विकास को बढ़ावा देना है। इस दृष्टिकोण से कौशल विकास के लिए तीन योजनाओं की घोषणा की गई है। पहली योजना में उच्च कौशल संवर्धन पाठ्यक्रमों के लिए अधिकतम कर्ज प्रदान करना है। इसके लिए संशोधित 'आदर्श कौशल कर्ज योजना' लाई गई है जिसमें प्रति वर्ष 1.5 प्रतिशत के व्याज पर 1.5 लाख से लेकर 7.5 लाख रुपये तक कर्ज का प्राविधान किया गया है। इस योजना से युवाओं के सशक्तीकरण की उम्मीद है। इससे उनको उत्कृष्ट स्तर के कौशल पाठ्यक्रमों तक पहुंच बढ़ाई जाएगी। इससे योग्य छात्रों के सामने आने वाली वित्तीय बाधाओं काफ़ी सीमा तक हटाने तथा उम्मीदवारों को भविष्योन्मुखी और उद्योगों में वॉलेंट कौशल प्रदान करने में सहायता मिलेगी। इससे भविष्य के लिए तैयार और सशक्त कार्यबल तैयार होगा।

कौशल संवर्धन कर्ज बाजार में गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों-एनबीएफएस व माइक्रो-फाइनेंस संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए कौशल विकास एवं रोजगार मंत्रालय-एमएसडीई ने योजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। इस योजना में एनबीएफएस, माइक्रो फाइनेंस संस्थानों तथा छोटे फाइनेंस बैंकों को शामिल कर गारंटी के आधार पर कर्जों की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत कर्ज का 75 प्रतिशत हर साल 25,000 उम्मीदवारों को 7.5 लाख तक का कर्ज बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा। इसका अर्थ है कि सरकार अपनी ओर से ऐसे कर्जों की गारंटी लेगी। सरकार ने यह तथ्य स्वीकार किया है कि बिना जीवन कौशल कर्ज योजना से सरकार को नौजवान तथा इच्छुक उम्मीदवारों को आवश्यक वित्तीय समर्थन नहीं मिल पाता है जिसके कारण वे अपना कौशल संवर्धन तथा कौशल प्रशिक्षण नहीं प्राप्त कर पाते हैं।

सहज प्रवाह सुनिश्चित करने तथा कम आय वाले नौजवानों को विशेष कौशल पाठ्यक्रमों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एमएसडीई ने पहले जुलाई, 2015 में क्रेडिट गारंटी फंड योजना शुरू की थी, लेकिन यह योजना अपनी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी।

पिछले दशक में इस योजना के अंतर्गत पैसे का कम प्रयोग कर्ज का 1.5 लाख रुपये तक सीमित आकार था, हालांकि मुद्रास्फीति के कारण पाठ्यक्रमों का खर्च और फीस बढ़ी थी। इसके कारण बहुत से अधिक खर्च वाले पाठ्यक्रमों को योजना से बाहर रखना पड़ा था। इसके साथ ही सरकार-प्रायोजित योजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए निजी बैंकों में इच्छाशक्ति जगाना जरूरी था। 31 मार्च, 2024 तक पिछले दशक में इस योजना के अंतर्गत 10,077 कर्ज लेने वालों को केवल 115.75 करोड़ रुपये कर्ज ही दिया जा सका था। लेकिन नई माडल कौशल कर्ज योजना से सरकार को इस मुद्दे के प्रति अडिग प्रतिबद्धता प्रकट होती है जिसका उद्देश्य तेज गति से होने वाले तकनीकी परिवर्तनों को देखते हुए उच्च कौशल वाला कार्यबल तैयार करना है।

वर्तमान समय में मांग किए जाने वाले प्रासांगिक कौशल को प्राप्त करने का खर्च काफी अधिक है। तथाकथित कुशल कार्यबल का केवल 5 प्रतिशत ही औपचारिक रूप से प्रशिक्षित है। इससे

कौशल की कमी व्यापक रूप से सामने आती है जिसे तत्काल दूर किया जाना चाहिए। हालांकि, हर साल स्कूलों में 26.5 करोड़ बच्चे प्रवेश लेते हैं, पर उच्च शिक्षा तक पहुंचने पर उनकी संख्या घट कर केवल 4.3 करोड़ रह जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-एनईपी 2020 के अनुसार स्कूल शिक्षा पास करने वाले अतिरिक्त पांच करोड़ बच्चों को उच्च शिक्षा के दायरे में लाया जाना चाहिए। इसके लिए न केवल प्रत्येक व्यक्ति की कौशल शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए, बल्कि ग्रामीण भारत के छात्रों की बड़ी संख्या को इसके दायरे में लाना होगा।

इस कमी को दूर करने के लिए आदर्श कौशल कर्ज योजना न केवल एक समाधान है, बल्कि यह आवश्यकता और तात्कालिक कदम है। कौशल अर्थव्यवस्था लगातार बाजार-संचालित होती जा रही है जिनमें नए युग के शिक्षण को कौशल विकास परिस्थितिकी से जोड़ना जाता है। शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में नौजवान कौशल संवर्धन एवं आजीविका में सुधार के अवसरों की पहचान करते हैं। ऐसे में आदर्श कौशल कर्ज योजना जैसी पहल अपने दरवाजे अनेक कौशल पाठ्यक्रमों के लिए खोलती है जिसमें स्वास्थ्यरक्षा, सौंदर्य-बेहतर, आईटी, एआई-डेटा साइंस, क्लाउड प्रयोग, डिजिटल मार्केटिंग, अतिथि सत्कार क्षेत्र, एनीमेशन, गेमिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग तथा ड्रोन टेक्नोलॉजी शामिल हैं। उद्योगों

की बदलती गतिशीलता से संचालित ये पाठ्यक्रम बड़ी संख्या में नौकरियों के अवसर प्रदान करते हैं तथा वैश्विक स्तर पर नौकरियों की संभावनाएं खोलते हैं। इससे नौजवानों को भविष्य के दरवाजे खोलने तथा अंतरराष्ट्रीय कैरियर विकल्प खोजने में सहायता मिलती है।

दूसरी योजना का लक्ष्य अगले पांच साल में 20 लाख नौजवानों का कौशल संवर्धन करना है। कुल 60,000 करोड़ रुपये के आबंटन वाली इस योजना का लक्ष्य इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों-आईटीआई का 'हब एंड स्पोक' व्यवस्था के अंतर्गत उच्चिकरण करना है जिससे उन्मुखीकरण में सुधार होगा। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका लक्ष्य नौजवानों को विशिष्ट-उद्योग कौशल से सम्पन्न कर उन्को ज्यदा रोजगारों के उपयुक्त बनाना है। इसके लिए पाठ्यक्रम की विषयवस्तु व डिजाइन को उद्योगों की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप उच्चिकृत करना होगा। उदाहरण के लिए, उभरते आईटी क्षेत्र को साइबर सुरक्षा या डेटा विश्लेषण कौशलों की आवश्यकता है जिनको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। बजट में शामिल तीसरी योजना का उद्देश्य युवाओं को समग्र रूप से कौशल प्रदान करना है ताकि नौजवानों को सर्वोच्च 500 कंपनियों में इंटरशिप के अवसर मिल सकें। इस प्रकार की पहली योजना में अगले पांच साल में एक करोड़

नौजवानों को शामिल किया जाएगा। यह नौजवानों में बेरोजगारी समस्या का समाधान करने में गेमचेंजर हो सकती है। इस इंटरशिप योजना का खोजी दृष्टिकोण और संभावित प्रभाव इसे युवा जनसंख्या को भावी रोजगार दिलाने में प्रकाश की किरण जैसा है। इससे युवा बेरोजगारी दरों में काफ़ी कमी आने की उम्मीद है। लेकिन इंटरशिप करना कठिन है क्योंकि इससे निराशा और हताशा का दुष्क्र पैदा हो सकता है। एमबीए, इंजीनियरिंग, आदि पेशेवर डिग्री वाले छात्रों को स्नातक के बाद अच्छी नौकरियां व इंटरशिप प्राप्त करने में आसानी होगी। लेकिन यह परिदृश्य उन स्नातकों के लिए ज्यदा कठिन होगा और उनको नौकरियों के अयोग्य बनाएगा जो मानविकी विषयों से स्नातक होंगे और उनके पास बाजार के उपयुक्त तत्काल कोई कौशल उपलब्ध नहीं होगा।

प्रमुख कंपनियों में विभिन्न विषयों में शिक्षित युवा स्नातकों को इंटरशिप प्रदान करने वाली यह योजना एक 'गेम चेंजर' के साबित हो सकती है। लेकिन इसके लिए योजना का समुचित व प्रभावी क्रियाव्यवहन बहुत जरूरी होगा। इसके लिए बड़ी कंपनियों को मजबूत इच्छाशक्ति दिखानी होगी और सरकार को इसके लिए उनको प्रेरित करना होगा। शायद भविष्य में सरकार इस योजना का दायरा बढ़ाने और कंपनियों के लिए इंटरशिप देना अनिवार्य रूप से कर विचार कर सकती है। कम से कम यह एक आकार से बड़ी कंपनियों के लिए अनिवार्य किया जा सकता है। सरकार इस उद्देश्य से कुछ विशिष्ट मानक भी निर्धारित कर सकती है।

कंपनियां अपने कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड-सीएसआर के अंतर्गत हर साल निश्चित संख्या में इंटरने लेने की व्यवस्था कर सकती हैं। इस फंड से वे इंटरशिप के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की फंडिंग कर सकती हैं। ये फंड कंपनियों की पहल पर पर्यावरणीय व सामाजिक बेहतरों के लिए खर्च किए जाते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली इंटरशिप से नौजवानों में नौकरियां प्राप्त करने की क्षमता बढ़ेगी। इस दौरान प्राप्त अपने सटीक अनुभव के आधार पर वे रोजगार प्राप्त करने में सफल होंगे। लेकिन रोजगार व नौकरी योग्य कौशल प्रदान करने में योजना का क्रियाव्यवहन, प्रभावशीलता व जवाबदेही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी।

भारत का संतुलनकारी राजनय

“
भारत सरकार पिछले महीने राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की बैठक के बारे में अमेरिका और यूरोपीय चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रही है।
”



कुमारादीप्टी बनर्जी
(लेखक नीति विश्लेषक हैं)

एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश में, भारत सरकार पिछले महीने राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की बैठक के बारे में अमेरिका और यूरोपीय चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रही है, जब कई नेता नाटो शिखर सम्मेलन के लिए वॉशिंगटन में एकत्रित थे। राष्ट्रपति पुतिन ने मास्को में पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए एक अतिरिक्त कदम उठाया, जो भारत के साथ दीर्घकालिक साझेदारी के बारे में अमेरिका को एक मजबूत संदेश देता है।

अमेरिका में वरिष्ठ अधिकारियों ने पीएम मोदी की मास्को यात्रा में शामिल दिखावे पर गहरी चिंता व्यक्त की, जबकि

उन्होंने दोहराया कि कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल नहीं हुआ। रूस के साथ द्विपक्षीय संबंध एक कठिन रस्सी हैं, जिस पर भारत पिछले दशकों में अमेरिका के साथ अपने बढ़ते जुड़ाव के बावजूद सावधानी से चलने में कामयाब रहा है। इसलिए, इस सप्ताह टोक्यो में क्राइड विदेश मंत्रियों का सम्मेलन, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात की, महत्वपूर्ण था। संयुक्त बयान में स्पष्ट शब्दों में यूक्रेन में रूस की कार्रवाई की निंदा की गई, शायद पहली बार इस तरह के बहुपक्षीय आधिकारिक संचार में शामिल हुआ।

संयुक्त बयान में कहा गया, हम यूक्रेन में चल रहे युद्ध और उसके भयानक और दुःखद मानवीय परिणामों पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। हम अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप व्यापक, न्यायसंगत और स्थायी शांति की आवश्यकता को दोहराते हैं, जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान सहित संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और



सिद्धांतों के अनुरूप हो। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठकों और बाद में सार्वजनिक संदेशों में भी युद्ध के मैदान से दूर यूक्रेन संकट की स्थायी समाधान खोजने की आवश्यकता न्यायसंगत और स्थायी शांति की आवश्यकता को दोहराते हैं, जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान सहित संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और

सिद्धांतों के अनुरूप हो। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठकों और बाद में सार्वजनिक संदेशों में भी युद्ध के मैदान से दूर यूक्रेन संकट की स्थायी समाधान खोजने की आवश्यकता न्यायसंगत और स्थायी शांति की आवश्यकता को दोहराते हैं, जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान सहित संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और

पीएम भू-राजनीतिक गतिशीलता को संतुलित करने और भारत और यूरोप के संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए अगस्त में यूक्रेन की यात्रा कर सकते हैं। इस बीच, क्राइड विदेश मंत्रियों की बैठक में गाजा संकट और लाल सागर क्षेत्र में इसके फैलाव पर ध्यान केंद्रित करना जारी रहा, जिससे लोगों के जीवन पर असर पड़ रहा है और माल ढुलाई को लागत बढ़ रही है।

विदेश मंत्रियों ने संयुक्त रूप से संवाद किया, हम सभी पक्षों से अंतरराष्ट्रीय कानून, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून भी शामिल है, का पालन करने का आग्रह करते हैं। हम यूएनएससी संकल्प का स्वागत करते हैं और सभी संबंधित पक्षों से सभी बंधकों को रिहाई और तत्काल युद्धविराम की दिशा में तुरंत और लगातार काम करने का आग्रह करते हैं।

हम सभी पक्षों से सहायता कर्मियों सहित नागरिकों के जीवन की रक्षा करने और मानवीय राहत के नेजी से परिवहन की सुविधा के लिए हर संभव कदम

उठाने का आह्वान करते हैं। हम इंडो-पैसिफिक सहित अन्य देशों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि वे जमीन पर गंभीर मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाएं। हम इस बात पर जोर देते हैं कि गाजा पट्टी के भविष्य की बहाली और पुनर्निर्माण को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थन दिया जाना चाहिए। हम दो-राज्य समाधान के हिस्से के रूप में इजरायल की वैध सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक संपृक्त, व्यवहार्य और स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें इजरायल और फिलिस्तीनियों दोनों को न्यायपूर्ण, स्थायी और सुरक्षित शांति में रहने में सक्षम बनाना है।

भारत इस साल होने वाले क्राइड नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, हालांकि, नवंबर में होने वाले महत्वपूर्ण अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव इस समय के प्रमुख निर्धारक होंगे। राष्ट्रपति बिडेन जिन्होंने अतीत में ज्यदातर क्राइड कथा को आकार दिया है, वे चार के इस समूह पर एक स्थायी छाप छोड़ना चाहेंगे।

आप की बात

कोटे के भीतर कोटा

सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण में उपश्रेणियां बनाने, यानी कोटे के भीतर कोटा बनाने की अनुमति रण्यों को दे दी ताकि इन वर्गों में अधिक पिछड़ी जातियों को लाभ मिले। यह फैसला आरक्षण व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव डालेगा। सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ में 6:1 के बहुमत से दिए गए फैसले से जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने असहमति व्यक्त करते हुए रण्यों को यह अधिकार देना गलत माना। एससी-एसटी में भी ओबीसी की तरह क्रीमी लेयर लागू करने और आरक्षण को एक पीढ़ी तक सीमित करने जैसे अलग-अलग सुझाव दर्ज भी बहुमत से फैसला देने वाले न्यायाधीशों द्वारा दर्ज कराए

गए। क्रीमी लेयर व आरक्षण एक पीढ़ी तक सीमित करने जैसे सुझावों को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। आरक्षण का यही सबसे बड़ा पहलू है कि आजादी के बाद से ही आरक्षण का फायदा उठाने वाले अब भी आरक्षण को यथावत जारी रखना चाहते हैं। इसी वजह से आरक्षण का 75 प्रतिशत से अधिक फायदा आरक्षित वर्गों के ही गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है। हालांकि, वोटबैंक राजनीति के चलते अब भी अधिक संख्या वाली दलित जातियों को पहले की तरह अधिक लाभ मिलने तथा कम संख्या वाली दलित जातियों को वंचित रहने की आशंका बनी हुई है।

सुभाष बुडवान वाला, रतलाम

कमला हैरिस को बढ़त

एक जनमत सर्वेक्षण के अनुसार, डेमोक्रेटिक अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस ने सात स्विंग राज्यों में से छह में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ बढ़त हासिल की है। कमला हैरिस का नाम सामने आने के बाद से ट्रम्प एक तरह से बचाव की मुद्रा में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि हैरिस पहले स्वयं को भारतीय मूल की महिला के रूप में पेश करती थीं, पर अब वे अश्वेत के रूप में सामने आ रही हैं। कमला हैरिस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ट्रंप को जो कुछ कहना हो, हमारे सामने कहे और राष्ट्रीय बहस में हिस्सा लें। मजेदार बात है कि जो ट्रंप पहले बाइडेन को बहस के लिए चुनती देते थे, अब इससे कन्नी काट रहे हैं। उनको अहसास हो गया है कि भावी प्रथम अमेरिकी अश्वेत महिला के रूप में कमला हैरिस का पलड़ा उनसे लगातार भारी होता जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी की गर्भपात-विरोधी और आप्रवासी-विरोधी नीतियों के कारण अमेरिकी जनता का वही वर्ग और ज्यदा मजबूती के साथ कमला हैरिस के साथ आ रहा है जिसने जो बाइडेन को विजय दिलाई थी।

- जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

आरक्षण की सीमा

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पंजज मिथल का विचार है कि आरक्षण केवल पहली पीढ़ी तक ही मिलाया जाए। अगर कोई पहली पीढ़ी आरक्षण लेकर उच्च स्तर पर पहुंच गई है तो उसको इसका हकदार नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह बात एससी-एसटी आरक्षण के कोटे में कोटा पर सुप्रीम कोर्ट में जजों के पेनल में हिस्सा लेने के दौरान कही। उनकी बात सही और तार्किक भी है। जिन्हें वोटबैंक आरक्षण का लाभ मिल चुका है और वे व उनका परिवार उसे पाकर सक्षम हो चुका है और यह लाभ अब उनकी ही जाति के दूसरे वंचित लोगों को मिला चाहिए। ऐसा न होने पर सक्षम लोग ही अपने लोगों को नुकसान

पहुंचाते हैं। आरक्षण नीति में कुछ ऐसे परिवर्तन होने चाहिए जिसमें अधिक से अधिक लोगों को आरक्षण का लाभ देकर सक्षम बनाया जा सके। संविधान निर्माता डा. भीमराव आंबेडकर ने भी आरक्षण के जरिये अधिक से अधिक लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने की बात कही थी। उन्होंने कुछ मामलों में आरक्षण 10 वर्षों तक रखने का सुझाव दिया था। लेकिन अब आरक्षण के इसकी सीमा और बढ़ने का मतलब मंडरा रहा है। यह स्थिति समाज कल्याण के बजाय निहित स्वार्थों को बढ़ावा देगी।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ अराजक युवाओं द्वारा स्कूटर सवार व्यक्ति व महिला पर गंदा पानी फेंकने और महिला के साथ छेड़खानी करने की घटना सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कठोर कदम उठाया है। उन्होंने क्षेत्र के डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और एसीपी का ट्रॉसफर करने के साथ थाना इंचार्ज और पुलिस चौकी के सभी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। कैमरों में दिखने वाले सभी अराजक व बेलगाम युवाओं को गिरफ्तार किया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री और यूपी पुलिस प्रशासन

की सहायता की जानी चाहिए। यूपी पुलिस की कार्रवाई अपनी जिम्मेदारी न निभाने वाले पुलिस कर्मियों तथा अराजक शहरी युवाओं के लिए सबक है। योगी आदित्यनाथ का यह कठोर कदम उन विपक्षी राजनेताओं के लिए भी सबक है जो युवाओं को बहका कर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब कर मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार की छवि खराब करना चाहते हैं। विपक्षी दलों को ऐसी घटना हरकतों से बचना चाहिए, नहीं तो 2027 में उनका फिर पूरी तरह सफाया हो जाएगा।

-वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

कांवड़ यात्रा ले जा रहे युवक की हादसे में मौत दो गंभीर रूप से घायल



● पुलिस अधीक्षक ने किया घटनास्थल का दौरा

मोहम्मदी खीरी। सीतापुर के महोली से मोटरसाइकिल पर सवार होकर छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ के लिए कावड़ यात्रा लेकर निकले एक युवक की पिकअप से टकरा में घटना स्थल पर मौत हो गई है वहीं पीछे बैठे दो लोगों

के गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस उपाध्यक्ष दलबल के साथ मौके पर पहुंचे तथा उसके उपरान्त पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक ने परिवार वालों से वार्ता की, तथा शव को मोहम्मदी सीएचसी पहुंचाया जहां से पोस्टमार्टम हेतु लखीमपुर भेजा गया, प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि चौकी अमीरनगर के अंतर्गत विपरीत दिशा से आ रहे पिकअप से मोटरसाइकिल

सवार आकाश कश्यप पुत्र राजकुमार 22 वर्ष की मौके पर मौत हो गई वहीं पीछे बैठे शिवा व रितिक कश्यप गंभीर रूप से घायल हो गए मटका आकाश का पंचनामा वर्कर पोस्टमार्टम के लिए लखीमपुर भेजा गया है दोनों घायलों को समुचित इलाज के लिए मोहम्मदी से लखीमपुर रेफर किया गया है, तीनों सीतापुर के महोली के निवासी हैं पिकअप को कब्जे में ले लिया है।

बेतवा नदी के स्लैब मरम्मत का कार्य झूल रहा है लोनिवि व सेतु निगम के बीच

● मरम्मत नहीं हुई तो कभी भी हो सकता है बड़ी घटना, एसई ने कहा कि करेंगे बातचीत

हमीरपुर। सरीला तहसील के बेतवा नदी में बना जलालपुर पथरखु गांव के पुल की खुली स्लैब की मरम्मत का कार्य लोनिवि व सेतु निगम के मध्य इधर उभर झूल रहा है दोनों विभाग के अभियंता इसके लिये एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लिहाजा दो दिन से मरम्मत न होने से कभी कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। तहसील सरीला के जलालपुर गांव के पास बेतवा नदी पर बने पुल की स्लैब के सरिया निकल आने से आने जाने वाले वाहनों के लिए तो खतरा उत्पन्न हो ही गया है साथ ही पुल के भी दरकने की आशंका बढ़ गई है यह पुल करीब पंद्रह साल पहले सेतु निगम ने निर्माण कराया था। पुल की



लंबाई एक किलोमीटर से अधिक है। करोड़ों रुपये की लागत से यह पुल बनाया गया था। पुल की जगह जगह स्लैब खुलने लगी है। पुल की स्लैब पिछले साल भी खुल गयी थी मगर किसी तरह जद्दोजेहाद के बाद सेतुनिगम ने मरम्मत करा दी थी। इधर दो दिन पहले पुल की स्लैब फिर से खुल गयी है। लोनिवि निर्माण खंड दो के सहायक अभियंता राधेश्याम गुप्ता का कहना है कि पुल की मरम्मत का काम सेतुनिगम द्वारा कराया जायेगा। लोनिवि के अधीक्षक अभियंता ने दो मर्तवा पत्र भी सेतु निगम को लिखा है। जोरकर कहा कि मरम्मत का काम सेतु निगम ही करायें। सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक आम्नाब रसूल का कहना है कि उनका काम पुल बनाकर संबंधित विभाग को हैंडओवर करना है।

एआरपी के गोली मारने में आरोपी शिक्षक गिरफ्तार



● आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से घटना में प्रयुक्त तमंचा आदि सामान भी पुलिस ने बरामद किया है।

फर्रुखाबाद। एआरपी को गोली मारने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से घटना में प्रयुक्त तमंचा आदि सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। पता चला की आरोपी बोते लगभग दो सालों से एआरपी विश्राम सिंह को रास्ते से हटाने की योजना बना रहा था। थाना जहांगंज के रूनी चुरसई निवासी विश्राम सिंह को कमालगंज खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पेट में एक महिला के कपड़े पहने आरोपी में गोली मार दी थी। विश्राम सिंह के भाई विजय सिंह ने घायल के साथी वीरेंद्र सिंह राजपूत निवासी गीतापुरम कालोनी फोहगढ़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस कई पहलुओं पर जाँच कर रही थी। पुलिस लाइन में एसपी अलोक प्रियदर्शी ने प्रेसवार्ता में खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी वीरेंद्र राजपूत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

आरोपी की निशानदेही पर 2 तमंचा 315 बोर, 5 जिंदा कारतूस 315 बोर, 1 मिस कारतूस 315 बोर, 2 दुपट्टा, 1 कुर्ती, 1 लैंगी, अंडर

बताया कि आरोपी पत्नी से आये दिन विवाद के चलते बीते लगभग दो सालों से विश्राम सिंह को रास्ते से हटाने की योजना बना रहा था। एक बार उसने मार्ग दुर्घटना की योजना बनायी, कामयाबी नहीं मिली। उसने पिन्नी अंदाज में विश्राम सिंह को महिला बनकर गोली मार दी।

एमजीनॉ से 2022 में खरीदा था महिलाओं का बिग

आरोपी ने 18 अक्टूबर 2022 को महिलाओं का बिग एमजीनॉ से 3,999 में खरीदा था। जिसकी फैन डिटेल भी पुलिस को आरोपी के मोबाइल से मिली है। आरोपी ने यूट्यूब पर पुलिस कैसे चेक करती है लोकेशन यह भी 12 जुलाई को खोजा था। पुलिस से मोबाइल में रिकार्ड बरामद किया है। खुलासे के लिए चार टीमों का गठन किया गया था। आरोपी की गिरफ्तारी साक्ष्यों के आधार पर की गयी। पुलिस अभिरक्षा में आरोपी ने अपने जुम में अडकाल किया है।

2 साल से बना रह था योजना

एसपी आलोक प्रियदर्शी ने

सीडीओ ने की काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस कार्यक्रम के संबंध में बैठक

कानपुर देहात। डीएम आलोक सिंह के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन. की अध्यक्षता में काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस से संबंधित कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में बैठक मुख्य विकास अधिकारी कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि ऐतिहासिक घटना काकोरी ट्रेन एक्शन के शताब्दी समारोह अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिसके अंतर्गत शहीद स्मारक पर माल्यापण/पुष्पांजलि, शहीद स्मृति यात्रा, वृक्षारोपण, शहीद परिवारों का सम्मान व अन्य संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि समय अंतर्गत



सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाए। काकोरी ट्रेन एक्शन कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रमों जैसे भाषण, पेंटिंग, लोको डिजाइन, निबंध प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाय।

जूनियर शिक्षकों का स्कूल हेल्थ एवं वैलनेस प्रशिक्षण

पुखराया, कानपुर देहात। आयुष्मान भारत के अंतर्गत विकासखंड अमरीधा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमरीधा में आयोजित पांच दिवसीय स्कूल हेल्थ एवं वैलनेस प्रशिक्षण संपन्न हुआ। जिसके पांचवें दिन शुक्रवार को मास्टर ट्रेनर दिनेश बाबू ने किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किशोरावस्था में बच्चे असहज महसूस करते हैं। प्रशिक्षण में यह भी बताया गया कि प्रत्येक जूनियर एवं प्राथमिक विद्यालय से दो हेल्थ एवं वैलनेस एम्बेसडर प्रशिक्षित किए जाएंगे। प्रशिक्षित एम्बेसडर अपने विद्यालय के प्रत्येक कक्षा से दो मैसेंजर एक बालक और बालिका को नियुक्ति करेंगे। सप्ताह में एक बार स्वास्थ्य संबंधी गतिविधि कराई जाएगी। बताया गया कि बच्चों को भूखपान से बचाएं। बच्चे सोशल मीडिया एवं इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग करें। कम से कम प्रयोग करें योग और व्यायाम के माध्यम से बच्चों के अंदर स्वस्थ जीवन की शैली को बढ़ाने का प्रयास किया



प्रशिक्षार्थी शिक्षक एवं प्रशिक्षक

जाए। मास्टर ट्रेनर डॉक्टर गिरिराज सिंह ने बताया गया कि बच्चों के अंदर व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाए। उन्हें प्रेरित किया जाए कि जंक फूड का सेवन न करें। बच्चों को बैलेंस डाइट के बारे में बताया जाए। जिससे बच्चे स्वस्थ और निरोगी हो सकें। परिषदीय विद्यालयों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जाने वाली आयरन फेलिक एसिड की गोली बच्चों को सासाह में एक बार अनिवार्य रूप से खिलाई जाए। और अलका शर्मा, संदीप कुमार, मोहम्मद साबिर ए अब्दुल वाजिद अंसारी उपस्थित रहे।

किसान अब 10 अगस्त तक करा सकते हैं फसलों का बीमा

लखीमपुर खीरी। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की अंतिम तिथि बढ़कर 10 अगस्त कर दी है। पहले यह तिथि 31 जुलाई थी। अब जिले के ऋणी एवम गैर ऋणी किसान भाई 10 अगस्त तक फसलों का बीमा करा सकते हैं। यह जानकारी सीडीओ ने दी। सीडीओ ने किसान भाइयों से अनुरोध करते हुए कहा कि अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुये योजना का लाभ लें। ऋणी किसान अपने बैंक शाखा से संपर्क कर यह सुनिश्चित कर लें कि बैंक शाखा द्वारा उनका फसल का बीमा किया गया है अथवा नहीं। बैंक शाखा को सूचित कर दे तथा गैर ऋणी कृषक आधार काई, स्व प्रमाणित फसल बुवाई का घोषणा पत्र, खातीनी की नकल, पासबुक की छायाप्रति (आईएफएससी कोड) के साथ कामन सर्विस सेंटर, बैंक शाखा से फसल पर देय प्रीमियम अंश को जमा करते हुये अधिसूचित फसल धान, मक्का, मूंगफली एवं उर्द आदि का बीमा करा सकते हैं।

विवक न्यूज

पंचायत उप निर्वाचन हेतु मतदान कार्मिकों को दिया प्रशिक्षण
कानपुर देहात। जिला मजिस्ट्रेट/डिप्टील निर्वाचन अधिकारी के निदेशन में सहायक निर्वाचन अधिकारी अजीत पांडेय की अध्यक्षता में पंचायत उप निर्वाचन नैया विकासखंड के ग्राम पंचायत अरिवाल न्यूजी एण्ड रसूलबाद के ग्राम पंचायत इटौली में प्रदान पर हेतु दिनांक 6 अगस्त को होने वाले निर्वाचन हेतु मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम नौ मुकेश्वरी डी.एस.नागर कक्ष कलेक्टर में सप्न हुआ। प्रशिक्षण में निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार मतदान प्रक्रिया समझ करये जाने हेतु सभी को निर्देशित किया गया। सभी मतदान कार्मिक प्रशिक्षण में दिये गये निर्देशों का तब प्रतियत अनुपालन सुनिश्चित करेगे। पोलिंग पार्टियां 5 अगस्त को रवाना होंगी। इस मौके पर मास्टर ट्रेनर सहित मतदान कार्मिक आदि उपस्थित रहे।

सीडीओ के औचक निरीक्षण ने चार अधिकारी

हमीरपुर। आग सीडीओ चंद्रशेखर शुक्ला ने विकास गवर्न की औचक निरीक्षण किया जिसमे चार अधिकारी व चैटर्नर्नली गायब पाये गये सभी का अभिमान अटोदो तक बेतन रोकने की कार्यवाही की गयी है।जानकारी के मुताबिक सीडीओ ने देस बजकर दस मिनट के बाद विकास गवर्न का निरीक्षण किया जिसमे जिला कृषि अधिकारी अ.इ.ए.सी.डी.सी.डी.पी.आई.सी. सिद्धार्थ, कृषि रक्षा अधिकारी, अपर जिला कृषि अधिकारी गैर संचित पाये गये इसी प्रकार चैटर्नर्नली भी गायब पाये गये नेसही का बेतन रोकने की संसुति कर दी गयी है। बताया जाता है कि विकास गवर्न से अधिकारी अधिकारी गायब रहते है यत तक कि तीन को तक ज्यादातर आभिष खाली हो जाते है। कर्नवाही तो अधिकारी से पहले ही जाते गये है जिससे दूर दराज से आने वाली जनता निराश होकर वापस लौट जाती है। अधिकारियों के त रहने से शासन की छवि खराब हो रही है। हालांकि कई नर्तव अधिकारी छापा गया है मगर कोई सुधार नहीं हो पा रहा है।

परिवार रजिस्टर में फर्जी नाम दर्ज करने पर सचिव निर्वाचित

सुनेरपुर। परिवार रजिस्टर में हेराफेरी करके फर्जी नाम दर्ज कर नकल जारी करने के आरोप में गांव के बाद जिला विकास अधिकारी ने देखा के ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया है। जिला विकास अधिकारी अजीत कुमार श्रीवास्तव ने ग्राम पंचायत देहा में तैनाती के दौरान ग्राम विकास अधिकारी रामसेवक दास पंचायत के परिवार रजिस्टर में कटिंग करके फर्जी ढंग से नाम दर्ज कर परिवार रजिस्टर की नकल जारी कर देते पर गांव के बाद निलंबित करके कुदारा विकासखंड में संबद्ध किया है। बताया है कि पंचायत सचिव ने जिसे फर्जी ढंग से परिवार रजिस्टर की नकल जारी की है। उसने फर्जी ढंग से वास्तव करकर करोड़ों रुपए की मुक्ति हप्त ली है। इसकी जांच करती जा रही है। इस प्रकार में राजस्व कमी भी संभावित बताए जा रहे है। बताया है कि 2022 में पंचायत सचिव ने परिवार रजिस्टर में फर्जीवाडा करके गांव निवासी सतीश श्रीवास्तव की जमीन पर कब्जा कराने का प्रयास किया था। इसकी शिकायत सतीश श्रीवास्तव ए नानसिंह यादव देवीदीन प्रजापति टीपू तिवारी शशुक्त तिवारी आदि ने जिलाधिकारी से की थी जांच के बाद मजाल सही पाए जाने पर अत्र कार्यवाही का सिलसिला शुरू हुआ है।

शराब की दुकान से किशोरी, युवक व संचालक धर दबोचे गए

फर्रुखाबाद। पुलिस ने कथित हुकाब बार से किशोरी व युवक के साथ ही दुकान मालिक को उतारा है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है शहर कोटवाली क्षेत्र के रेवेन्यू सेट्ट रिपत एक कथित हुकाब बार से एक किशोरी व उसके साथी युवक के साथ पकड़ा। पुलिस ने दुकान मालिक को भी उतारा है। पुलिस के पहुंचने पर हड़कंध मच गया। तीन माह पूर्व भी पुलिस ने दी थी दबिश शहर कोटवाली में मोहल्ला ओटी कोठाना इन्टी छरित हुकाब बार में दबिश देकर कई युवकों को हुकाब गुडगुडो पकड़ा था। पुलिस को यही से ही एक बोटी में हुकाब बार से सम्बन्धित सामान भी बरामद हुआ था। रेवेन्यू सेट्ट की प्रभारी रमेश गौतम ने बताया कि बालिका और युवक को पकड़ा गया है। दुकान संचालक भी पुलिस के कब्जे में है। पुलिस जांच कर रही है। शहर कोटवाल जेपी शर्म ने बताया कि जांच की जा रही है। जांच के बाद कार्यवाही पर विचार होगा।

जिला सेवायोजन कार्यालय द्वारा करियर काउन्सिलिंग कार्यशाला का हुआ आयोजन

कानपुर देहात। जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशन में जिला सेवायोजन कार्यालय कानपुर देहात द्वारा केन्द्रीय विद्यालय माती अकबरपुरए कानपुर देहात में छात्र-छात्राओं के लिए ऑन लाइन करियर काउन्सिलिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया। काउन्सिलर भारतीया वायु सेना के विंग कमांडर ए. गुणशेकर कर्माडिआ ऑफिसर, 3 वायु सैनिक परवन केन्द्र वायु सेना स्टेशन चकरी कानपुर द्वारा भारतीय वायु सेना की अभिनय योजना के तहत अगिनवीर वायु के रूप में भर्ती किये जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन कैरियर काउन्सिलिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया।

सीज डंपो से हो रही मौरंग की चोरी, प्रशासन को नहीं लग पाती मजक

फतेहपुर। खखेरू थाना क्षेत्र के अंतर्गत कई स्थानों पर सीज पड़े मौरंग के डंपो से आए दिन मौरंग चोरी हो रही है। जिसकी भनक प्रशासन को भी नहीं लग पाती है। जिससे खनन माफियाओं के हाँसेले बुलंद हैं और रात भर चोरों का सिलसिला चलता है। बताया है कि बारिश के मौसम में मौरंग खदानों के बंद होने से पहले मौरंग माफियाओं द्वारा बड़ी मात्रा में जगह-जगह मौरंग के डंप लगाए जाते हैं। जिनका खनन विभाग की ओर से चालान व कार्रवाई की जाती है। तहसील क्षेत्र के कबरे, घरवासीपुर, मोईउडीनपुर मोड़ समेत अन्य स्थानों पर लगे मौरंग डंपों पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए उन्हें सीज कर दिया था। सूचों के अनुसार सीज मौरंग को भी माफिया नहीं छोड़ रहे हैं और प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में वाहन सहित जेसीबी मौरंग डंप स्थल पहुंच जाते हैं और रात भर मौरंग चोरी का सिलसिला जारी रहता है। शायद अब तक खनन समेत पुलिस विभाग को इनकी भनक नहीं लग सकी है।

जिलाधिकारी ने खरीफ गोष्ठी व तिलहन मेले का किया शुभारंभ

● मिलेट्स, तिलहन व दलहन प्शलों के मिनीकित व मृदा स्वास्थ्य कार्ड का करारा वितरण

फतेहपुर। शुक्रवार को प्रेक्षागृह सभागार में जनपद स्तरीय खरीफगोष्ठी के साथ कृषि सूचना तंत्र के सुदृष्टीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद स्तरीय किसान मेला, त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के अंतर्गत खरीफ गोष्ठी व नेशनल मिशन आन एडिडविल आयल योजना के अंतर्गत खरीफ तिलहन मेले का आयोजन किया गया। इन्डुमती की अध्यक्षता में किया गया। डीएम के अलावा सीडीओ, अपर जिलाधिकारी न्यायिक, उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी ईईसी सहित तमाम अधिकारियों व प्रगतिशील किसानों ने हिस्सा लिया। गोष्ठी में

विभिन्न विभागों द्वारा स्टाल लगाए गए। डीएम ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उप कृषि निदेशक राम मिलन सिंह परिहार ने संचालन करते हुए कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर अधिकारियों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। डीएम ने कृषकों से सीधा संवाद स्थापित करते हुए अग्रगत कराया कि फसल क्राप कैलेंडर को कृषकों की मांग के अनुसार 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक शासन द्वारा विस्तार कर दिया गया है। कृषकों की उर्वरक की अधिक मांग के दृष्टिगत जनपद में अधिक केले के उत्पादन को देखते हुए केले की फसलों के क्षेत्रफल में जोड़कर शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। जिससे कृषकों की मांग के अनुसार गत वर्ष की अपेक्षा वर्तमान वर्ष में अधिक उर्वरक जनपद को उपलब्ध होगा। डीएम ने विद्युत समस्या के निदान हेतु अग्रगत कराया कि 11 केवी नया फीडर तैयार किया जा रहा है। जो तीन माह में बनकर तैयार हो जाएगा।

कीचड़ युक्त गलियों से निकलना हुआ दुशवार

● ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन डीएम से की विकास कार्यों की मांग ● गंगागंज गुदौली में गौशाला में गायों की स्थिति हुई दयनीय, भूख प्यास से हो रही बीमार

गुरसहायगंज (कन्नौज)। गंगागंज गुदौली स्थित गौशाला में भूख प्यास तड़प रही गायों का बुरा हाल है। वही सिंगपुर में विकास कार्यों के अभाव में कीचड़ युक्त गलियों से ग्रामीणों का निकलना दुशार हो गया है। विकास कार्यों के नाम पर प्रधानों एवं सचिवों द्वारा गोलमाल का आरोप ग्रामीणों द्वारा जिला प्रशासन से जांच करवाए जाने एवं विकास कार्य करवाने की मांग की जा रही है। विडंबना है कि प्रदेश सरकार गौशालाओं में गायों की सुरक्षा हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम एवं योजनाएं चला रही है। समय-समय पर अधिकारियों को गाड़इलाइन भी दी



गौशाला में बीमार पड़ी गाय, कीचड़ युक्त पानी से निकलते एवं प्रदर्शन करते ग्रामीण।

जाती है। इसके बावजूद भी अधिकारी एवं जिम्मेदार ध्यान नहीं देते हैं। क्षेत्र के ग्राम गंगागंज दुर्गज निस्थित गौशाला में लगभग एक दर्जन पालतू गायों में एक गाय गंभीर रूप से घायल है और दूसरी गाय गाय भी बीमार होकर तड़प रही है। केयटरेकर मौके से दीप कुमार उसके स्थान पर उसका उसका बच्चा गौशाला की सफाई कर रहा था। चारा के स्थान पर सूखा भूसा भी नहीं था। पूछे जाने पर सचिव विमल दुवे ने कहा कि निरीक्षण किया जा चुका है। गायों का इलाज चल रहा है उभर ताराग्राम ब्याक के ग्राम सिंगपुर में विकास कार्यों एवं सफाई के अभाव में गलियां कीचड़ पानी से भरी है। कीचड़ युक्त गलियों से निकलना ग्रामीणों की मजबूरी है। ग्राम

प्रधान पुष्पेंद्र एवं सचिव लगातार अनदेखी कर रहे हैं। अग्रत सरोवर की सफाई का ध्यान नहीं रखा गया है। जूड़े के ढेर गांव की हर गली में लगे हुए हैं। इसके विरोध में ग्रामीण ओम प्रकाश, बांकलाल, पूरन, राकेश चंद्र, सतीश, सावित्री, रेखा, डॉ. रामकेश सहित तमाम लोगों ने प्रधान एवं सचिव के विरुद्ध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने जिम्मेदारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि विकास कार्यों के लिए आने वाले बजट का बंदरबाट हो रहा है। ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से एक टीम भेज कर निरीक्षण करवाने एवं जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है।

पुलिस नें अंतर्जनपदीय गिरोह के चार बदमाशों को दबोचा

कन्नौज। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनन्द के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी छिब्रामऊ ओमकार नाथ शर्मा के पर्यवेक्षण मे थाना छिब्रामऊ पुलिस द्वारा घरों का ताला तोड़कर चोरी करने वाले अंतर्जनपदीय गिरोह के चार शास्त्र अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार कर चोरी हुए जेवरत व हजारां रुपये की नगदी बरामद की। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनन्द ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुये बताया कि विगत 27 जुलाई को अरविन्द कुमार दुबे निवासी मोहल्ला नयी वस्ती भैनपुरा थाना छिब्रामऊ ने अज्ञात चोरों द्वारा घर का ताला तोड़कर पांच लाख रुपये के जेवरत, 54,600 की नगदी 12 कारतूस 12 बोर, कपड़े व अन्य सामान चोरी कर लिये थे। अज्ञात चोर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में व साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण अजीत जाटव पुत्र धनपाल जाटव निवासी ग्राम भारापुर थाना छिब्रामऊ, शीलेश यादव पुत्र



चोरी की घटना का खुलासा करते एसपी व छिब्रामऊ सीओ।

कालीचरन यादव निवासी गढी मदारी थाना पचोखरा मिरोजवाब, सुरेशील जाटव पुत्र लखू सिंह निवासी ग्राम किनावर थाना बिख्या मैनुपुरी, दीपक जाटव पुत्र स्व. रामनरेश निवासी हलपुरा थाना द्वाहार मैनुपुरी को छिब्रामऊ फर्रुखाबाद मार्ग पर स्थित इण्डियन आयल प्रेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से अरविन्द कुमार दुबे (रिटायर्ड सैनिक) के घर से चोरी किये गये जेवरत व नगदी तथा 12 कारतूस 12 बोर व घटना में प्रयुक्त औजार व एक

तमंचा 315 बोर व एक कारतूस बरामद हुआ। धारा 317(2) बीएमएस की बढोत्तरी की गयी अभियुक्तगण ने करीब एक 5 माह पूर्व चौकी सिन्दरपुर थाना छिब्रामऊ क्षेत्र के ग्राम शहजहाँपुर में पंचायत घर से चोरी की घटना को अंजाम दिया था जिसके सम्बन्ध में थाना छिब्रामऊ पर मुकदमा पंजीकृत है। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी कर अजीत जाटव व शीलेश यादव को न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

नि:शुल्क लगवाएं स्मार्ट मीटर गलत बिलों से पाएं छुटकारा

फतेहपुर। दोआबा के बिजली उपभोक्ताओं को अब स्मार्ट मीटर से बिजली आपूर्ति देने की तैयारी तेजी पर है। पूरे जिले के बिजली उपभोक्ताओं के घरों में लगे डिजिटल मीटर को पहले हटवाया जा रहा है। इसके बाद स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को मीटर रीडिंग की गड़बड़ी और गलत बिलों से छुटकारा मिल जाएगा, वहीं अधिकारी किसी भी मीटर का ऑनलाइन जायजा भी ले सकेंगे।

सदर एसडीओ इंजी. एमएम सिद्दीकी ने बताया कि स्मार्ट मीटर पूरे जिले के बिजली उपभोक्ताओं के यहाँ नि:शुल्क लगाए जाएंगे। पहले चरण में शहरी क्षेत्र को लिया गया है। शहर के अंदर सिविल लाइन में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू हो चुका है, अभी तक करीब 600 से ऊपर उपभोक्ताओं के परिसर पर स्मार्ट मीटर स्थापित किया जा चुका है। बताया कि इस व्यवस्था से बिजली का लाइनलॉस

काभी हद तक घटेगा। अभी तक डिजिटल मीटर से बिजली आपूर्ति दी जा रही हैं। इससे मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी, रीडिंग स्टोर करने के मामले थमने का नाम नहीं ले रही है। इस समस्या से निजात पाने को अब उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर से आपूर्ति देने की तैयारी तेजी पर है। इसकी कवायद शुरू हो गई है, सभी डिजिटल मीटर को हटवाया जाएगा, जिसके स्थान पर स्मार्ट मीटर से आपूर्ति मिलेगी।

स्मार्ट मीटर की ये हैं खूबियां: उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर पर लगी डिस्प्ले स्क्रीन के माध्यम से वर्तमान शेष बिजली बिल, बिजली की वर्तमान शेष राशि, पिछले महीने खपत बिजली की स्थिति का पता चल सकेगा। इसके जरिए उपभोक्ता बिजली की खपत को नियंत्रण में रख सकेंगे। फिहालहा अभी उपभोक्ताओं के लिए पोस्टपेड रीचार्ज की व्यवस्था दी जा रही है, बाद में इच्छुक लोगों को प्री-पेड व्यवस्था भी दी जाएगी।

जिला अस्पताल पहुंचे पूर्व केन्द्रीय गृहराज्यमंत्री जनरल सर्जरी वार्ड सहित ओपीडी व ब्लड बैंक का किया निरीक्षण

लखीमपुर खीरी। जिला अस्पताल एमसीएच विंग ओयल में दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी करने पूर्व केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी शुक्रवार को अस्पताल पहुंचे जहां उन्होंने अल्ट्रा साउण्ड रूम, एक्सरे रूम व पैथोलोजी सहित जनरल सर्जरी वार्ड, ओपीडी व ब्लड बैंक का भ्रमण कर मरीजों से मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी करी। इस दौरान सीएमओ डॉ सन्तोष गुप्ता, सीएमएस डॉ आरके कोली व सीएमएस एमसीएच विंग डॉ ज्योति मेहरोजा भी मौजूद रहीं।

शुक्रवार को करीब 11 बजे पूर्व केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी जिला अस्पताल पहुंचे, जहां सीएमएस डॉ ज्योति मेहरोजा द्वारा बुके देकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद वह सीएमएस एक्स रे व अल्ट्रासाउण्ड कक्ष में पहुंचे। जहां पर बैठे हुये मरीजों से उन्होंने मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी की, उन्होंने एक महिला



मरीज से पूछा कि आप कहां रहती हैं, तो महिला मरीज ने अपने जिले का नाम सीतापुर बताया। इसके बाद वह पैथोलोजी सहित जनरल सर्जरी वार्ड, ओपीडी व ब्लड बैंक का भ्रमण कर मरीजों से मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी करी। इस दौरान सीएमओ डॉ सन्तोष गुप्ता, सीएमएस डॉ आरके कोली व सीएमएस एमसीएच विंग डॉ ज्योति मेहरोजा भी मौजूद रहीं।

उनके तीमारदारों से बात की और दवाओं के बारे में पूछा जिस पर सभी ने अस्पताल से ही दवाएं मिलने की बात कही। इसके बाद डेन्यू वार्ड पहुंचे। यहां की व्यवस्थाएं देखी, मरीजों के लगी मच्छरदानी के बारे में पूछा जिस पर सीएमओ डॉ सन्तोष गुप्ता ने बताया कि डेन्यू से पीड़ित मरीज को अगर मच्छर काटे और वह मच्छर दुबारा किसी सामान्य व्यक्ति को काट ले तो उसे भी डेन्यू होने का खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए इन मरीजों के लिए अलग वार्ड है और इन्हें मच्छरदानी में रखा जाता है।

देश में निर्माण होने पर जनहित याचिकाएं क्यों दायर की जाती हैं: शीर्ष अदालत हैरान

नई दिल्ली। विकास और पारिस्थितिकी संतुलन को महत्वपूर्ण बताते हुए उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को इस बात पर हैरानी जताई कि जब राजमार्ग जैसी ढांचगत परियोजनाएं शुरू की जाती हैं तो जनहित याचिकाएं (पीआईएल) क्यों दायर की जाती हैं? शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी गोवा में तिनैघाट-वास्को डी गामा मार्ग के वास्को डी गामा-कुलेम खंड पर रेलवे पटरियों के दोहरीकरण से जुड़े निर्माण कार्य पर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा, हम केवल यह सोच रहे हैं कि ऐसा केवल इस देश में ही क्यों होता है कि जब आप हिमाचल प्रदेश में सड़क बनाना शुरू करते हैं, तो जनहित याचिकाएं आ जाती हैं। जब आप राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना

शुरू करते हैं, तो जनहित याचिकाएं आ जाती हैं। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, आप हमें एक भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बताएं जहां रेलवे की सुविधा नहीं है। पीठ ने कहा, आरम्भ पर्वत पर जाएं और वे आपको ट्रेन में बर्फ के बीच से ले जाएंगे।

शीर्ष अदालत बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ के अगस्त 2022 के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने रेलवे पटरी के दोहरीकरण के निर्माण से संबंधित एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में आरोप लगाया था कि निर्माण कार्य वर्ष 2011 के तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना, गोवा सिंचाई अधिनियम-1973, गोवा पंचायत राज अधिनियम-1994 और

गोवा शहर एवं नगर नियोजन कानून के तहत पूर्व अनुमति प्राप्त करने के वैधानिक आदेश का उल्लंघन करके किया जा रहा था। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह परियोजना गोवा में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करेगी और सड़क परिवहन पर बोझ को कम करने में मदद करेगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने अनियोजित विकास के खतरों पर प्रकाश डालते हुए केरल के वायनाड जिले की हालिया घटना का जिक्र किया जो 195 लोगों को जान ले ली। गोवा में रेलवे लाइन परियोजना पर पीठ ने कहा कि विशेषज्ञ हैं जो हर चीज की जांच करेंगे।

वकील ने कहा कि रेलवे लाइन पारिस्थितिकीय रूप से नाजुक क्षेत्र से होकर गुजरती है और याचिका को विकास विरोधी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। पीठ ने कहा, विकास और पारिस्थितिकी संतुलन साथ-साथ

चलने चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई भी अंधाधुंध विकास की इजाजत नहीं दे सकता। आखिरकार हम कानून के शासन द्वारा शासित हैं। पीठ ने वकील से कहा कि किसी बात को लेकर कोई अस्तित्वहीन या धामक आशंका नहीं होनी चाहिए। जब वकील ने तर्क दिया गोवा की तटरेखा पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र है तो पीठ ने कहा, आपका अंतिम तर्क यह है कि जहां रेलवे लाइन नहीं होनी चाहिए... जब शानदार वाहनों में लोग वहां जाते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होती। उनके पास आलीशान बंगले हैं, उनके पास बहुत सारी गार्डियां हैं, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है। शीर्ष अदालत ने इसके बाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया।

दहेज हत्या मामले में पति को दस साल और सास व ससुर को सात-सात साल की सजा

बलिया। बलिया की एक स्थानीय अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में बृहस्पतिवार को मुत्का के पति, सास और ससुर को दोषी करार देते हुए उन्हें क्रमशः दस साल औरसात - सात साल के कारावास की सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक विक्रान्त वीर ने शुक्रवार को बताया कि अ्पर जिला जज रवि किरण सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पति धर्मेंद्र वमां , ससुर बेरन प्रसाद वमां और सास मंजू देवी को दोषी करार देते हुए पति को दस साल और सास व ससुर को सात - सात साल के कारावास और प्रत्येक को तीन - तीन हजार रूपए के अर्थदंड को सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि बिहार राज्य के बस्सर जिले के काली नगर सोहनी के रहने वाले कृष्ण सिंह ने अपनी पुत्री शशि कला को शादी गत फरवरी 2012 में फेफना थाना क्षेत्र के कोपवा बहादुरपुर गांव के धर्मेंद्र वमां के साथ की थी।

महाराष्ट्र सरकार की लाडकी बहिन योजना के खिलाफ याचिका, अदालत ने जल्द सुनवाई से इंकार किया

भाषा। मुंबई

महाराष्ट्र सरकार की महिलाओं के लिए नकद लाभ योजना मुख्यमंत्री मांझी लाडकी बहिन योजना के खिलाफ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि इससे कर्दाताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। याचिकाकर्ता ने नौ जुलाई को इस योजना को शुरू करने वाले सरकारी प्रस्ताव को रद्द करने की मांग की, जिसके तहत 21 से 65 आयु वर्ग की उन महिलाओं के बैंक खातों में 1,500 रूपए का मासिक भता स्थानांतरित किया जाएगा, जिनकी पारिवारिक आय सालाना 2.5 लाख रूपए से कम है। इस योजना की घोषणा राज्य के बजट में की गई थी।

याचिकाकर्ता के वकील ओवेस पेचकर ने शुक्रवार को याचिका पर तत्काल सुनवाई और योजना के कार्यान्वयन पर रोक लगाने के लिए

अंतरिम आदेश का अनुरोध किया, क्योंकि इस महीने के अंत में लाभार्थियों को राशि वितरित की जाएगी। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ ने अनुरोध को खारिज करते हुए कहा कि याचिका पर नियमित प्रक्रिया के अनुसार सुनवाई की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय ने कहा, नियमित प्रक्रिया की प्रणाली को निरर्थक न बनाएं। कहीं तोड़फोड़ की कारवाई हो रही है या किसी को फांसी पर लटकया जा रहा हो..तब अत्यावश्यक कार्यवाही होती है।

उच्च न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार, जनहित याचिका पर पांच अगस्त को सुनवाई होने की संभावना है। याचिकाकर्ता नवीद अब्दुल सईद मुल्ला ने दावा किया कि संबंधित सरकारी योजना के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर्दाताओंराजकोष पर

अतिरिक्त बोझ डाला जाता है, क्योंकि करों को अवसरंचना विकास के लिए एकत्र किया जाता है, न कि बेतुकी नकद योजनाओं के लिए।

उन्होंने कहा, ऐसी नकद लाभ योजनाएं, आगामी राज्य विधानसभा चुनावों में मौजूदा गठबंधन सरकार में शामिल दलों को ओर से किसी खास वर्ग के मतदाताओं को किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में वोट के लिए रिश्तत या उपहार देने के समान हैं। याचिका में कहा गया कि ऐसी योजना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के विरुद्ध है और भ्रष्ट आचरण के समान है। याचिका में दावा किया गया कि महिलाओं के लिए इस योजना पर लगभग 4,600 करोड़ रूपए खर्च होंगे और यह महाराष्ट्र पर बहुत बड़ा बोझ है, जिस पर पहले से ही 7.8 लाख करोड़ रूपए का कर्ज है, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने घाटल लोकसभा सीट के सभी कागजात, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया

कोलकाता (।भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि परिषम बंगाल के घाटल लोकसभा क्षेत्र में चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार हिरण्मय चट्टोपाध्याय द्वारा दायर चुनाव याचिका के निपटारे तक सुरक्षित रखे जाएं। घाटल से तुण्मूल कांग्रेस के दीपक अधिकारी को विजेता घोषित किया गया, जहां 25 मई को चुनाव हुए थे। अदालत ने निर्देश दिया कि चुनाव याचिका पर निर्णय होने तक, घाटल निर्वाचन क्षेत्र में हुए चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज, उपकरण, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (डीवीआर) को ऐसे दस्तावेजों के संरक्षक प्राधिकारी द्वारा संरक्षित रखा जाए। न्यायमूर्ति बिवास पटनायक ने उच्च न्यायालय के संबंधित रजिस्ट्रार को इस आदेश की एक प्रति मुख्य

निर्वाचन आयुक्त को देने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के फॉरेंसिक ऑडिट के लिए याचिकाकर्ता के वकील के अनुरोध पर छह सितंबर को आगली सुनवाई में फैसला किया जाएगा।

भाजपा के हिरण्मय चट्टोपाध्याय और तुण्मूल के दीपक अधिकारी दोनों ही फिल्म अभिनेता हैं और फिल्म जगत में क्रमशः हिरण और देव के नाम से चर्चित हैं। चट्टोपाध्याय के वकील विलवदल भट्टाचार्य ने कहा कि याचिका में कथित भ्रष्ट आचरण के आधार पर चुनाव प्रक्रिया को चुनौती दी गई है।

उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों में सीसीटीवी फुटेज, ईवीएम और डीवीआर सहित रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए आदेश देने का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति पटनायक ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।

अदालत ने दूसरी बेटी को जन्म देने पर पत्नी की हत्या करने के जुर्म में पति को सुनाई मौत की सजा

भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर की एक अदालत ने एक व्यक्ति को दो साल पहले अपनी पत्नी की चाकू चोंपकर हत्या करने और छह वर्षीय बेटी की गला रेतकर हत्या करने की कोशिश करने के अपराध में मौत की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोषी संजीत दास (46) ने नौ जून, 2022 को इस अपराध को अंजाम दिया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उसने भुवनेश्वर के घाटिक्रिया इलाके में स्थित घर पर अपनी पत्नी सरस्वती की 33 बार चाकू चोंपकर हत्या कर दी थी। निजी अस्पताल में हेड नर्स के तौर पर काम करने वाली सरस्वती ने हत्या से कुछ दिन पहले ही दूसरी बेटी को जन्म दिया था। दास ने अपनी पहली बेटी (6) का भी गला रेत दिया था, लेकिन वह बच गई। दास को घटना के अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर अक्टूबर, 2022 में उसके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था।

भुवनेश्वर की द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बंदना कारी की अदालत ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाते हुए इस अपराध को दुर्लभतम श्रेणी में रखा और कहा, ऐसे में दोषी के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए... इसलिए यह अदालत दोषी को मौत की सजा सुनाती है। अदालत ने कहा कि पीड़िता के दूसरी बेटी को जन्म देने के कारण दोषी ने अपनी पत्नी की हत्या की और यही कारण था कि उसमें पहली बेटी की भी हत्या करने की कोशिश की।

अदालत ने कहा कि ऐसे दुर्लभतम अपराध के लिए मृत्युदंड देने अन्य लोगों को हतोत्साहित करेगा, जो इस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम देने के बारे में सोचते हैं। अदालत ने दास को आजीवन कारावास की भी सजा सुनाई है। दोनों अपराधी साथ-साथ चलेंगे, बरतों की दोषी की सजा में संशोधन न हो, उसकी सजा बदलकर हल्की न कर दी

जाए या सजा की अवधि न घटा दी जाए या माफी न दी जाए।

अदालत ने छह साल की बच्ची को लगे आघात पर टिप्पणी करते हुए कहा, वह बच्ची, जिसे भारतीय कानून की व्यवस्था फिल्मों में भी ऐसी भयावहता देखने को अनुमति नहीं देती है, उसे अपनी आंखों के सामने यह सब होते हुए देखना पड़ा। अदालत ने कहा, गर्ब से वदे मातरम गाने वाली छह साल की छोटी बच्ची के पिता ने ही उसका गला रेतने की कोशिश की। वह बच्ची जो शाब्द काटून छोटा भीम और डोरैमोन देखने का आनंद लेती होगी, उसे अपने ही पिता द्वारा मां की जघन्य हत्या देखनी पड़ी। अदालत ने कहा, हम उस बच्ची की गहन पीड़ा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वह घर जो उसके लिए एक सुरक्षित आश्रय था, लेकिन अब अकल्पनीय भयावहता का दृश्य बन गया है, जिसने उसकी सुरक्षा और विश्वास की भावना को चकनाचूर कर दिया है।

न्यायालय ने अधिविश्वास, जादू-टोना उन्मूलन के लिए वक्त उठाने संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अधिविश्वास, जादू-टोना और इसी तरह की अन्य प्रथाओं के उन्मूलन के लिए केंद्र और राज्यों को उचित कदम उठाने के निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि अधिविश्वास को खत्म करने का उपाय शिक्षा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि समेत मालों में संसद को हस्तक्षेप करना चाहिए। पीठ ने कहा, हम यह आदेश कैसे जारी कर सकते हैं कि वैज्ञानिक सोच विकसित करने और अधविश्वास को खत्म करने के लिए कदम उठाए जाएं। संविधान निर्माताओं ने यह सब राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया था। पीठ द्वारा मामले पर सुनवाई से इनकार करने के बाद याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका वापस ले ली।

ट्रांसजेंडर के रक्तदान पर रोक लगाने संबंधी निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें ट्रांसजेंडर, समलैंगिक और यौनकर्मियों को रक्तदान करने से रोकने वाले दिशानिर्देशों को चुनौती दी गई है। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और राष्ट्रीय रक्तदान परिषद को नोटिस जारी किए। शीर्ष अदालत कार्यकर्ता शरीफ डी रंगनेकर द्वारा 2017 के दिशानिर्देशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दिशा निर्देश में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, पुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों (एमएसएम) और महिला यौनकर्मियों को रक्तदाता बनने से बाहर रखा गया है। वर्ष 2017 के दिशानिर्देश एचआईवी और हेपेटाइटिस संक्रमण या ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शन (टीटीआई) के जोखिम के कारण इन्हें रक्तदाता बनने से स्थाई रूप से रोकते हैं।

एशियानेट न्यूज नेटवर्क के खिलाफ दिव्या स्पंदना के मानहानि के मामले को रद्द करने से इनकार

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अभिनेत्री-राजनेता दिव्या स्पंदना द्वारा एशियानेट न्यूज नेटवर्क और पत्रकार विश्वेश्वर भट के खिलाफ दायर मानहानि का मामला रद्द करने से इनकार कर दिया। स्पंदना ने एशियानेट न्यूज और अन्य के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग कांड में कन्नड़ फिल्म अभिनेत्रियों की कथित संलिप्तता की खबर प्रसारित की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि समाचार प्रसारित होने के दौरान शिकायतकर्ता का नाम बार-बार लिया गया तथा उनके फोटो और वीडियो दिखाए गए।

स्पंदना द्वारा दायर शिकायत में विशेष रूप से कहा गया है कि समाचार को इस तरह से प्रसारित किया जा रहा था, जैसे शिकायतकर्ता स्वयं कथित क्रिकेट सट्टेबाजी या स्पॉट फिक्सिंग कांड में शामिल हो। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़



और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कार्यवाही रद्द करने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

पीठ ने कहा, उनका (स्पंदना का) बार-बार बलुटिनी में उल्लेख किया गया है, हम आदेश को कैसे रद्द कर सकते हैं? हम इस पर विचार नहीं कर सकते। शीर्ष अदालत एशियानेट न्यूज नेटवर्क और अन्य द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी।

शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन: न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा से स्थिति को और खराब न करने को कहा

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा सरकारों से कहा कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सहित अन्य मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से संपर्क करने के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित करने के वास्ते कुछ तटस्थ व्यक्तियों के नाम सुझाएं। न्यायालय ने कहा कि किसी की भी स्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहिए। न्यायालय ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने का अधिकार है और वह सभी पक्षों को शामिल करते हुए वादाचिती की एक सहज शुरुआत चाहता है।

शीर्ष अदालत पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें राज्य सरकार को एक स्पष्टाह के भीतर अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड हटाने के लिए कहा

गया था, जहां प्रदर्शनकारी किसान 13 फरवरी से डेरा डलेंगे हुए हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा, किसी की भी स्थिति को और बिगाड़ना नहीं चाहिए। उनका (किसानों) भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं, लेकिन एक राज्य के रूप में... आप उन्हें समझाने की कोशिश करें कि जहां तक ट्रैक्टरों, जेसीबी मशीनों और अन्य कृषि उपकरणों का सवाल है, उन्हें उन जगहों पर ले जाएं जहां तक जरूरत है जैसे खेत या कृषि भूमि में।

पीठ ने कहा, हां, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्हें अपनी शिकायतें व्यक्त करने का अधिकार है। ए शिकायतें अपने स्थान पर रहकर भी व्यक्त की जा सकती हैं। न्यायालय ने 24 जुलाई को मामले की सुनवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों से संपर्क करने और उनकी मांगों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध लोगों की एक स्वतंत्र समिति के गठन का प्रस्ताव

रखा था। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान, हरियाणा सरकार की ओर से पेश सॉलिडिस्ट जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्होंने 24 जुलाई के अदालत के निर्देशानुसार इस पर काम शुरू कर दिया है।

पंजाब की ओर से पेश वकील ने चरणबद्ध तरीके से राजमार्ग खोलने का उल्लेख किया। पीठ ने कहा, आप अपने प्रस्ताव का आदान-प्रदान क्यों नहीं करते? हर बार दो राज्यों के बीच लड़ाई होना जरूरी नहीं है। मेहता ने दलील दी कि कोई राज्य यह नहीं कह सकता कि किसानों को देश की राजधानी में जाने दिया जाए। उन्होंने कहा कि नोटिस जारी होने के बावजूद किसान उच्च न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुए। पीठ ने कहा, हम सभी पक्षों के बीच बातचीत की प्रक्रिया के संदर्भ में एक बहुत ही सहज शुरुआत चाहते हैं। पीठ ने राज्यों से समिति में शामिल किए जा सकने वाले लोगों के कुछ नाम सुझाने को कहा।

पेज 1 का शेष कोचिंग सेंटर...

चालक मनुज कथुरिया पर आरोप था कि वह 27 जुलाई को अपना वाहन लेकर जलमगन सड़क से गुजरे थे जिससे पानी तीन मंजिला इमारत के गेट से टकराया और इससे गेट टूट गया जहां कोचिंग सेंटर स्थित था। आरोप था कि इससे इमारत के बेसमेंट में पानी भर गया जिसमें डूबने से तीन विद्यार्थियों की मौत हो गई। अदालत ने छात्रों के डूबने की घटना को लेकर पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को फटकार लगाते हुए कहा कि वह यह समझ पाने में असमर्थ है कि छात्र बाहर कैसे नहीं आ सकते। अदालत ने साथ ही यह भी जानना चाहा कि क्या दरवाजे अवरुद्ध थे या सीढ़ियां संकरी थीं। पीठ ने कहा कि प्रशासनिक तौर पर दिल्ली में कई प्राधिकारी हैं जो केवल जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डाल रहे हैं और इसके अलावा कुछ कर नहीं रहे हैं। इसने कहा कि आम धारणा यह है कि नगर निगम के अधिकारी अक्षम हैं। पीठ ने कहा कि दिल्ली में भौतिक बुनियादी ढांचा करीब 75 साल पुराना है और यह न केवल अपर्याप्त है, बल्कि इसका रखरखाव भी ठीक से नहीं किया जाता। अदालत में

मौजूद एमसीडी आयुक्त द्वारा यह बताया जाने पर कि इलाके में बसती नालों से पानी की निकासी ठीक ढंग से नहीं हो रही थी, पीठ ने सवाल किया कि अधिकारियों ने एमसीडी प्रमुख को इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। पीठ ने राजेंद्र नगर क्षेत्र में अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण को हटाने का भी आदेश दिया, जिसमें बसती नालों और सीवेज नालों पर किया गया अतिक्रमण भी शामिल है। इसने कहा कि एमसीडी अधिकारियों को इसकी कोई परवाह नहीं है और यह एक आम बात हो गई है। अदालत ने कहा कि दिल्ली की आबादी बढ़ने के साथ ही शहर को एक मजबूत व्यवस्था की आवश्यकता है और विभिन्न सफ़िडी योजनाओं के कारण राष्ट्रीय राजधानी में पलायन भी बढ़ रहा है। पीठ ने कहा कि दिल्ली के आशासनिक, वित्तीय और भौतिक बुनियादी ढांचे पर फिर से विचार करने का समय आ गया है। पीठ ने इस मुद्दे से निपटने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की।

नीट-यूजी...

सोशल मीडिया या इंटरनेट का उपयोग करके व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था, या परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके छात्रों को उतार बताया जा रहे थे। पता लगाना कठिन साबित हो सकता

है।पीठ ने कहा, हजारोंबाग और पटना में लोक से लाभान्वित होने वाले छात्रों की पहचान की जा सकती है। सीबीआई जांच से इस स्तर पर उन छात्रों की संख्या का पता चलता है जो हज़ारीबाग और पटना में कदाचार के लाभार्थी हैं। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह है कदाचार या

धोखाधड़ी के लाभार्थियों को ईमानदार छात्रों से अलग करना संभव है, इस मामले में, अदालत दोबारा परीक्षा का निर्देश नहीं दे सकती। कोर्ट ने कहा कि पेपर पटना और हज़ारीबाग् में लोक हुआ था. एक केंद्र में, स्टूडंग रूम का पिछला दरवाजा खोला गया था और अनधिकृत व्यक्तियों को प्रश्न पत्रों जल्द पहुंचने की अनुमति दी गई थी। यह इंगित करता है कि सुरक्षा में गंभीर चूक हुई है और सुरक्षा उपाय जो कड़े और प्रभावी हैं उन्हें एनटीए द्वारा लागू किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, पता चला कि प्रश्नपत्र कभी-कभी ई-रिक्शा में ले जाए जाते थे और निजी कूरियर कंपनियों की सेवाओं का लाभ उठाना जाता था।पीठ ने कहा, चिंता का एक और मुद्दा यह है कि एनटीए परीक्षा के लिए पर्यवेक्षक बनने के लिए उन लोगों पर निर्भर करता है जिन पर वह प्रत्यक्ष निगरानी नहीं रखता है। ऐसे कई तरीके हैं जिन्हें पर्यवेक्षकों पर उचित निगरानी सुनिश्चित करने और अनुचित साधनों के उपयोग की संभावना को कम करने के लिए अपनाया जा

सकता है। सभी मुद्दों से संकेत मिलता है कि कदाचार और धोखाधड़ी की संभावना को कम करने और प्रश्न पत्रों तक निजी व्यक्तियों की पहुंच को कम करने के लिए सुरक्षा को कड़ा किया जाना चाहिए।

नीट से पहले...

लिए नीट की शुरूआत एक आवश्यक सुधार था। मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनके पहले कार्यकाल के दौरान नीट लाए जाने से पहले चिकित्सा शिक्षा में भ्रष्टाचार व्याप्त था। उन्होंने जोर देकर कहा कि एनईईटी से पहले, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र गंभीर कदाचार से ग्रस्त था, जिसमें 8 करोड़ रुपये से 13 करोड़ रुपये तक की अत्यधिक रकम के लिए स्नातकोत्तर सीटों की बिक्री भी शामिल थी।नट्डी ने कहा, मेडिकल शिक्षा एक व्यवसाय का अड्डा बन गई थी।

आशा किरण...

नहीं सौंपा है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल अब तक 28 मानसिक रूप से बीमार कैदियों की मौत हो चुकी है। जुलाई में हुई कुल 14 मौतों में से 10 मौतें महीने के आखिरी हिस्से में हुईं, जिनमें एक 14 साल के लड़के की मौत भी शामिल है। शेल्टर होम की मेडिकल केयर यूनिट के मुताबिक, ज्यादातर मृतकों को सांस लेने में दिक्कत और दस्त की शिकायत थी।एलजी ने दिल्ली

सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी शेल्टर होम की स्थिति पर एक व्यापक जांच का आदेश दिया और एक सप्ताह के भीतर जिम्मेदारी तय करने वाली रिपोर्ट पेश की।

दुश्मनों ने...

'पड़ोस के चार लोग - अंकित, गौरव, करण और आकाश - घर आए और मेरे बेटे को अपने साथ ले गए।' 18 जुलाई की शाम वे उसे गांव के बाहर खेत की ओर ले गए और उसकी पिटाई की। फिर उसके गले में रस्सी डालकर उसका गला घोट दिया और उसे गड्डे में मरने के लिए छोड़ दिया। फिर, एक चमत्कार हुआ। खुन की गंध आने पर आवारा कुत्तों के झुंड ने मिट्टी खोदी। मेरा बेटा बेहोश था, और जैसे ही कुत्तों ने उसे खींचना शुरू किया, वह होश में आ गया। बाद में हम उसे अस्पताल ले गए जहां वह ठीक हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि 18 जुलाई को इलाके में दो समूहों के बीच विवाद हुआ था और रूप ने एक व्यक्ति द्वारा अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई थी।

52 साल बाद

आगे था। दूसरे क्रांटेर में आस्ट्रेलियाई टीम ने आक्रामक तेवरों के साथ वापसी की और चौथे ही मिनट में पेनल्टी कॉर्नर

बनाया। इस पर गोवर्स ब्लैक के शॉट को श्रीजेश ने बड़ी चतुराई से बचाया। अगले ही पल एक और पेनल्टी कॉर्नर पर भी यही कहानी रही लेकिन शॉट शॉर्प लालचाल का था। आस्ट्रेलिया के लिए पहला गोल 25वें मिनट में क्रेग थॉमस ने पेनल्टी कॉर्नर पर किया। भारत को अगले मिनट पेनल्टी

कॉर्नर मिला लेकिन हरमनप्रीत गोल नहीं कर सके। तीसरे क्रांटेर में भारत को दूसरे ही मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला लेकिन हरमनप्रीत का शॉट बचा लिया गया।

भारतीय टीम ने वीडियो रैफरल लिया जिसके बाद भारत को पेनल्टी स्ट्रोक दिया गया और भारतीय कप्तान ने टूर्नामेंट का अपना छठा गोल करके भारत को 3 .। से बढत दिला दी। भारतीय फॉरवर्ड पंक्ति ने अभिषेक की अगुवाई में हमले बोलने का सिलसिला जारी रखा और दूसरी और आस्ट्रेलियाई टीम अपने कमजोर पेनल्टी कॉर्नर से जूझती रही। आस्ट्रेलिया को 45वें मिनट में मिला पेनल्टी कॉर्नर भी बेकार गया। आखिरी पंद्रह मिनट में आस्ट्रेलिया ने वापसी की भरसक कोशिशें की लेकिन भारत ने 51वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को मिनट में मिला पेनल्टी कॉर्नर भी बेकार कर दिया। तीसरे क्रांटेर में आस्ट्रेलियाई डिफेंडर ने बचा लिया। भारत के लिए इसी पेनल्टी कॉर्नर मिला जिस पर अमित रोहिदास की फिलक को आस्ट्रेलियाई डिफेंडर ने बचा लिया। भारत के लिए इसी

मिनट अभिषेक ने गोल कर दिया था लेकिन आस्ट्रेलिया के वीडियो रैफरल पर उसे अमान्य कर दिया गया। आस्ट्रेलिया को 55वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक मिला जिस पर गोवर्स ने गोल करके आखिरी पांच मिनट में खेल को रोमांचक बना किया। भारत को अगले मिनट पेनल्टी मिनट।भारतीय डिफेंस ने आखिरी पांच मिनट जबरदस्त संयम का प्रदर्शन करते हुए आस्ट्रेलिया के नामचीन स्ट्राइकर्स को कोई मौका नहीं दिया।

मुख्यमंत्री ने...

को अयोध्या जिला महिला चिकित्सालय में दुकर्म पीड़ित बालिका से मुलाकात करने के निर्देश भी दिये। वहीं अयोध्या पहुंचीं आयोग की सदस्य ने पीड़ित बच्चों का हाल-चाल जाना तथा उसके परिजनों से शिष्टाचर मुलाकात करते हुए उनको न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में 12 वर्षीय की बालिका के साथ दरिंदगी निंदनीय घटना है। परिजनों द्वारा अवगत कराया गया है की बच्ची अक्सर खेतों में काम करने जाती थी। बहला फूसला कर उसके साथ हैवानियत की गई है। दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। इसको लेकर जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा भी हमें आश्वस्त किया गया है।

नाइजीरिया में आर्थिक संकट के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान 13 लोग मारे गए

मानवाधिकार समूह का दावा

भाषा। अन्वुजा

नाइजीरिया में आर्थिक संकट के खिलाफ व्यापक पैमाने पर जारी विरोध-प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 13 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। एक मानवाधिकार समूह ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। विरोध-प्रदर्शन ने कई राज्यों में हिंसक रूप ले लिया है, जिसके चलते कई जगह कर्फ्यू घोषित किया गया है। अधिकारियों ने बम धमाके में चार लोगों की मौत होने की पुष्टि की और कहा कि



देशभर में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के नाइजीरिया निदेशक ईसा सानुसी ने एक साक्षात्कार में

कहा कि समूह ने चरमदीयों, पीड़ितों के परिवारों और वकीलों द्वारा बताई गई मौतों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि की है। इस बीच, नाइजीरिया की पुलिस

गिरफ्तार किया गया और कर्फ्यू लगा दिया गया। उसने बताया कि एक पुलिस अधिकारी की भी मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रदर्शनकारों बढ़ते आर्थिक संकट को दूर करने की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते अफ्रीका के शीर्ष तेल उत्पादक देश के लोग सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार और कुशासन को समाप्त करने की मांग की। मॉडिया में आए विरोध-प्रदर्शन के वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारियों को गोदामों में लूटपाट करते और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए देखा जा सकता है।

रूस से बंदियों की अदला-बदली के बाद रिहा हुए तीन अमेरिकी स्वदेश पहुंचे

भाषा। वाशिंगटन

रूसी खुफिया एजेंट को भी छोड़ा गया

तालिन (एस्टोनिया)। अमेरिा और रूस के बीच शीत युद्ध केबाद कैदियों की सबसे बड़ी अदला-बदली में रूस ने पहली बार स्वीकार किया किपरियमी देशो ने पकड़े गए कुछ रूसी नागरिकउसवी सुरक्षा सेवाओ से जुड़े थे। रिस चिप गए कैदियों के परिवारो ने इस आश्चर्यजनकरिसई पर अपनी खुशी व्यक्त की। बहुरूपतिवार रात अमेरिखी प्राप्त नैडीसेवो ने पत्रकार इवान गेरशवोविच और अल्प कुशीया तथा पूरी नशीन पील व्हेलन का उनके परिवारो से स्वागत किया। अमेरिख के राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी इस पर खुशी जताई। वहीं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मास्को के वातुक्वो हवाई अड्डे पर वापस आए प्रत्यक्ष रूसी नागरिकको गले लगाया। "दोे वाले आठ लोगो ने वापिन क्शीकोव भी शामिल था, जो एक रूसी हत्याार था और 2019 ने बर्लिन केएक पार्क में एक पूर्व चेचन लड़ाके की हत्या के लिए नर्तनी ने आजीवन कारावास की सजा कस रस था। जर्मन न्यायाधीशो ने कस था कि हत्या रूसी अधिकारिओ के आदेश पर की गई थी।" रूस के राष्ट्रपति क्वासलय फ्रेनज़लिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने शुक्रवार को संवाददाताओ को बताया कि क्शीकोव सशरी सुरक्षा सेवा (एफएसबी) का अधिकारी है और परियमी देशो को भी यह तथ्य बताया गया। उन्होंने यह भी कस कि क्शीकोव ने एक बार पुतिन के कुछ अंगरक्षको के साथ एफएसबी की विशेष अल्ल इजमें ने वजन किया था।

मध्यरात्रि में स्वदेश पहुंचे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने के कारण शीतयुद्ध के बाद

वाशिंगटन और माँस्को के बीच संबंध

सबसे निचले स्तर पर आ गए थे,

लेकिन इसके बावजूद बंदियों की

अदला-बदली के लिए गुप्त बैठकें

अमेरिका में मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में दो भारतीय गिरफ्तार

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिका में मादक पदार्थ की तस्करी करने के आरोप में दो भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से एक करोड़ अमेरिकी डॉलर का नशीला पदार्थ भी बरामद हुआ है। न्याय विभाग ने यह जानकारी दी। न्याय विभाग ने बताया कि आरोपियों की पहचान 28 वर्षीय सिमरनजीत सिंह और 19 वर्षीय गुस्मिरत सिंह के रूप में हुई है और वे कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो के निवासी थे। उसने बताया कि भारतीय नागरिकों पर मादक पदार्थ की तस्करी करने का आरोप है। आरोपियों को 29 जुलाई को बोस्टन की एक अदालत में पेश किया गया था, जहां से उन्हें हिरासत में भेज दिया था। स्थानीय पुलिस ने एक ट्रैक्टर से 400 किलोग्राम से अधिक की कोकीन बरामद करने के बाद दोनों भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया था। कोकीन की कीमत लगभग 1.05 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका में मादक पदार्थ की तस्करी का दोषी पाए जाने पर अधिकतम 20 साल और कम से कम तीन साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही दस लाख अमेरिकी डॉलर तक के जुर्माने का प्रावधान है।

एआई के युग में दर्शनशास्त्र महत्वपूर्ण है

लंदन। नई वैज्ञानिक समझ और इंजीनियरिंग तकनीकें हमेशा प्रभावित और भयभीत करती रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आगे भी ऐसा होता रहेगा। ओपनएआई ने हाल ही में घोषणा की है कि उसे इस दशक में मानवीय क्षमताओं को पार करने वाला एआई 'सुपरइंटेलिजेंस' बन जाने का अनुमान है। यह तदनुसार एक नई टीम का निर्माण कर रहा है, और अपने क्यूंटिंग संसाधनों का 20x यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित कर रहा है कि ऐसे एआई सिस्टम का व्यवहार मानवीय मूल्यों के साथ संरेखित होगा। ऐसा लगता है कि वे नहीं चाहते कि दुष्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवता पर युद्ध छेड़े, जैसा कि जेम्स कैमरून की 1984 की विज्ञान कथा थ्रिलर, द टर्मिनेटर (बदकिस्मती से,



ऑनॉल्ड श्वार्ज़नेगर की टर्मिनेटर में 2029 से समय में वापस भेजा गया है) में हुआ था। ओपनएआई समस्या से निपटने में मदद के लिए शीर्ष मशीन-लर्निंग शोधकर्ताओं और इंजीनियरों को बुला रहा है।लेकिन क्या दार्शनिकों के पास योगदान करने के लिए कुछ हो सकता है? अधिक सामान्यतः, अब उभर रहे नए तकनीकी रूप से उन्नत युग में इस सदियों पुराने विषय से क्या उम्मीद

की जा सकती है?इसका उत्तर देने के लिए, इस बात पर जोर देना जरूरी है कि दर्शन अपनी शुरुआत से ही एआई से सहायक रहा है। पहली एआई सफलता की कहानियों में से एक 1956 का कंप्यूटर प्रोग्राम था, जिसे लॉजिक थियोरिस्ट कहा जाता था, जिसे एलन नेवेल और हर्बर्ट साइमन ने बनाया था। इसका काम प्रिंसिपिया मैथमेटिका के प्रस्तावों का उपयोग करके प्रमेयों को सिद्ध करना था, जो 1910 में दार्शनिक अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड और बर्ट्रेड रसेल द्वारा तीन खंडों में लिखा गया काम था, जिसका लक्ष्य सभी गणित को एक तार्किक आधार पर फिर से बनाना था।वास्तव में, एआई में तर्क पर शुरुआती फोकस गणितज्ञों और दार्शनिकों द्वारा अपनाई गई मूलभूत बहसों के कारण था।

मेटा ने इतिहास का सबसे बड़ा ओपन एआई मॉडल लॉन्च

इसका व्यापकहित में होना जरूर

सिडनी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को दुनिया में एक लड़ाई चल रही है। एक तरफ ऐसी कंपनियाँ हैं जो अपने उन्नत सॉफ्टवेयर के पीछे डेटासेट और एल्गोरिदम को निजी और गोपनीय रखने में विश्वास करती हैं। दूसरी ओर ऐसी कंपनियाँ हैं जो जनता को यह देखने की अनुमति देने में विश्वास करती हैं कि उनके परिष्कृत एआई मॉडल के के पीछे आखिर क्या है।इसे खुले और बंद स्रोत एआई के बीच की लड़ाई के रूप में देखा जा सकता है।हाल के सप्ताहों में, फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने बड़े एआई मॉडल का एक नया संग्रह जारी करके ओपन-सोर्स एआई के लिए बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ी। इनमें

लामा 3.1 405बी नाम का एक मॉडल शामिल है, जिसके बारे में मेटा के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी, मार्क जुकरबर्ग कहते हैं, "पहला फ्रंटियर-स्तरीय ओपन सोर्स एआई मॉडल है।ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए जो ऐसे भविष्य की परवाह करता है जिसमें हर कोई एआई के लाभों तक पहुंच सके, यह अच्छी खबर है।क्लोउड-सोर्स एआई का खतरा - और ओपन-सोर्स एआई का वादाक्लोउड-सोर्स एआई उन मॉडलों, डेटासेट और एल्गोरिदम को संदर्भित करता है जो स्वामित्व वाले होते हैं और गोपनीय रखे जाते हैं। उदाहरणों में चैटजीपीटी, गुगल का जेमिनी और एंथ्रोपिक का क्लाउड शामिल हैं।हालाँकि कोई भी इन उत्पादों का उपयोग कर सकता है, लेकिन यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि एआई मॉडल या टूल बनाने के लिए

आई एनर्जी में नवाचार का प्रयोग जारी

ऊर्जा लेइएण के समाधानों में नवाचार में अग्रणी लिटावॉज को अपने नवीतम अभियान बनेो किसी की एनर्जी को लॉन्च करते हुए गर्व हो रहा है जिसमें प्रतिष्ठित अभिनेता अशय कुमार को भी दर्शाया गया है। ब्रांड ने हाल ही में अपना शानदार उत्पाद, डिजन एक्टीएक्स 1100आई इनवर्टेड लॉन्च किया है जो पावर कट प्रोडिशनए चार्जिंग इंडिरेक्टर के साथ डिजिटल स्क्रैन डिस्प्ले,इंजिन लोड, बैकअप टाइम अदि जैसी उन्नत और स्मार्ट सुविधाओं के साथ आता है और इसे एक अत्याधुनिक उत्पाद बनाता है। दिल को छूने वाली यह लाइविंग परिवार के स्तंभ कर्ताथि होने के साथ आने वाली निम्नोदारी की अद्भुत भावना को उजागर करती है और बताती है कि कैसे लिटावॉज के स्मार्ट एआई चार्जिंग इनवर्टेड लोगों को अपने प्रियजनों की सहायता करने और उनका उत्थान करने में सक्षम बनाते है। यह उत्पाद अपनी अपन डिजन अग्ने तरीके से पत्थाने में सक्षमता करेगा। टीवीसी पर टिप्पणी करते हुए लिटावॉज एनर्जी टेकनोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के एनडी और सीईओ गुरजीत भाटिया ने कहा कि हम अपने उपभोक्ताओं को समझते है और अपने प्रियजनोंकी प्रगति में उनकी मुश्किल को स्वीकार करते है। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे उत्पाद उन्हें और उनके परिवार को ऊर्जा के बारे में अज्ञादी एक्षित करने में मदद करेए जिससे उनकी प्रगति को बढ़ावा मिलता है।

किस डेटासेट और स्रोत कोड का उपयोग किया गया है।हालाँकि यह कंपनियों के लिए अपनी बौद्धिक संपदा और अपने मुनाफे की रक्षा

करने का एक शानदार तरीका है, लेकिन इससे सार्वजनिक विश्वास और जवाबदेही को कम करने का जोखिम है। एआई प्रौद्योगिकी को बंद-स्रोत

बढ़ते तनाव के बीच इजराइल में रह रहे भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह

भाषा। तेल अवीव

भारतीय दूतावास ने यहां शुक्रवार को इजराइल में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी कि वे सतर्क रहने के साथ स्थानीय प्रशासन की ओर से सुझाए गए सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें। इजराइल के हमले में एक के बाद एक दो हमास नेताओं और हिजबुल्ला के एक कमांडर के मारे जाने के बाद पश्चिम एशिया में नए सिरे से बढ़े तनाव के मद्देनजर भारतीय दूतावास ने यह परामर्श जारी किया। पिछले महीने हमास नेता इस्माइल हनिएह की ईमन में हत्या कर दी गई जबकि हमास की सैन्य शाखा के प्रमुख मोहम्मद जैफ गाजा में मारा गया। लेबनान में सक्रिय हिजबुल्ला का कमांडर फौद शुक्ूर बेरूत पर किए

ए गए हवाई हमले में मारा गया। इजराइल को कई देशों और समूहों द्वारा गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है और हनिएह की मौत से इलाके में तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंचने की आशंका है। भारतीय दूतावास ने यहां जारी एक परामर्श में कहा, कृपया सावधानी बरतें, देश के भीतर आवश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षा आश्रयों के करीब रहें। दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इजराइली अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में है। दूतावास के सभी सोशल मीडिया मंच पर पोस्ट करके अंग्रेजी, हिंदी, तेलगु और कन्नड़ में जारी किए गए परामर्श में इमेल पते के साथ टेलीफोन नंबर

972-547520711 और 972-543278392 जैसे संपर्क विवरण भी दिए गए हैं जिस पर 24 घंटे मदद उपलब्ध रहेगी। एयर इंडिया ने बृहस्पतिवार को अपनी दिल्ली-तेल अवीव उड़ानें मराने का फैसला कर दिया है। इजराइली अधिकारियों के इस दावे के बावजूद कि उसका हवाई क्षेत्र बिस्कुल सुरक्षित है, लगभग 10 अंतरराष्ट्रीय विमानन कंपनियों ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। इजराइल में भारतीय मिशन की ओर से जारी परामर्श में पहले बेरूत स्थित भारतीय दूतावास ने बृहस्पतिवार को परामर्श जारी करके भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक लेबनान की यात्रा नहीं करने की सलाह दी थी, इसके अलावा उन्हें लेबनान छोड़ने की भी सलाह दी गई है।

विक न्यूज़

अपनी पहली विदेश यात्रा पर थाईलैंड जा सकते हैं नेपाल केनए प्रधानमंत्री ओली
कठमांडू। नेपाल के नव-निर्वाचित प्रधानमंत्री केपी. शर्मा ओली अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए संभवतः थाईलैंड जा सकते है, जिससे पहले किसी पड़ोसी देश की यात्रा करने की पधर चर्चा जान्ती। पूर्व में, नेपाल के प्रधानमंत्रियों ने अधिकतर पहले भारत वा दौर किया था, हालांकि कुछ ने चीन की भी यात्रा की थी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री ओली सितंबर के पहले सप्ताह में बिसप्टेक (बहू-क्षेत्रीय तन्त्रीय) और आर्थिकसदस्यों के लिए बंगाल की खाड़ी (पहल) शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष होने के लिए थाईलैंड की यात्रा पर जावेंगे। ओली के एकसहयोगी ने बताया कि प्रधानमंत्री बिस्मक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए अपनी पहली विदेश यात्रा केतहत सितंबर केपहले सप्ताह में थाईलैंड जावेंगे, हालांकि यात्रा केतिथिया को अभी अंतिम रूप दिया जना है। बंगलादेश, भूटान, भारत, क्यामार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड सहित बिस्मकेक सदस्य देश के नेता शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए सितंबर के पहले सप्ताह में बैकेंक में मिल रहे है।प्रधानमंत्री ओली संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए सितंबर केतीसरे सप्ताह में अमेरिख की यात्रा करवेंगे। प्रधानमंत्री के एकसहयोगी ने कस, अभी तक ह्मे भारत यात्रा के लिए कोई आधिकारिकनिर्णय नही मिला है।

नेपाल: नवनियुक्त प्रधानमंत्री ओली ने तीन लोगों को राज्य मंत्री बनाया

कठमांडू। नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने शुक्रवार को अपनी मंत्रिपरिषद का विस्तार करते हुए तीन लोगों को राज्य मंत्री बनाया। नेपाल के राष्ट्रपति रामप्रद पांडेय ने प्रधानमंत्री ओली की सिफारिश पर अपना रुकावट नहीं दिया, स्या बीके और पूर्व बहुरद तामांग को राज्य मंत्री नियुक्त किया। राष्ट्रपति कार्यालय द्वाय जारी एक नोटिस के अनुसार, चौधरी को पर्यटन, संस्कृति और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री, स्या बीके को वन और पर्यावरण राज्य मंत्री और तामांग को ऊर्ा एव सिवाय राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है। स्या बीके और तामांग नेपाली कांग्रेस से है जबकि चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी का प्रतिनिधित्व करते है। प्रधानमंत्री ओली की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित 25 सदस्य है। पिछले महीने सीपीएन-यूएमएल के अध्यक्ष 72 वषीय ओली चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त चिच गए थे, जिन्होंने पुष्य क्जाल दाहाल प्रव्रं का स्थान लिया।

उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान में न्यायाधीशों के कफिले पर हमला, दो पुलिसकर्मी मारे गए

पेशावर। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में शिया अशात प्राप्त खैबर परखूनख्या ने आतक्वादियों ने शुक्रवार को ड्यूटी करके घर लौट रहे न्यायाधीशों के एक कफिले पर घात लगाकर हत्या कर दिया जिससे उनकी सुरक्षा में तैनात दो पुलिसकर्मीयों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। सभी तीन न्यायाधीश सुरक्षित है। एक पुलिस अधिकारी ने कस, आतक्वादियों की ओर से घात लगाकर किए गए सशस्त्र हमले ने न्यायाधीशों की रक्षा करने समय ड्यूटी के दौरान दो पुलिसकर्मी मारे गए, जबकि दो अन्य घायल हो गए। खैबर परखूनख्या प्रांत केडैर इस्माइल खान ने टैक जितने की अदालतों ने ड्यूटी केबाद न्यायाधीशों का वाफिया जमा उनकेघरों की ओर जा रहा था तो चड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसके बावजूद सशस्त्र आतक्वादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। टैकडीअशत खान मार्ग पर पुलिस और आतक्वादियों केबीच गोलीबारी जारी है। इस बीच प्रांत के मुख्यमंत्री अली उम्रीन गंडापुर ने न्यायाधीशों को वाहनो पर हमले की निराद करते हुए बल्लेबंदी तल्ल की है। गंडापुर ने दो पुलिसकर्मीयों की मौत पर संवेदन्य व्यक्त करते हुए न्यायाधीशों के लिए सुरक्षा घेरा मजबूत करने का भी आह्वान किया। नेशनल असेबली ने परस्तुत गृह मंत्रालय की एकरिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान में वर्ष 2023 में,1,514 आतक्वादी हमले हुए जिसने 2,922 लोग मारे गए।

पाकिस्तान : कुर्म जिले में हिंसक झड़पों में शामिल जनजातियों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए

पेशावर। पाकिस्तान के अशात उत्तर-पश्चिमी कुर्म जिले ने हिंसक झड़पों में शामिल जनजातियों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए है, जिसकेबाद हिंसा रूक गई है। एकवर्षिक अधिकरी ने यह जानकारी दी। लगभग एकघण्टासे जो भी हिंसक झड़पों में 50 लोगों की मौत हो गई और 225 से अधिक लोग घायल हुए है। अधिकरियों ने बताया किबृहस्पतिवार को जिन्ना (स्थानीय पंचायत) नेताओं के हस्तक्षेप के बाद शांति समझौता किया गया। उम्पुयत जादेर उल्लेख महसूस में कस कि शांति समझौते के बाद अफ़गानिस्तान की सीमा से लगे खैबर परखूनख्या प्रांत के कुर्म जिले में झड़पे बंद हो गईं है। अधिकरियों ने बताया कि शांति समझौता कुर्म जिले में संघर्षत शिया और सुन्नी मुत्ते केबीच दो अलग-अलग अशौचित जिन्ना बैठको में हुआ। दोनों पक्षों केपुसख लोगो ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत दोनों जनजातियां सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में सहकार के साथ सहयोग करने पर सहमत हुईं। समझौते के अनुसार, शांति समझौते का उल्लंघन करने वाले किसी भी पक्ष को 12 व्साइ टाक तक व जुर्माना देना होगा।

अमेरिका-रूस कैदी अदला-बदली : पत्रकारों के मू-राजनीतिक सौदेबाजी में इस्तेमाल का जोखिम

सिडनी। एक अमेरिखी सैनिक ने कैदियों की वापसी की तस्वीर, जिन्होंने चेस्से पर लंबी मुक्कुहट है, सब कुछ कहती है। सुग्री, रवत और एक अविश्वसनीयता से जटिल तस्वीरों की सफ़ाफाल। वॉल स्ट्रीट जर्नल केरिपोटर् इवान गेरशवोविच, रेंडिओ पी यूरोप केपत्रकार अल्प कुशीया, पूर्व अमेरिखी नशीन पील व्हेलन और कई अन्य लोगो ने रिसई शीत युद्ध की समाप्ति केबाद सबसे बड़ी कैदी अदला-बदली है छ्ठू मिलाकर, सात अलग-अलग देशो के 26 लोगो को एक बेहद जटिल समझौते के तहत रिहा किया गया, जिस पर बातचीत करने में कई साल लगे गए। उनमें रूस में कैद 16 लोग शामिल थे: तीन अमेरिखी, कई रूसी राजनीतिक कैदी, और एक 19 वषीय रूसी-जर्मन नागरिक जो रूसी सैन्य अड्डे की तस्वीर लेने के कारण जेल में बंद था।बदले में, आठ रूसियों को भी रिहा कर दिया गया - उनमें से सबसे कुख्यात, वादिन क्रासिवोव, सशरी सुरक्षा सेवा में एक कर्नल था, जिसे 2019 ने बर्लिन में एकपूर्व चेचन विद्रोही की हत्या करने पर जर्मनी ने जेल में डाल दिया गया था।अन्यव्यापूरां तरीकेसे कैद किए गए लोगो के लिए स्वांत्रता निर्दिष्टए रूस से आदेशत खबर है, मले ही इसमें बहुत देर हो चुकी है, और बाइडेन प्रशासन सीटै पर बातचीत के दौधन की गई मेहनत के लिए श्रेय का स्कार है।

पोरैसिक विशेषज्ञ बताते हैं शव परीक्षण में क्या होता है

सिडनी। कमी-कमी यह रास्ट नहीं होता कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कैसे और क्यों हुई। मृत्यु के बाद शरीर की विस्तृत जांच, जिसे शव परीक्षण या पोस्टमॉर्टल के रूप में जाना जाता है, इस प्रश्न का उत्तर खोजने में मदद कर सकती है। आपने टीवी द्रष्टांन शो में जो देखा होगा, उसके बावजूद अधिकांश शव-परीक्षाएं ज्यादा खट-खट किए बिना होती हैअ अधिकतर अलोक्य कप्रिया के दौरान शरीर पर: अग्रण्य रहता है।हालाँकि, कमी-कमी अधिक विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है।शव परीक्षण में शामिल सभी लोगो द्वारा इस प्रक्रिया के प्रत्यक्ष चरण में मृतक की पहिना और सम्मान को प्राथमिकता दी जाती है।हामी शवो का परीक्षण नहीं होता-वह विच्छी की मृत्यु प्राकृतिक कारणो से होती है, संदिग्ध परिस्थितियों को कोई सबूत नहीं है या कोई हलिया थिक्किना इतिहास है, तो मृत्यु को उडिटेड द्वारा प्रमाणित किया जाता है। फिर व्यक्ति को अंतिम संस्कार सेवा तक ले जाया जाता है।लेकिन जब मौत के बारे में सवाल बने रहते हैं, तो विशेषज्ञ डॉक्टर, क्लॉनीशियन और सल्यक कर्नलपरी आगे की जांच कर सकते हैं। कमी-कमी इसमें शव-परीक्षा शामिल होती है।

